राष्ट्रीय संस्करण

संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' पर पुनर्विचार से इन्कार ››3

वर्ष 9 अंक 44

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 14

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक एफटीए

प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर की मौजूदगी में लंदन में विजन डाक्यूमेंट-2035 पर भी लगी मुहर

मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौता साझा समृद्धि की योजना

जयप्रकाश रंजन • जागरण

- ब्रिटिश पीएम ने इसे यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का सबसे अहम कारोबारी समझौता बताया
- समझौते से दोनों देशों में कारोबार करना आसान होगा, इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे
- दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने वाले रोडमैप को भी मंजूरी दी गई

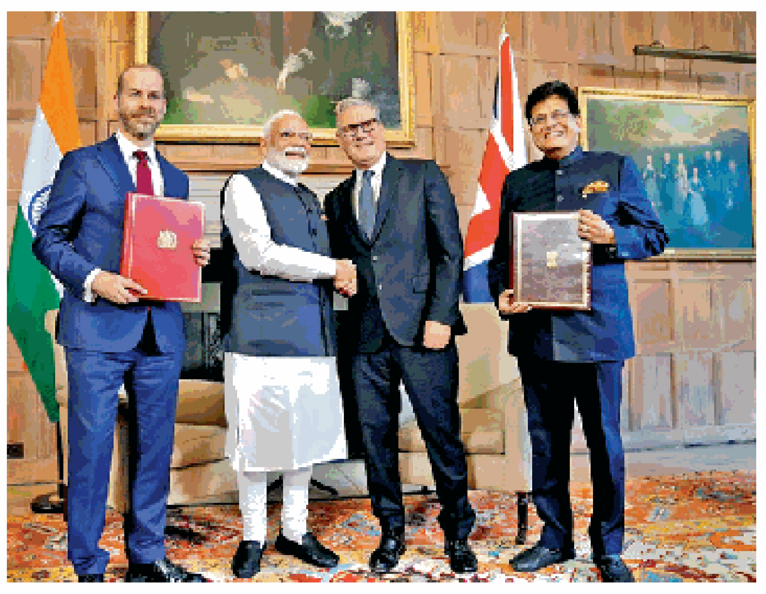

इंग्लैंड के चेकर्स में गुरुवार को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान अपने ब्रिटिश समकक्ष किएर स्टार्मर से हाथ मिलाते प्रधानमंत्र नरेन्द्र मोदी। इस अवसर पर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनोल्ड भी उपस्थित रहे। एपी

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद आक्रामक शुल्क नीति से फैली वैश्विक अस्थिरता के बीच वैश्विक उद्योग जगत में भरोसा जगाते हुए भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। लंदन में पीएम नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर की मौजूदगी में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनोल्ड ने समग्र आर्थिक व कारोबारी समझौते (सीटा) पर हस्ताक्षर किए। इसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऐतिहासिक करार दिया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत व ब्रिटेन के द्विपक्षीय रिश्तों के अगले 10 वर्षों की दिशा तय करने वाले विजन डाक्यूमेंट-2035 को भी मंजूरी दी। इसमें रक्षा व सुरक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने वाले रोडमैप को भी मंजूरी दी गई है।

पीएम मोदी दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार देर रात लंदन पहुंचे। गुरुवार को स्टार्मर के साथ बैठक के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने सीटा के बारे में कहा- यह समझौता केवल आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक ओर भारत के कपड़ा, जूते, रत्न व आभूषण, समुद्री खाद्य, इंजीनियरिंग उत्पादों को ब्रिटेन में बड़ा बाजार मिलेगा। भारत के कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी ब्रिटेन में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों, और मझोले व छोटे उद्यमों को विशेष तौर पर लाभ होगा। दूसरी ओर, भारत के लोगों व उद्योग के लिए ब्रिटेन के उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों व उड्डयन क्षेत्र के कल-पुर्जों की उपलब्धता सुलभ व किफायती होगी। इससे कारोबार करना आसान होगा। ब्रिटेन को भारत के सक्षम कार्यकुशल श्रमिक उपलब्ध होंगे। दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस दौरान पीएम स्टार्मर ने इस समझौते को ब्रिटिश जनता और कारोबारियों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने इसे यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी समझौता करार दिया। उन्होंने कहा- इससे द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि होगी। ब्रिटिश उपभोक्ताओं को सस्ते कपड़े, जूते और खाद्य उत्पाद मिलेंगे। यह ब्रिटेन में हजारों नौकरियां पैदा करेगा और कामकाजी लोगों की जेब में अधिक पैसा डालेगा।

मोदी बोले- 'हम सीधे बल्ले से खेलते हैं' : पीएम मोदी ने स्टार्मर से बातचीत के दौरान भारत-ब्रिटेन साझेदारी का क्रिकेट की शब्दावली में वर्णन किया। कहा- हम एक हाई स्कोरिंग मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम दोनों के लिए, क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, बल्कि एक जुनून है। कभी-कभी स्विंग और मिस हो सकता है, लेकिन हम हमेशा सीधे बैट से खेलते हैं। (पेज-3भी देखें)

भारत में ब्रिटेन की ये चीजें होंगी सस्ती

कार, शराब, मेडिकल उपकरण, अंतरिक्ष यान से जुड़े पार्ट्स, चाकलेट और सौंदर्य प्रसाधन के समान।

ब्रिटेन में सस्ती होने वाली भारत की वस्तुएं

टेक्सटाइल, लेदर व फुटवियर आइटम, इलेक्ट्रानिक्स, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स गुड्स, खिलौने, दवा, केमिकल्स, भारत के कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पाद।

अनुवादक से बोले मोदी- 'कोई समस्या नहीं, आप बीच-बीच में अंग्रेजी बोल सकती हैं'

ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर जब बोल रहे थे तो अनुवादक को उनके वक्तव्य का हिंदी अनुवाद करने में कठिनाई हो रही थी। एक जगह वह ठिठक भी गईं और उन्हें कुछ बोलने को सूझ नहीं रहा था तो उन्होंने कहा- 'माफ कीजिए...' इस पर मोदी उनकी परेशानी भांप गए और उनसे बड़ी शालीनता से बोले-'आप परेशान मत होइए, हम बीच-बीच में अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं...चिंता मत कीजिए।' इस पर अनुवादक पीएम का धन्यवाद करती हैं। इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि मोदी और हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। इस पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े।

मोदी ने खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों और भगोड़ों के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाया पेज>>10

क्या अयोग्य लोगों को मतदान करने की अनुमति देता है संविधान : सीईसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध पर आयोग ने राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं से किए सवाल
- कहा, मृत और स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों को मतदाता सूची में नहीं दी जा सकती है जगह

सीईसी ज्ञानेश कुमार। फाइल

बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर आरोपों से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने अपना बचाव करते हुए पूछा है कि क्या चुनाव आयोग किसी के प्रभाव में आकर संविधान के विरुद्ध मृत, स्थायी रूप से पलायन कर चुके, दो जगहों पर पंजीकृत और विदेशी मतदाताओं को मतदाता सूची में जगह दे सकता है। देश के आम मतदाताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या पहले बिहार में और बाद में पूरे देश में अयोग्य लोगों को मतदान करने की अनुमति संविधान देता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुरुवार को यह टिप्पणी तब की है, जब बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों की ओर से संसद में विरोध किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि आयोग के इस कदम से करोड़ों पात्र लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। इस विवाद के बीच ज्ञानेश कुमार ने सवाल किया कि 'क्या चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही एक शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव की राह में नींव का पत्थर नहीं है?'

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इन यक्ष प्रश्नों पर तो कभी न कभी हम सबको और भारत के सभी नागरिकों को मिलकर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर गहन चिंतन करना ही होगा। गौरतलब है कि बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने अब तक 21 लाख से अधिक मृत मतदाता, 31 लाख से अधिक स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाता और सात लाख मतदाताओं के दो जगहों से पंजीकृत होने का दावा किया है।

राहुल की टिप्पणियों पर आयोग का पलटवार, कहा-आरोप आधारहीन पेज>>4

जागरण विशेष

एक रुपये स्वच्छता अभियान से बदल रही गांवों की सूरत

लखनऊ : स्वच्छता के मामले में शहरों के साथ गांव भी पीछे नहीं हैं और सरकारी प्रयास के साथ लोग जुड़ रहे हैं। प्रति दिन एक रुपये स्वच्छता अभियान ने 100 ग्राम पंचायतों की सूरत बदल दी है। • पेज-7

संपादकीय

सभी हितों को साधने वाला व्यापार समझौता: ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से एक प्रमुख बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होने के साथ ही सेवा प्रदाताओं एवं किसानों के हितों की भी रक्षा होगी। **पीयूष गोयल** का आलेख।

पड़ोसियों को पटरी पर लाता भारत: भारत ने शांत, संयमित और संवेदनशील रवैये से काम लिया और तभी मालदीव में स्थिति बदल पाई है। **श्रीराम चौलिया** का दृष्टिकोण। • पेज 8

विमर्श

मतांतरण के निशाने पर हिंदू : उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में मतांतरण की घटनाएं सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट बढ़ा रही हैं। **डा. अनुराग सिंह** का विश्लेषण।

शोध को मिलती महत्ता : चार वर्षीय स्नातक पद्धति उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। **पीयूष कुमार दुबे** का आलेख। • पेज-9

मुंबई ट्रेन धमाकों पर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दोषियों की रिहाई पर नहीं होगा असर, लेकिन बांबे हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा नजीर
- महाराष्ट्र सरकार की अपील पर शीर्ष कोर्ट ने बरी किए गए लोगों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले से 12 लोगों को बरी करने के बांबे हाई कोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने साफ किया कि इसका असर जेल से रिहा हो चुके लोगों की रिहाई पर नहीं होगा यानी उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि बांबे हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल अन्य मामलों में नजीर नहीं माना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की अपील पर शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा बरी किए गए लोगों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब है।

ये आदेश जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद जारी किए। इससे पहले जब मेहता ने शीर्ष कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की तो पीठ ने कहा कि उन्हें पता चला है कि मामले में बरी किए गए सभी लोग जेल से रिहा हो चुके हैं। अब उनको वापस जेल नहीं भेजा जा सकता। इस पर मेहता ने कहा कि वह यह मांग नहीं कर रहे कि रिहा हो चुके लोगों को दोबारा जेल भेजा जाए, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसले में बहुत-सी टिप्पणियां की हैं। मकोका के बारे में भी कहा है जिसका अन्य लंबित मामलों पर असर हो सकता है। ऐसे में कानूनी पहलू को देखते हुए आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। उनकी दलीलों पर पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले पर इस हद तक रोक जारी कर रहे हैं कि वह फैसला नजीर नहीं माना जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने अपील में हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसने विशेष अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों को बरी करने में बहुत ही तकनीकी आधार लिए हैं। जैसे हाई कोर्ट ने कहा है कि उनमें से एक से आरडीएक्स की बरामदगी को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसमें हाई कोर्ट ने बहुत ही तकनीकी आधार लिया है कि जब्त विस्फोटक को लाख से सील नहीं किया गया था।

बांबे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई, 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा और यह विश्वास करना कठिन है कि इन लोगों ने अपराध किया है। जबकि इस मामले में विशेष अदालत ने 12 में से पांच को मौत की सजा सुनाई थी और सात को आजीवन कारावास दिया था। मौत की सजा पाए एक व्यक्ति की 2021 में मृत्यु हो गई थी। पश्चिमी लाइन पर विभिन्न स्थानों में लोकल ट्रेनों में हुए सात विस्फोटों में कुल 187 लोग मारे गए थे। बांबे हाई कोर्ट ने मामले की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले पर व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने आनन-फानन सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की और जल्द सुनवाई पर भी लगाने का अनुरोध किया। इसके बाद गुरुवार को मामला सुनवाई पर लगा था।

हर तहसील में बनेंगे पांच माडल सहकारी गांव

नई दिल्ली : देश को 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति मिली है, जिसका अनावरण गुरुवार को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक तहसील में पांच-पांच माडल सहकारी गांवों की स्थापना है। ये गांव राज्य सहकारी बैंकों की सहायता से विकसित किए जाएंगे और इनमें महिलाओं की विशेष भागीदारी होगी। (पेज-3)

छग में 2.54 करोड़ के इनामी 66 माओवादियों का समर्पण

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में गुरुवार को 2.54 करोड़ के इनामी 66 माओवादियों ने समर्पण किया। इनमें 25 लाख का इनामी माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर (एसजेडसीएम) रामन्ना ईरपा उर्फ जगदीश भी शामिल है, जो ओडिशा के सब जोनल ब्यूरो का प्रमुख था। (पेज-6)

तीन हजार करोड़ की बैंक ऋण धोखाधड़ी में अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी के छापे

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- कंपनी ने दिया स्पष्टीकरण-आठ वर्ष पुराने लेनदेन से संबंधित मालूम होती है कार्रवाई
- ऋण ब्याज सहित पूरी तरह चुका दिए गए हैं, जिससे बकाया राशि अब शून्य हो गई है

मुंबई में गुरुवार को अनिल अंबानी के कार्यालय के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड। आइएएनएस

ईडी ने गुरुवार को अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित तौर पर तीन हजार करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी उनकी रिलायंस समूह की कंपनियों एवं यस wबैंक से जुड़े बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में की गई है। एजेंसी इन कंपनियों द्वारा लिए गए कुछ और बैंक ऋणों के अलावा अघोषित विदेशी संपत्तियों की भी जांच कर रही है। मुंबई में 50 कंपनियों और 25 लोगों के 35 से ज्यादा ठिकानों की तलाशी ली गई। समूह की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है कि जिन रिपोर्टों को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई है, वह रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े आठ वर्ष से ज्यादा पुराने लेनदेन से संबंधित प्रतीत होती है।

ईडी ने जिन शिकायतों के आधार पर छापेमारी की हैं, वे कंपनियों द्वारा लोन के दुरुपयोग और सार्वजनिक संस्थाओं से धोखाधड़ी से संबंधित हैं। ईडी को जानकारी नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, बैंक आफ बड़ौदा आदि से प्राप्त हुई थी। कहा जा रहा है कि 2017-19 के बीच यस बैंक से करीब तीन हजार करोड़ रुपये के ऋण की कथित हेराफेरी हुई थी।

कई मामलों में औपचारिक मंजूरी से पहले ही कर दिया गया ऋण वितरित पेज>>10

वाराणसी में 41 वर्षों बाद एक ही परिसर में गूंजेंगे शबद-कीर्तन और हनुमान चालीसा

जागरण संवाददाता, वाराणसी

- काशी में गुरु तेग बहादुर चरण स्पर्श गुरुद्वारा और श्री बड़े हनुमान मंदिर के बीच विवाद खत्म
- समझौता कराने में आगे आई बाबू जगत सिंह रायल फैमिली, मुख्यमंत्री योगी की भी रही भूमिका

गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष (बाएं) सरदार करन सिंह सभरवाल, श्री बड़े हनुमान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एसएन पांडेय का हाथ मिलवाते बाबू प्रदीप नारायण सिंह (बीच में)। सौ. गुरुद्वारा कमेटी »

जगतगंज में करीब 200 साल पुराने गुरु तेग बहादुर चरण स्पर्श गुरुद्वारा और श्री बड़े हनुमान मंदिर का विवाद 41 वर्षों बाद सुलझ गया है। अब एक ही परिसर में शबद-कीर्तन और हनुमान चालीसा गूंजेंगे। बीते सोमवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री बड़े हनुमान मंदिर प्रबंध समिति ने आपसी समझौते से ताले खोले और जमीन को बराबर बांटा। जगत सिंह रायल फैमिली के वंशज बाबू प्रदीप नारायण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मध्यस्थता से यह सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ। बाबू प्रदीप नारायण सिंह के पूर्वजों ने मंदिर और गुरुद्वारे के लिए यह जमीन दान की थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष श्याम नारायण पांडेय ने समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जल्द गुरुद्वारा और मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू होगा।

गुरुद्वारा कमेटी के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह अहलूवालिया ने बताया कि सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर सिंह जी अपने जीवनकाल में काशी आए थे तो उन्होंने यहां छह माह, 12 दिन प्रवास किया था। उस अवधि में वह गुरुद्वारा वाले स्थान पर साधना करते थे। इसलिए यह स्थान गुरु चरण स्पर्श का स्थल है। लगभग 200 साल पूर्व यहां गुरुद्वारा का निर्माण हुआ।

अराजकतत्व खेलने-कूदने के बहाने करने लगे थे जमीन पर कब्जा पेज>>6

शिव मंदिर को लेकर भिड़े थाईलैंड-कंबोडिया, 12 मरे

बैंकाक : सीमा पर स्थित 1100 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर बढ़े विवाद में गुरुवार को थाईलैंड व कंबोडिया भिड़ गए। इस दौरान थाईलैंड ने एफ-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडियाई इलाके में बमबारी की और कंबोडियाई सेना ने तोप से गोले दागे। संघर्ष में एक सैनिक समेत 12 लोगों के मारे जाने की सूचना है। तनाव के बीच थाईलैंड ने कंबोडिया से लगी सीमा पर छह एफ-16 विमान तैनात किए हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया है। (पेज-11)

दैनिक जागरण सप्तरंग

मनोरंजन की दुनिया का

क्लासिक फिल्मों के क्लाइमेक्स में एआइ का तड़का

शाहरुख खान पर केस करूंगी : बरखा सिंह

• पेज-13

न्याय

32 लाख की एफडी हड़पने के लिए गोद लिए बेटे ने मां की हत्या कर बाथरूम में दफना दिया था शव, अदालत ने अपने फैसले में श्रीरामचरितमानस, श्री गुरुग्रंथ साहिब, कुरान व बाइबिल का दिया उद्धरण

धर्मग्रंथों का उद्धरण देकर हत्यारे बेटे को सुनाया मृत्युदंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर

मां की हत्या करने वाला अपराधी दीपक पचौरी। नईदुनिया

मध्य प्रदेश में श्योपुर की जिला अदालत ने 32 लाख रुपये की एफडी हड़पने के लिए मां की हत्या कर शव बाथरूम में दफनाने वाले 27 वर्षीय दत्तक पुत्र को फांसी की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने सजा सुनाते हुए श्रीरामचरितमानस सहित चार प्रमुख धर्मग्रंथों का उद्धरण देकर मां का महत्व भी बताया।

लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव के अनुसार वारदात आठ मई 2024 की है। श्योपुर स्थित रेलवे कालोनी निवासी दीपक पचौरी ने मां ऊषा देवी को सीढ़ियों से धक्का दिया, उन पर राड से वार किया और साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को उसने घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया और सीमेंट से गड्ढे को बंद भी कर दिया। इसके बाद वह कोतवाली थाना पहुंचा और मां के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पड़ताल में संदेह होने पर पुलिस ने दीपक से सख्ती से पूछताछ की तो हत्या की बात सामने आई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने ऊषा देवी का शव बाथरूम से गड्ढा खोदकर बरामद कर लिया।

दरअसल, ऊषा देवी और उनके पति भुवनेश पचौरी ने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए 2004 में ग्वालियर के अनाथ आश्रम से दीपक को गोद लिया था। तब वह लगभग छह साल का था। दोनों ने उसे पढ़ाया-लिखाया और परवरिश की, लेकिन 2021 में भुवनेश पचौरी की मौत होने के बाद दीपक बुरी संगत में पड़ गया और अपने नाम की गई 16 लाख की एफडी तोड़कर राशि गलत शौक व शेयर बाजार में खर्च कर दी। ऊषा देवी के नाम से बैंक में 32 लाख रुपये की एफडी थी, जिसमें दीपक ही नामिनी था। जांच में सामने आया कि इस रकम को हासिल करने के लिए ही उसने मां को मार डाला।

फैसले में इन धर्मग्रंथों का दिया गया संदर्भ

- श्रीरामचरितमानस में लिखा है, 'सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु-पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा।' यानी वही पुत्र सौभाग्यशाली है, जो माता-पिता के वचनों के प्रति अनुराग रख उन्हें प्रसन्न करता है। ऐसे पुत्र संसार में दुर्लभ हैं।
- श्री गुरुग्रंथ साहिब के अनुसार, माता-पिता की सेवा करही, अपना गति भिती जाणी। वीर बिना कुल कैसे चले, मात पिता को राखी करे।' यानी जो माता-पिता की सेवा करता है, वही कुल का रक्षक होता है और वही सच्चा वीर कहलाता है। जिस मां की गोद में व्यक्ति पला-बढ़ा, उसी को भूल जाना, अधर्म नहीं, घोर पाप है।
- कुरान में सूरा अल-इसरा, आयत 23 में लिखा है, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि माता-पिता से अच्छा व्यवहार करो, बुढ़ापे में पास हों तो 'उफ' तक न कहो और शिष्टाचार से बात करो।
- बाइबिल में लिखा है, माता-पिता का अपमान प्राणदंड योग्य अपराध है, जो व्यक्ति अपने माता या पिता को मारे या श्राप दे, वह निश्चय ही मृत्यु का भागी है।

रूस में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी 48 लोगों की मौत

- रूस-चीन सीमा पर सुदूर पूर्वी अमूर क्षेत्र में ब्लागोवेशचेंस्क से टिंडा जा रहा था विमान
- 50 वर्ष पुराना था अंगारा एयरलाइंस का यह विमान, 42 यात्री और छह क्रू मेंबर थे सवार

मास्को, रायटर : रूस के सुदूर पूर्व में गुरुवार को एक एंटोनोव एएन-24 यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पांच बच्चों समेत 42 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे। दुर्घटना में सभी लोग मारे गए हैं। सोवियत काल में निर्मित यह विमान लगभग 50 वर्ष पुराना था। दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। रूसी समाचार एजेंसी 'इंटरफैक्स' ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दुर्घटना के समय मौसम बेहद खराब था।

यह ट्विन टर्बोप्रोप विमान ब्लागोवेशचेंस्क शहर से टिंडा जा रहा था, जो चीन सीमा से लगे अमूर क्षेत्र का एक दूरस्थ कस्बा और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। विमान जब दूसरी बार लैंड करने की तैयारी कर रहा था, तब उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और रडार स्क्रीन से गायब हो गया। तलाशी अभियान के दौरान एक एमआइ-8 हेलीकाप्टर ने विमान के बिखरे हुए मलबे की खोज एक घने जंगल में की। आपात सेवा अधिकारियों ने बताया कि विमान का मलबा टिंडा से लगभग 15 किमी दूर एक पहाड़ी पर मिला। घटनास्थल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी और बचाव टीम को वहां रास्ता बनाने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग करना पड़ा।

विमान दुर्घटनाग्रस्त पर चीनी राष्ट्रपति ने पुतिन को भेजा शोक संदेश पेज>>11

****

14 दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को जर्मनी में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है। यह पहला मौका है जब दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्र सीधे अंतरराष्ट्रीय मंच पर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 25 जुलाई, 2025

आज का मौसम

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
25 जुलाई	36.0	25.0
26 जुलाई	34.0	25.0
नोएडा		
25 जुलाई	36.0	26.0
26 जुलाई	37.0	27.0
गुरुग्राम		
25 जुलाई	30.0	25.0
26 जुलाई	30.0	26.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

वाहन ने फुटपाथ पर सो रहे दो को कुचला, एक की मौत

नई दिल्ली : उत्तरी जिले में कश्मीरी गेट स्थित मोनेस्ट्री कैंप के पास तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने फुटपाथ पर सो रहे दो लोगों को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डाक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। अभी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मृतक व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है। (जासं)

बैंक अधिकारी बन की 10.64 लाख की धोखाधड़ी, दो धरे

नई दिल्ली : बैंक अधिकारी बनकर 10.64 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के दो साइबर ठगों को दक्षिण-पश्चिमी जिले की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान धनबाद निवासी शंकर दान और प्रदीप कुमार दान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से छह मोबाइल फोन, कालिंग डिवाइज व बिल डेस्क एप्लिकेशन चलाने में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस बरामद की हैं। (जासं)

संसद सुरक्षा सेंध में जमानत याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपित सागर शर्मा और मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि भारत में आतंक फैलाने का सबसे आसान तरीका संसद को बाधित करना है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद में घुसपैठ एक गंभीर मामला है। मनोरंजन की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि संसद के भीतर धुआं छोड़ना और नारेबाजी करना आतंकवादी कृत्य नहीं था। (जासं)

अब लोगों को नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, घर बैठे मिलेगा डाक्टर से समय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआइएमएस) की शुरुआत की है। इसके जरिये मरीज अस्पताल में ओपीडी, जांच के लिए समय ले सकेंगे। अस्पताल से जुड़े लैब, रेडियोलोजी, मेडिकल रिकार्ड, बिलिंग, एंबुलेंस, प्रशासनिक तो वह डिजिटल प्लेटफार्म पर जाकर अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। अब मरीज या उसका रिश्तेदार घर बैठे अपने लिए डाक्टर से अप्वाइंटमेंट ले पाएंगे। उसे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय ने इस सेवा की शुरुआत की। इसके साथ ही सीएम ने 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आठ जन औषधि केंद्रों का डिजिटल उद्घाटन कर दिल्लीवासियों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का तोहफा दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली की जनता का हेल्थ रिकार्ड बना रही है। लोग अपना कार्ड प्रस्तुत करेंगे, उसकी जांच के बाद इलाज शुरू हो जाएगा। इस तरह से राजधानी के अस्पतालों का डिजिटलीकरण होना दिल्ली की प्रगति का सूचक है। उन्होंने बताया कि एचआइएमएस को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ई-हेल्थ डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया है। वर्षों से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जानकारी का मैनुअल डेटा एंट्री किया जाता रहा, जबकि देश के अन्य हिस्से डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़ चुके थे। अब इस प्रणाली के माध्यम से 20 डिजिटल माड्यूल लागू किए जाएंगे, जिनमें ओपीडी- आइपीडी पंजीकरण, लैब एवं रेडियोलाजी प्रणाली, डाइटरी सेवाएं, अस्पताल प्रशासन और इलेक्ट्रानिक मेडिकल रिकार्ड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। डिजिटल हेल्थ रिकार्ड की सुविधा के लिए, अब तक लगभग 93 लाख आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) आइडी बनाए जा चुके हैं, जो मरीजों के स्वास्थ्य इतिहास को सुरक्षित रखने और विभिन्न अस्पतालों के बीच रेफरल प्रणाली को आसान बनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजधानी में कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना करना है।

सस्ती दवाओं की उपलब्धता का वादा: राजधानी के प्रमुख अस्पतालों जैसे चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, संजय गांधी मेमोरियल हास्पिटल, जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, डा. हेडगेवार आरोग्य संस्थान और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आदि में आठ नए जन औषधि केंद्र खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही, दिल्ली में अब कुल 25 जन औषधि केंद्र संचालित हो चुके हैं, जिनमें से 17 पिछले माह प्रारंभ किए गए थे।

दिल्ली सचिवालय में 34 नए आयुष्मान अरोग्य मंदिर सहित अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं को रिमोट द्वारा डिजिटल शुभारंभ करती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साथ में स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह। ध्रुव कुमार

34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत

सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी, बैंक एन्क्लेव, बुध नगर, रोहिणी सेक्टर- चार और साकेत आदि में 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। पीएम-एबीएचआइएम के अंतर्गत स्थापित इन सुविधाओं की कुल संख्या अब बढ़कर 67 हो गई है। मुख्यमंत्री ने पिछले माह 33 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया था। ये आरोग्य मंदिर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के लिए देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, टीबी- कुष्ठ रोग उन्मूलन और गैर-संचारी रोगों की जांच व प्रबंधन जैसी 12 मुख्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

जलभराव को लेकर आलोचना पर सीएम ने आप को लिया आड़े हाथ

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: दिल्ली में जलभराव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बुधवार सुबह वर्षा के बाद आप नेताओं ने जलभराव से संबंधित वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया था। गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, जलभराव व नागरिक मुद्दों पर 'सकारात्मक आलोचना' का वह स्वागत करती हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व की आप सरकार की गड़बड़ियों को ठीक किया जा रहा है।

बुधवार को पानी भरने पर आप की पूर्व पार्षद गीता रावत ने नाव चलाकर सरकार पर निशाना साधा था। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, "जो लोग अब 'इस सड़क को देखो, इस पानी को देखो' कहते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं, वही लोग पांच महीने पहले सत्ता में थे। उन्होंने तब इसे ठीक क्यों नहीं किया?"

गैंग्सटरों के विरुद्ध मामलों के लिए विशेष कोर्ट स्थापित करने पर करें विचार : कोर्ट

शीर्ष अदालत का केंद्र व दिल्ली सरकार से आग्रह, प्रस्ताव पेश करने को दिया तीन हफ्ते का समय

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी में गैंग्सटरों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने पर विचार करें। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में प्रभावी प्रस्ताव पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस समय सीमित संख्या में अदालतें विभिन्न मामलों के बोझ तले दबी हैं और गैंग्सटरों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतें आइपीसी, एनडीपीएस और पीएमएलए के तहत मामलों की भी सुनवाई कर रही हैं। पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश एएसजी एसडी संजय से कहा, "केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर गैंग्सटरों से संबंधित मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने पर निर्णय क्यों नहीं लेतीं? विशेष अदालतें स्थापित करने से त्वरित सुनवाई होगी।" शीर्ष अदालत ने कहा, "फास्ट ट्रैक अदालतों ने बहुत उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। इसी तरह गैंग्सटरों से संबंधित मामलों के लिए भी विशेष अदालतें हो सकती हैं। हम दुर्दांत अपराधियों की बात कर रहे हैं, छिटपुट घटनाओं की नहीं। समाज को उनसे छुटकारा पाना होगा। कानून का राज कायम होना चाहिए और पुलिस को निर्मम होना होगा।"

दिल्ली सरकार के हलफनामे का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि 288 मामलों में से केवल 108 में ही आरोप तय किए गए और उनमें से केवल 25 ही अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ के चरण तक पहुंच पाए। जस्टिस कांत ने कहा कि आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं कि कैसे गैंग्सटर मुकदमे में देरी करने की कोशिश करते हैं और मुकदमे को जल्द निपटाने की व्यवस्था के अभाव में अदालतों को जमानत देने के लिए मजबूर करते हैं। जमानत का विरोध करने के बजाय अभियोजन पक्ष को मुकदमे पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा कि सरकारी वकील मुकदमों के बोझ तले दबे होने के कारण विशेष कानून के तहत आने वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। यह चलन बन गया है कि सभी मामले गिरफ्तारी से शुरू होते हैं और बिना दोषसिद्धि या बरी हुए जमानत पर खत्म हो जाते हैं। जस्टिस कांत ने इसे एक विचित्र स्थिति बताया क्योंकि जब अदालतें आरोपितों को जमानत पर रिहा करती हैं, तो पुलिस उन्हें अदालत में वापस नहीं ला पाती। वे कहीं से भी और कभी भी गतिविधियां संचालित करते हैं। हरियाणा की सीमा से लगे दिल्ली के बाहरी इलाकों में स्थिति बहुत गंभीर है। जिन बुजुर्गों के बच्चे विदेश में रहते हैं, उन्हें चेन स्नैचिंग और अन्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

गवाहों की सुरक्षा के मुद्दे पर पीठ ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि सुरक्षा के अभाव में उन्होंने गैंग्सटरों के विरुद्ध गवाही नहीं दी। पीठ ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने और आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता है।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- देश में कानून का राज कायम होना चाहिए और पुलिस को निर्मम होना होगा
- भारत की जेलों या विदेश से धड़ल्ले से रंगदारी रैकेट चला रहे हैं 100 से अधिक गैंग्सटर

'गैंग्सटरों के अंदर पुलिस और कानून का खौफ खत्म'

जागरण संवाददाता । नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे गैंग्सटरों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गहरी चिंता जताई है। समाज के लिए खतरा बन चुके गैंग्सटरों के आतंक पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैंग्सटरों के प्रति किसी को भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने गैंग्सटरों को लेकर पहली बार यह टिप्पणी एक कुख्यात अपराधी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि आए दिन लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगने से ऐसा प्रतीत होता है कि गैंग्सटरों के अंदर पुलिस और कानून का डर खत्म हो चुका है। कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी इसलिए की क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के करीब 100 से अधिक कुख्यात गैंग्सटर या तो देश की विभिन्न जेलों अथवा विदेश में बैठकर गिरोह चला रहे हैं। हिमांशु उर्फ भाऊ, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, लारेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, ज्योति बाबा, काला जठेड़ी, छेनू, राशिद केबलवाला, हाशिम बाबा, कौशल चौधरी, अनवर चाचा आदि गैंग्सटर अब जेल आधारित माफिया कारपोरेट्स बन चुके हैं।

पर्यावरण को क्षति पहुंचाना पड़ेगा भारी, नियम हुए और सख्त

संजीव गुप्ता ● जागरण

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण का क्षति पहुंचाना अब और भारी पड़ेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने मौजूदा नियमों को सख्त करते हुए जुर्माना नहीं भरने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से वसूली (रिकवरी) की कार्रवाई का प्रविधान भी कर दिया है। गौरतलब है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के मामले में वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ पल्यूशन) एक्ट 1974 के नियमानुसार डीपीसीसी जुर्माना लगाने की कार्रवाई करता रहा है। लेकिन जुर्माना अदायगी की कोई समय सीमा तय नहीं होने और सख्ती के अभाव में उल्लंघनकर्ता जुर्माने की राशि भरते ही नहीं थे। कुछ कोर्ट चले जाते थे तो कुछ आधा अधूरा भरकर इतिश्री कर लेते थे। डीपीसीसी ने जुर्माना वसूली के लिए पहली बार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसमें जुर्माना लगाने से लेकर वसूली तक के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।

डीपीसीसी के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्यम के निरीक्षण करने के पांच कार्यदिवसों के भीतर ही उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस स्पीड पोस्ट या ई-मेल के जरिए भेजा जाएगा। इसका जवाब देने के लिए उक्त प्रतिष्ठान को 15 दिन का समय मिलेगा। इस प्रक्रिया पर हुई कार्रवाई पर 21 से 30 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जबकि, कारण बताओ नोटिस जारी करने के 60 दिन के भीतर पर्यावरण क्षति का जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए जाएंगे। 90 दिन के भीतर पर्यावरण क्षति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर रिकवरी के लिए मामले को एसडीएम के पास भेज दिया जाएगा।

- जुर्माना वसूलने को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पहली वार जारी की मानक संचालन प्रक्रिया
- 90 दिनों में पर्यावरण क्षति शुल्क नहीं भरने पर होगी अब वसूली की कारवाई

पांच साल में जुर्माना लगा 25 करोड़, वसूल हुए 11 करोड़

सख्ती के अभाव में उल्लंघनकर्ता जुर्माना भरने को लेकर कितने लापरवाह रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले पांच साल में लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि भी डीपीसीसी वसूल नहीं पाया। एक जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2024 तक पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीपीसीसी ने 815 नोटिस जारी किए। साथ ही 25 करोड़ का जुर्माना भी ठोंका। लेकिन डीपीसीसी को इस राशि में से केवल 11 करोड़ ही मिल पाए।

राजधानी में अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी दवाओं की बिक्री

अनूप कुमार सिंह ● जागरण

- सरकार ने जारी किया आदेश, सभी केमिस्ट एसोसिएशनों को दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में नकली दवाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए दवाओं की बिक्री पर सख्त नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी दवा की दुकानों पर अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में दवाओं की बिक्री होगी। सरकार की ओर से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव दानिश अशरफ ने 23 जुलाई को जारी आदेश में दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग को इसे सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने 24 जुलाई को दिल्ली के सभी केमिस्ट एसोसिएशनों को आदेश का पालन करने के लिए पत्र जारी कर दिया हैं।

विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शेड्यूल एच, एच-1 और एक्स दवाओं की अवैध व नकल की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस बाबत नेशनल नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन पोर्टल (एनसीओआरडी) की 11वीं बैठक में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के विशेष सचिव ने निर्देश जारी किए थे। इसके तहत कहा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। विभाग के मुताबिक दिल्ली की सभी केमिस्ट एसोसिएशन व दवा की 16 हजार फुटकर तथा 14 हजार थोक दुकानों तथा गोदामों को पहले भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी गई थी पर, जांच में सामने आया कि अधिकांश ने इसका अनुपालन नहीं किया, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए।

बीएस-6 वाहनों के परिचालन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें वाहनों पर आयु-आधारित एक समान प्रतिबंध लगाने के बजाय बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में चलने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ इस बात पर विचार करने पर सहमत हो गई कि क्या एनसीआर में बीएस-6 मानकों वाले पेट्रोल वाहनों की जीवन अवधि 15 वर्ष और डीजल वाहनों की जीवन अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। एक वकील द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सोमवार के लिए स्थगित कर दी। वकील ने कहा कि ऐसे वाहनों को उनकी जीवन अवधि समाप्त होने के बाद भी चलने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आवश्यक है क्योंकि ये अवधियां स्वयं अदालत ने निर्धारित की थीं।

एमसीडी में ढाई साल बाद गठित हुई समितियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम में भाजपा का शासन आने के बाद पहले वार्ड कमेटियों और फिर स्थायी समिति के गठन के बाद ढाई साल बाद तदर्थ और विशेष समितियों के गठन हो गया है। अब समितियों के सदस्य अपने बीच में किसी एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुनेंगे।

23 समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एमसीडी की सदन की विशेष बैठक में पूरी की गई। महापौर राजा इकबाल सिंह ने तय सदस्यों की संख्या और प्राप्त नामांकन की संख्या समान होने पर सभी सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।

इसके साथ ही नेता सदन प्रवेश वाही ने अनुसूचित जाति व जनजाति समिति के साथ ही शिक्षा समिति में तीन-तीन सदस्यों के मनोनयन के लिए महापौर को अधिकृत किया। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी ने अनुसूचित जाति व जनजाति समिति में कुल सदस्यों की संख्या 35 से घटाकर 21 करने पर विरोध जताया। इसकी वजह हंगामा होता देख महापौर ने बैठक को अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया।

सदन की बैठक के बाद महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि ढाई साल से आप ने जिन समितियों का गठन नहीं होने दिया था भाजपा की सरकार आने के बाद उनका गठन किया जा रहा है। हमने पहले वार्ड कमेटियों का गठन कराया। इसके बाद स्थायी समिति का गठन कराया और फिर अब सभी 23 तदर्थ और विशेष के साथ वैधानिक समितियों का गठन हम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यों का निर्वाचन का कार्य हो गया है। जल्द ही इन समितियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के चुनाव की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। जल्द ही इन कमेटियों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। संभवतः 31 जुलाई तक नामांकन होंगे। महापौर ने कहा कि चूंकि पिछले सदन की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। विरोध जताकर वे सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं।

सिविक सेंटर में नगर निगम सदन की बैठक लेते महापौर राजा इकबाल सिंह। जागरण

कौन-कौन सी हैं समितियां

विशेष समिति में आश्वासन, नियुक्तियां और पदोन्नितयां, निर्माण, चिकित्सा सहायता एवं जन स्वास्थ्य, पर्यावरण सेवाएं, उद्यान, हिंदी, खेल-कूद प्रोत्साहन, उच्चाधिकार प्राप्त संपत्तिकर समिति, निगम लेखा समिति, पार्षदों के लिए आचार संहिता समिति हैं। जबकि तदर्थ समितियों में लाइसेंसिंग, सामुदायिक, मलेरिया निरोधक उपाय, बाढ़ नियंत्रण उपाय, गलियों आदि के नामकरण, सहायता अनुदान, राष्ट्रीय त्यौहार, महिला कल्याण एवं बाल विकास, शिकायत निवारण समिति हैं।

पूर्व एनटीबीसीएल अधिकारी पर टिप्पणी वाले आदेश को संशोधित करने पर सहमति

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे का संचालन करने वाली निजी फर्म नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों वाले अपने आदेश में संशोधन करने पर गुरुवार को सहमति जताई। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि हालांकि एनटीबीसीएल के पूर्व अधिकारी प्रदीप पुरी के खिलाफ टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से की गई थी, चूंकि वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए अदालत नहीं चाहती कि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े।

पीठ ने कहा कि कैग रिपोर्ट स्पष्ट है। इसलिए फैसला वही रहेगा। हालांकि, हम पूर्व अधिकारी के खिलाफ टिप्पणियों के संबंध में फैसले में संशोधन करेंगे। पुरी ने कैग रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित फैसले में उनके खिलाफ की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों को हटाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

सवाल

हमदर्द सोसाइटी ने एमबीबीएस-पीजी की 199 सीटें शून्य किए जाने पर दिया जवाब, कहा- 2021 के समझौता ज्ञापन व प्रबंधन बोर्ड के प्रस्ताव के तहत संस्थान है स्वायत्त, कैग रिपोर्ट में गड़बड़ी वित्तीय रिकार्ड में मिसप्रिंट से होने का किया दावा

जिस डीन को बताया फर्जी, वही संस्थान में काम करते मिले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय प्रशासन और हमदर्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के बीच तनातनी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कभी डिग्री होल्ड होने के नाम पर तो कभी परीक्षा से ही वंचित किए जाने को लेकर छात्र ही सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ताजा मामला एचआइएमएसआर के डीन का है। विश्वविद्यालय प्रशासन दो जुलाई 2025 को जारी अपने पत्र में जिस डीन को फर्जी करार दिया था, मौके पर वही डीन कार्यालय में कामकाज संभालते मिले। उन्हीं की ओर से 21 जुलाई 2025 को नोटिस भी जारी किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से प्रो. सुधीर कुमार जैन को डीन नियुक्त किया गया है, जबकि संस्थान की ओर से यह जिम्मेदारी डा. मुसर्रत हुसैन संभाल रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, विगत छह जून को जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय की ओर से नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को पत्र लिखकर एचआइएमएसआर में एडमिशन और आनलाइन पोर्टल पर अपना नियंत्रण न होने का हवाला दिया। साथ ही कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एचआइएमएसआर में 813 करोड़ रुपये के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 150 एमबीबीएस और 49 पीजी मेडिकल सीटें वापस ले ली हैं। इसके चलते एनएमसी के अस्थाई सीट मैट्रिक्स में अब एचआइएमएसआर की सीटें शून्य दिख रही हैं। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब 21 जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। यह फैसला उन छात्रों के लिए चिंता का विषय है, जो हमदर्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च को मेडिकल करियर की मंजिल मानते थे। उन्हें नीट काउंसलिंग में अन्य विकल्पों पर ध्यान देना होगा।

संस्थान के लिए उपलब्ध कराए 426 करोड़: एचईएस: एचआइएमएसआर का प्रबंधन देख रही हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी ने कहा, सीटों की वापसी पूरी तरह से जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय द्वारा छह जून, 2024 को संबद्धता रद करने के एकतरफा फैसले के कारण हुई, जो दिल्ली हाई कोर्ट के यथास्थिति आदेश का उल्लंघन था।

विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। डीन की नियुक्ति मैंने की है। जिन लोगों ने किसी और डीन के हवाले से विवि के पोर्टल पर 21 जुलाई को नोटिस जारी की है, वे खुद ही मामले में फंस रहे हैं। - **प्रो. मोहम्मद अफशार आलम, कुलपति, जामिया हमदर्द**

****

लक्ष्मी पुरी और साकेत गोखले को हाई कोर्ट ने समझौते की दी सलाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद साकेत गोखले के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह दी।

कोर्ट ने कहा कि अदालतों पर पहले से ही भारी बोझ है इसलिए समझौता एक बेहतर विकल्प हो सकता है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह सुझाव तब दिया जब कोर्ट को बताया गया कि गोखले ने पुरी से माफी मांग ली है और पुरी ने वह माफी स्वीकार भी कर ली है। पुरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह और गोखले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वे अपने-अपने मुवक्किलों से बात करेंगे और कोर्ट के समझौते के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

दिल्ली के मंत्री ने पंजाब सरकार और आप पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

- मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, जांच कराने की मांग

दिल्ली सरकार में मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी (आप) पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पंजाब पुलिस के लिए खरीदी गई 144 लग्जरी गाड़ियों की कीमत बाजार दर से कहीं ज्यादा दी गई और इससे जनता के 14 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक आप की ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

दिल्ली के मंत्री ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने सीधे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है, वो भी आरोपों और बिल की प्रतियों के साथ। सिरसा का कहना है कि ये गाड़ियां, टोयोटा हीलक्स बाजार में 37 लाख रुपए में उपलब्ध थीं और उस पर भी कंपनी 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट देने को तैयार थी। बावजूद इसके पंजाब सरकार ने हर गाड़ी 47 लाख रुपए में खरीदी। यानी एक गाड़ी पर सीधा 10 लाख रुपए का अंतर! और अगर इसे 144 गाड़ियों पर लागू किया जाए तो मामला सीधे 14 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले का बनता है। सिरसा ने अपने पत्र में सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि इस पूरे सौदे की पारदर्शी जांच की मांग भी की है।

मनजिंदर सिंह सिरसा। फाइल

95.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास है शौचालय की सुविधा है। यह जानकारील गुरुवार को लोक सभा में जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने दी है।

सीमा पार आतंकवाद से निपटने को भारत और ब्रिटेन बढ़ाएंगे सहयोग

संबंधों में प्रगाढ़ता ▶ कारोबारी ही नहीं, रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ब्रिटेन के लिए भारत ज्यादा महत्वपूर्ण

भारत-ब्रिटेन आतंकी खतरे से जुड़ी सूचनाएं साझा करेंगे, न्यायिक सहयोग बढ़ाएंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इंग्लैंड के चेकर्स में गुरुवार को क्रिकेट खेलते स्कूली बच्चों से मिलने पर भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला बल्ला पकड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष किएर स्टार्मर। jएपी

1947 में आजादी के बाद कई दशकों तक ब्रिटेन कूटनीतिक व रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के करीब रहा। शीत युद्ध के काल में भारत के हितों के बजाय ब्रिटिश सरकार ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मगर पीएम नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश पीएम किएर स्टार्मर ने गुरुवार को द्विपक्षीय संबंधों का अगले 10 वर्षों का जो रोडमैप विजन डाक्यूमेंट-2035 जारी किया है, वह बताता है कि सिर्फ कारोबारी दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत ब्रिटेन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।

ब्रिटेन सरकार ने हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए भारत के साथ सहयोग करने की बात कही है। साथ ही आतंकियों और उन्हें प्रश्रय देने वालों के खिलाफ भारत के साथ सूचना साझा करने व उन पर लगाम लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर काम करने की बात कही है।

विजन डाक्यूमेंट-2035 में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने का भी रोडमैप है। इसमें अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने की बात है। रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से निगरानी करने की व्यवस्था की जा रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश सेना के लिए हिंद महासागर में भारत एक क्षेत्रीय हब के तौर पर काम करेगा।

इस प्रपत्र में दोनों देशों ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की है और आतंकवाद व कट्टरवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही है। भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रस्तावना को कड़ाई से लागू करने की मांग लगातार करता है, जिसका ब्रिटेन ने स्वागत किया है। विजन डाक्यूमेंट में कहा गया है कि दोनों देश सीमा पार आतंकी गतिविधियों, आतंकियों को वित्तीय समर्थन देने वालों पर रोक लगाने, आतंकियों की तरफ से नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने पर तैयार हैं। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत और ब्रिटेन आतंकवाद से जुड़े हर तरह के खतरे को रोकने के लिए सूचनाओं को साझा करने, न्यायिक सहयोग बढ़ाने की भी सहमत हुए हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से नामित आतंकियों, आतंकवादी संगठनों और इनको प्रश्रय देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी दोनों देश पहले के मुकाबले अब ज्यादा एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।

सर्वाधिक समय तक लगातार पीएम पद संभालने वाले दूसरे नेता बने मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खाते में एक और रिकार्ड जुड़ गया है। शुक्रवार 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी के कार्यकाल के 4078 दिन पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक समय तक लगातार देश सेवा करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी पहले कार्यकाल में 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थीं। हालांकि इंदिरा दूसरे कार्यकाल में 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं।

पीएम के तौर पर कुल कार्यकाल के मामले में इंदिरा अभी भी दूसरे स्थान पर हैं। सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शीर्ष पर हैं। वह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे। नरेन्द्र मोदी राज्य और केंद्र मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करने वाले इकलौते नेता हैं। मोदी गैर-हिंदी भाषी राज्य से सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में कुछ अन्य रोचक तथ्य भी हैं। मसलन, वह एकमात्र ऐसे पीएम हैं, जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ।

संसद प्रश्नोत्तर

बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन छुट्टी की है अनुमति

▶ केंद्रीय कर्मियों के संबंध में जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी जानकारी

▶ यह भी बताया, भारत बना रहा तीन प्रकार के छोटे माड्यूलर रिएक्टर

जितेंद्र सिंह। फाइल/प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कारणों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रविधान है? सिंह ने लिखित उत्तर में बताया, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की आधी वेतन की छुट्टी, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और प्रति वर्ष दो दिन की प्रतिबंधित छुट्टी प्रदान की जाती है। इसके अलावा अन्य पात्र छुट्टियां भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं, जिन्हें किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए भी अधिकतम एक महीने की छुट्टी लेना शामिल है।

एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि भारत तीन विभिन्न प्रकार के छोटे माड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित कर रहा है। इसमें एक हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समर्पित है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए कैप्टिव संयंत्रों के रूप में होगा। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए तीन प्रकार के एसएमआर-200 मेगावाट भारत छोटे माड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर), 55 एमडब्ल्यूई एसएमआर और 5 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शन रिएक्टरों के निर्माण के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्राप्त की गई है। इन प्रदर्शन रिएक्टरों का निर्माण 60 से 72 महीनों के भीतर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। बीएसएमआर और एसएमआर की प्रमुख इकाइयां परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की साइटों पर न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआइएल) के सहयोग से स्थापित की जाने की योजना है।

आपरेशन सिंदूर भारत की संतुलित कार्रवाई

▶ सरकार ने पाक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर रास में दी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत सरकार ने संसद में बताया कि आपरेशन सिंदूर 'पाकिस्तान-समर्थित आतंकियों' द्वारा किए गए 'बर्बर' हमले के जवाब में शुरू किया गया था और इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य आतंकी ढांचे को नष्ट करना और उन आतंकियों को निष्क्रिय करना था जिन्हें भारत में भेजे जाने की आशंका थी। सरकार ने कहा कि भारत की कार्रवाई 'केंद्रित, संतुलित और गैर-उत्तेजक' थी।

राज्यसभा में सदस्य रामजी लाल सुमन के एक सवाल के लिखित उत्तर में विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि जबकि पाकिस्तान ने कुछ सैन्य सुविधाओं के अलावा भारतीय नागरिक क्षेत्रों को लक्षित करने का प्रयास किया। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के किए गए इन उत्तेजक और उग्र कार्यों का भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मजबूत और निर्णायक प्रतिक्रिया दी गई, जिससे पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद 10 मई, 2025 को पाकिस्तान के सैन्य संचालन के महानिदेशक ने अपने भारतीय समकक्ष से फायरिंग और सैन्य गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया, जिसे उसी दिन बाद में स्वीकार कर लिया गया। ध्यान रहे कि आपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सात मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम जम्मू कश्मीर (पीओजेके) में नौ आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए की गई थी।

यह भी पूछा गया था कि क्या विदेश मंत्रालय ने 'पाकिस्तान को विश्व मंच पर अलग-थलग करने' के प्रयास किए हैं। इस पर मंत्री ने कहा, 'भारत के निरंतर प्रयासों के कारण वैश्विक समुदाय को सीमा पार आतंकवाद के संबंध में भारत की चिंताओं की बेहतर समझ है।'

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक ही दिन 112 पायलटों ने लिया चिकित्सा अवकाश

▶ नागर विमानन राज्यमंत्री मोहोल ने बताया, पायलटों के चिकित्सा अवकाश लिए जाने में हुई है वृद्धि

मुरलीधर मोहोल। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : अहमदाबाद विमान दुर्घटना के चार दिन बाद एक ही दिन में एअर इंडिया के 112 पायलटों ने लिया चिकित्सा अवकाश लिया। नागर विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने गुरुवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद पायलटों के चिकित्सा अवकाश लिए जाने में वृद्धि देखी गई है। 16 जून को 112 पायलटों ने बीमार होने की सूचना मिली है, जिनमें 51 कमांडर और 61 फर्स्ट आफिसर शामिल थे।

गौरतलब है कि एअर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून को अहमदाबाद हवाईअड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोगों में केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा। वहीं, विमान के इमारत से टकराने पर दुर्घटनास्थल पर मौजूद 19 लोगों की भी जान चली गई। एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्तमान में विमान दुर्घटना के कारण जमीन पर नागरिकों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे से संबंधित कोई विशिष्ट नीति नहीं है।

एआइ एक्सप्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई : मोहोल ने बताया कि डीजीसीए ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि डीजीसीए ने निरीक्षण के दौरान पाया कि एयरलाइन ने एयरबस ए320 विमान में लगे इंजनों के संबंध में उड़ान योग्यता निर्देश का पालन नहीं किया। हालांकि यह नहीं बताया कि दंडात्मक कार्रवाई कब की गई।

जस्टिस वर्मा मामले में आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करेंगे बिरला

▶ तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन के लिए चल रहा है विचार-विमर्श

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति के गठन की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि 152 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ 21 जुलाई को बिरला को सौंपा गया नोटिस अब सदन की संपत्ति है। तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन के लिए परामर्श शुरू हो गया है, जिसमें या तो भारत के प्रधान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। चूंकि उसी दिन 63 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक नोटिस राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ को भी सौंपा गया, इसलिए उच्च सदन भी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है।

प्रक्रिया के तहत स्पीकर से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध करेंगे, जबकि प्रतिष्ठित न्यायविद का चयन उनका विशेषाधिकार है। नोटिस प्रस्तुत किए जाने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श का हिस्सा रहे हैं।

धनखड़ ने सोमवार को राज्यसभा में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम का हवाला देते हुए कहा था कि जब संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन नोटिस प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति गठित की जाती है।

हर तहसील में बनेंगे पांच माडल सहकारी गांव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ 23 वर्षों के बाद मिली देश को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति, ग्राम विकास पर दिया गया है जोर

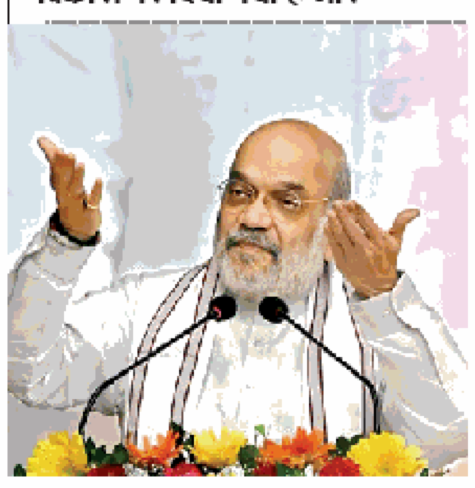
नई दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारिता नीति- 2025 के अनावरण के अवसर पर संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। एएनआइ

देश को 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति मिली है, जिसका अनावरण गुरुवार को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इसका उद्देश्य सहकारिता के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित कर भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक तहसील में पांच-पांच माडल सहकारी गांवों की स्थापना है। ये गांव राज्य सहकारी बैंकों की सहायता से विकसित किए जाएंगे और इनमें महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नीति का मसौदा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विमर्श के बाद तैयार किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 सदस्यीय समिति ने इसकी रूपरेखा तैयार की है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में नाबार्ड ने माडल सहकारी गांव बनाए हैं। उसी तर्ज पर यह काम तहसीलों में होगा। नीति में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए एक पारदर्शी तकनीकी माडल तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव में सहकारी इकाई बनाने का है, जो पैक्स, मछुआरा समिति, डेयरी या बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में हो सकती है। नई सहकारिता नीति में विशेष जोर आर्थिक रूप से स्वतंत्र, पेशेवर तरीके से संचालित एवं सफल छोटी सहकारी इकाइयों को प्रोत्साहित करने पर दिया गया है। शाह ने कहा कि सहकारिता को पारंपरिक क्षेत्रों से निकालकर हेल्थ, टूरिज्म, टैक्सी, ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों में भी शामिल किया जाएगा। 'सहकार टैक्सी' सेवा इसी वर्ष के अंत तक शुरू कर दी जाएगी, जिससे सीधे लाभ ड्राइवर तक पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि सहकारी इकाइयों को तकनीक से युक्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। प्रत्येक दस वर्ष में जरूरत के अनुसार नियमों-कानूनों में संशोधन की व्यवस्था की गई है। नीति के माध्यम से महिला, युवा, आदिवासी और दलित वर्ग के समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है। छोटी-छोटी पूंजी को मिलाकर बड़ी आर्थिक ताकत बनाना केवल सहकारिता के जरिये संभव है और यही इसकी मूल भावना है।

शाह ने नई सहकारिता नीति को नवाचार एवं वैश्विक बाजार में विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि इसके लिए तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनाई गई हैं, जिनमें बीज उत्पादन, निर्यात और जैविक उत्पादों के सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को प्रमुखता से शामिल किया गया है। नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन की भूमिका को भी मजबूत किया गया है।

संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' पर पुनर्विचार से इन्कार

▶ केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा-फिलहाल नहीं है कोई योजना

▶ मेघवाल बोले-सरकार ने कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है

अर्जुन राम मेघवाल। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों को हटाने या उस पर पुनर्विचार करने की 'कोई वर्तमान योजना या इरादा' नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों ही शब्द तत्कालीन केंद्र सरकार ने आपातकाल के दौरान जोड़े थे। संसद को यह भी बताया गया कि सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से इन दो शब्दों को हटाने के लिए 'औपचारिक' रूप से कोई कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में कहा कि जबकि कुछ सार्वजनिक या राजनीतिक हलकों में चर्चाएं या बहसें हो सकती हैं, लेकिन सरकार द्वारा इन शब्दों में संशोधन के संबंध में कोई औपचारिक निर्णय या प्रस्ताव नहीं घोषित किया गया है।' सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों को हटाने या पुनर्विचार करने का कोई वर्तमान योजना या इरादा नहीं है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 1976 के संशोधन (42वें संवैधानिक संशोधन) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि संसद का संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रस्तावना तक फैला हुआ है। भारतीय संदर्भ में 'समाजवाद' का अर्थ कल्याणकारी राज्य है और यह निजी क्षेत्र की वृद्धि में बाधा नहीं डालता, जबकि 'पंथनिरपेक्षता' संविधान की मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा है।

जजों की 193 रिक्तियों के लिए अभी तक नामों की सिफारिश नहीं

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा को सूचित किया कि विभिन्न हाई कोर्टों में 371 जजों के पद रिक्त हैं और हाई कोर्टों की कालेजियम ने इन रिक्तियों में से 50 प्रतिशत से अधिक के लिए अभी तक कोई सिफारिश नहीं भेजी है। हाई कोर्टों से 193 रिक्तियों के खिलाफ सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। हाई कोर्टों को रिक्ति होने से कम से कम छह महीने पहले सिफारिशें करनी होती हैं। इस समयसीमा का कभी-कभी ही पालन होता है।

जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

▶ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की दोबारा सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी का मामला

▶ याचिकाओं में केंद्र पर उठाए गए हैं सवाल, दो सप्ताह बाद शीर्ष कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट ने कोलेजियम द्वारा जजों के नामों की दोबारा अनुशंसा के बाद भी जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की ओर से हो रही देरी पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर गुरुवार को सहमति जताई।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वह दो सप्ताह बाद याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीठ ने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार और प्रशांत भूषण की अपील पर यह सहमति दी। दोनों वकीलों ने याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये 2023 में सूचीबद्ध थीं, लेकिन उन्हें सूची से हटा दिया गया। दातार ने कहा, कुछ जजों के नाम 2019, 2020 और 2022 में दोबारा सिफारिश के बावजूद अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। हर स्तर पर निर्णय लेने की निश्चित समयसीमा होती है। कुछ हफ्तों की देरी समझ में आती है, लेकिन चार साल की देरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। वकील ने उन उदाहरणों का भी उल्लेख किया जहां दिल्ली और मुंबई के वकीलों, जिनके नामों की सिफारिश की गई थी ने आखिरकार अपने नाम वापस ले लिए। भूषण ने दिल्ली की वकील के नाम को स्वीकृत न किए जाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि वह नेशनल ला स्कूल की टापर रही हैं।

शीर्ष अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें हाई कोर्ट के जजों की पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी देने के लिए 2021 के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित समयसीमा का कथित रूप से पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।

सियासी संग्राम में चौथे दिन भी ठप हुई संसद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ राज्यसभा में वाइको, रामदास समेत छह सदस्यों की विदाई तक ही दिखाया विपक्षी दलों के सांसदों ने संयम

▶ दोनों सदनों में प्रश्नकाल भी नहीं चला, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष के तेवर जारी

संसद परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन करतीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों के अन्य सदस्य। प्रेट्र

जैसी कि मानसून सत्र को लेकर आशंका जताई जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही हाल संसद का दिखाई भी दे रहा है। पहलगाम हमले और आपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा के लिए सरकार सहमत हो गई, लेकिन बिहार मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा संग्राम छिड़ा है कि संसद के दोनों सदन लगातार चौथे दिन भी इसी पर हंगामे की भेंट चढ़ गए। राज्यसभा की कार्यवाही जरूर कुछ देर तक चली, लेकिन सिर्फ सेवानिवृत्त हो रहे छह सदस्यों की विदाई तक ही विपक्षी खेमे ने संयम बरता।

राजनीति को गर्माने वाले कुछ ऐसे ताजा मुद्दे हैं, जिनके कारण संसद का मानसून सत्र पटरी ही नहीं चढ़ पा रहा है। इस बीच बुधवार को हुई राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच इस पर सहमति बन गई थी कि राज्यसभा को कम से कम सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई के लिए चलाया जाए। हुआ भी यही, गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उसके बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सूचना दी कि तमिलनाडु से ही आने वाले छह सांसद एमडीएमके सदस्य एम. वाइको, डीएमके सदस्य एन. शनगुनम, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला और पी विल्सन, एआइएडीएमके सांसद एम. चंद्रशेखरन और पीएमके से डा. अंबुमणि रामदास का कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो गया। ऐसे में प्रमुख नेताओं ने इन सदस्यों के संसदीय योगदान की सराहना करते हुए विदाई वक्तव्य दिया। यह भी बताया गया कि इनमें से पी. विल्सन का फिर से राज्यसभा में आना तय हो गया है।

विदाई भाषण पूरे होने के बाद जैसे ही उपसभापति ने जैसे ही प्रश्नकाल आरंभ करना चाहा, वैसे ही विपक्षी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए। बिहार मतदाता सघन पुनरीक्षण के मुद्दे पर हंगामा व नारेबाजी करने लगे। इस पर पहले दोपहर दो बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

सीपेक परियोजनाओं का तीसरे देश तक विस्तार अस्वीकार्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) को वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) की एक प्रमुख परियोजना में शामिल करने पर संबंधित पक्षों के समक्ष लगातार विरोध जताया है। उनसे इन गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा गया है।

राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत सरकार 21 मई 2025 को बीजिंग में आयोजित चीन-पाकिस्तान अफगानिस्तान बैठक से अवगत है। सीपेक पर सरकार का रुख साफ है। किसी भी तीसरे देश की प्रस्तावित भागीदारी या तथाकथित सीपेक परियोजनाओं का तीसरे देश तक विस्तार अस्वीकार्य है। सरकार ने संबंधित पक्षों को लगातार इस स्थिति से अवगत कराया है।

****

कह कर रहेंगे
माधव जोशी

12 जिलों में उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पहले चरण में गुरुवार शाम तक 60 प्रतिशत मतदान हुआ। 6049 पदों के लिए 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया है।

राहुल ने चेताया, बख्शे नहीं जाएंगे वोट चोरी करने वाले

किया दावा, कर्नाटक के एक चुनाव क्षेत्र में चुनाव आयोग की ओर से धोखाधड़ी की अनुमति देने के ठोस सुबूत कांग्रेस के पास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण में भारी हेर-फेर का दावा करते हुए इसके खिलाफ सड़क से संसद तक आक्रामक लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी के पास इसके 100 प्रतिशत पुख्ता सबूत हैं कि कर्नाटक के एक चुनाव क्षेत्र में चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की अनुमति दी। लोकसभा में नेता विपक्ष ने बिहार में पुनरीक्षण पर चेतावनी देते हुए कहा-चुनाव आयोग गलतफहमी में न रहे, वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100 प्रतिशत पुख्ता सुबूत हैं हमारे पास। हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण पर आयोग के 24 जून के लिखित निर्देश का पालन नहीं हो रहा है और इसीलिए जितने भी आंकड़े चुनाव आयोग दिखा रहा वह सरासर झूठ है।

संसद में पुनरीक्षण विवाद पर चर्चा की एकजुट विपक्ष की मांग का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि यह संवैधानिक संस्था देश के चुनाव आयोग के रूप में अपना काम नहीं कर रही है। विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से वंचित वर्ग के लोगों को बड़ी संख्या में बाहर कर दिए जाने की गहरी आशंका जताते हुए बिहार चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला होने के राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी की अनुमति देने को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ 90 प्रतिशत नहीं, जब हम इसे आपको दिखाने का फैसला करेंगे तो यह 100 प्रतिशत ठोस सुबूत होगा। इस तरह की धोखाधड़ी की पड़ताल के लिए कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कराए गए अध्ययन का जिक्र करते हुए कहा, हमने अभी एक निर्वाचन क्षेत्र पर नजर डाली और हमें इसका प्रमाण मिला। मुझे पूरा यकीन है कि तमाम चुनावी सीटों पर यही नाटक चल रहा है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में हजारों-हजार नए मतदाता बनाए जा रहे, उनकी उम्र कितनी है 45, 50, 60, 65 साल। मतदाताओं का नाम हटाने और जोड़ने के इस खेल में हमने उन्हें पकड़ लिया है।

- कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने कहा-पुनरीक्षण में प्रक्रिया का पालन नहीं, आयोग के आंकड़े झूठे, हो रही वोटर लिस्ट कैप्चरिंग

राहुल गांधी। फाइल

कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लावरू ने मुख्य चुनाव आयुक्त को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि हर विधानसभा में 1,000 लोगों को चुन कर यह देखा जाए कि पुनरीक्षण के लिए तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। अगर 25 प्रतिशत भी इसमें सही निकला तो हम इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार खुलेआम भाजपा से मिलकर बिहार में गरीब, युवा, महिला, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट चोरी कर उनके वोट का अधिकार चुरा रहे हैं और राज्य में चुनाव की चोरी की तैयारी चल रही है। पहले के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी। आज मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिये बिहार में भाजपा वोटर लिस्ट कैप्चरिंग कर रही है।

राहुल की धमकी भरी टिप्पणियों पर आयोग का पलटवार, कहा-आरोप आधारहीन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राहुल गांधी की ओर से कर्नाटक में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणियों पर आयोग ने तीखा पलटवार किया है। कहा कि उन्हें आधारहीन और झूठे आरोप लगाने से बचना चाहिए। आयोग ने इस दौरान कुछ तथ्य भी पेश किए और कहा कि इसे हर भारतवासी को जानना चाहिए।

आयोग के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की जिस मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है, उसने लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का उस समय इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जिसमें उसे मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर जिला और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करनी थी। यह उनके पास एक वैध कानूनी उपाय था। लेकिन, कांग्रेस सहित किसी भी दल ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान गड़बड़ी को लेकर एक भी अपील नहीं की। आयोग ने कहा कि आयोग यह सोचने को मजबूर है कि इस प्रकार से आधारहीन व धमकीपूर्ण आरोप अब

- कर्नाटक में 2024 में कराए गए पुनरीक्षण में नहीं मिली थी आपत्ति
- लोस चुनाव की प्रक्रिया को लेकर दायर 10 याचिकाओं में एक भी चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार की नहीं

आयोग और उसके अधिकारियों के खिलाफ क्यों लगाए जा जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर दायर की गई 10 याचिकाओं में से भी एक भी याचिका कांग्रेस के किसी हारे हुए प्रत्याशी की ओर से नहीं दायर की गई है। इस बीच, कर्नाटक के मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने एक्स पर 2024 में हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का पूरा ब्योरा साझा किया गया है, जिसमें कहा है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र से एक भी आपत्ति इस दौरान उन्हें नहीं मिली है। कानूनी उपाय का भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं इस्तेमाल किया था।

नाम गलत जुड़ा या छूटा हो तो एक सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटने और फर्जी मतदाता बनाने के लग रहे आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि यदि एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में किसी का नाम छूट गया है या नाम गलत जुड़ गया है तो राजनीतिक दल और जागरूक मतदाता आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होते ही बिहार के सभी 12 राजनीतिक दलों को इसकी प्रिंटेंड और डिजिटल प्रति दी जाएगी। साथ ही इस प्रारूप मतदाता सूची को बेवसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। आयोग ने पुनरीक्षण अभियान के तहत 24 जुलाई तक बिहार के 99 प्रतिशत मतदाताओं तक पहुंचने का दावा दिया है। आयोग ने प्रारूप से जुड़ी आपत्तियों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) व सहायक निर्वाचन पंजीयक अधिकारी (एईआरओ) के पास दर्ज कराने को कहा है। साथ ही कहा है कि यदि वहां से वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास उसे चुनौती दे सकते हैं।

आयोग के अनुसार, बूथ लेवल आफीसर (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की पड़ताल में अब तक

- चुनाव आयोग ने एक अगस्त को ड्राफ्ट सूची आने से पहले राजनीतिक दलों और आम लोगों को किया सतर्क
- पुनरीक्षण में पहले चरण में 99 प्रतिशत मतदाताओं तक पहुंचने और इनमें 21.6 लाख के मृत मिलने का दावा

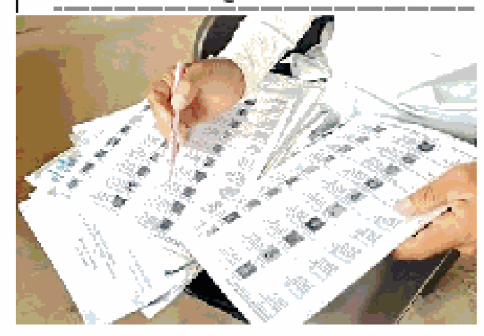

21.6 लाख मृत मतदाताओं के नाम पाए गए हैं जबकि 31.5 लाख मतदाता स्थाई रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं। वहीं सात लाख मतदाताओं के वोट एक से अधिक जगह पर पाए गए हैं। इसके साथ ही एक लाख मतदाताओं का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है।

इसके अतिरिक्त बीएलओ व बीएलए के घर-घर दौरों के बावजूद भी करीब सात लाख मतदाताओं के गणना फार्म अभी वापस नहीं मिले हैं। आयोग के अनुसार, इन सभी लोगों की सूची जिलों में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को 20 जुलाई को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं 7.21 करोड़ मतदाताओं के गणना फार्म डिजिटल तरीके से अपलोड़ कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि बिहार में मौजूदा समय में 7.90 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं।

'चुनाव बहिष्कार भी विकल्प, जनता से लेंगे राय'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा है कि उनके लिए चुनाव बहिष्कार का भी एक विकल्प है। इसका निर्णय सहयोगी दलों की राय और जनता की सहमति से ही लिया जाएगा। गुरुवार को बिहार विधानसभा के बाहर मीडिया से उन्होंने कहा कि वह यथाशीघ्र जनता के बीच जाकर इसके लिए राय लेंगे। पूछेंगे कि क्या बिहार को ऐसा चुनाव स्वीकार करना चाहिए, जिसमें अंदरखाने सब कुछ तय हो चुका है या फिर जनादेश को लूटने वालों के विरुद्ध इन्कलाब बुलंद होना चाहिए?

मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को तेजस्वी ने नौटंकी बताया। कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता संख्या की 'राजनीतिक हत्या' कर रहे हैं। पहले मतदाता सरकार चुनते थे, अब सरकार तय कर रही कि कौन वोट देगा। जब चुनाव मात्र दिखावा हो, जब ईवीएम का खेला तय हो, तो फिर वोट क्यों डाले जाएं? चुनाव आयोग रेफरी नहीं, बल्कि खिलाड़ी बन गया है। उन्होंने इसे चंडीगढ़ माडल बताया। कहा कि अगर यही बेईमानी चलनी है तो चुनाव आयोग और सरकार को सीधा 'एक्सटेंशन लेटर' पकड़ाओ, चुनाव का ड्रामा बंद करो। अब तो खुलकर नंगापन सामने आ गया है, तो अपने आकाओं को बनाकर रखो, हम भी हर प्लेटफार्म पर टकराएंगे। कहा कि राज्य सरकार हमारी घोषणाओं की नकल कर रही है। लेकिन, यह सरकार आगे चल नहीं पाएगी। भाजपा पर मुख्यमंत्री नीतीश को हाईजैक करने का आरोप लगाया। कहा कि जदयू के चार नेताओं ने इस दल को भाजपा का प्रकोष्ठ बना दिया है। नीतीश कभी राज्य के लिए विशेष दर्जा और पैकेज की मांग करते थे। अब नहीं कर रहे हैं। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से सबक लेना चाहिए, जो अपने राज्य के लिए केंद्र से पैकेज ले जा रहे हैं।

- तेजस्वी बोले-हमारी घोषणाएं कापी कर रही सरकार, चुनाव बाद चल नहीं पाएगी

पटना में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान परिसर में मीडिया से बात करते नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। प्रेट्र

मुझे मरवाना है तो अपना लाइसेंसी हथियार देता हूं

विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत पहुंचने पर तेजस्वी ने कहा कि सरकार मुझे मरवाना चाहती है तो मैं अपना लाइसेंसी हथियार देता हूं। वह मुझे मरवा दे। आरोप लगाया कि विधायक जनक सिंह ने उन्हें अपशब्द कहे।

बिहार विस में पक्ष-विपक्ष में तीखी नोक झोंक, हाथापाई की नौबत

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन पहली पाली जहां शांतिपूर्ण रही, वहीं दूसरी पाली में पक्ष-विपक्ष में तीखी नोक झोंक हुई। फिर हाथापाई की नौबत आ गई। सदस्यों के लिए लगाए गए माइक तक को उखाड़ लिया गया। सदस्यों के हंगामे को देखते हुए करीब 2.39 बजे सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे।

विधानसभा की दूसरी पाली में समाज कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा चल रही थी। उस वक्त कांग्रेस विधायक अजय कुमार के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में तेजस्वी बोल रहे थे। अपने संबोधन के दौरान कई सदस्यों के साथ तेजस्वी की नोक झोंक हो गई। इसी बीच तेजस्वी ने एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की हकीकत दिखाने वाले पत्रकार पर केस करने का हवाला दिया। जिसका विरोध उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया और कहा कि फर्जी मामला है। जो ऐसा कर रहा है, वह फर्जी है। पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा, आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन गलत है और कौन सही। सम्राट इस पर नाराज हो गए और बहस शुरू हो गई। दोनों नेताओं की बहस में भाजपा विधायक जनक सिंह भी कूद पड़े और तेजस्वी को कुछ कहने की कोशिश करते दिखे। जनक सिंह के हस्तक्षेप पर तेजस्वी ने कहा कि ज्यादा जोर से बोलिएगा तो गीला हो जाइयेगा। जनक सिंह ने पलटवार किया और कहा, तुम क्या बोलेगा। हमने तुम्हारे बाप के साथ काम किया है। जनक सिंह के इतना कहते ही विपक्ष की ओर से राजद विधायक विजय सम्राट अपना स्थान छोड़कर उनकी ओर लपके। विजय सम्राट के पीछे-पीछे मुकेश यादव, सीपीएम के सत्येंद्र यादव भी उसी ओर लपके। बचाव में भाजपा के संजय सिंह, लखींद्र पासवान ने मोर्चा संभाला। इस बीच सदस्यों के संबोधन के लिए लगा माइक भी उखाड़ लिया गया। हालात ऐसे बन गए मानो बस मारपीट हो ही जाएगी। मार्शल ने दोनों पक्षों को संभाला। विधान परिषद में गुरुवार को भोजनावकाश के उपरांत मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के विरोध में काले कपड़ों में विपक्षी सदस्यों ने आसन के समक्ष हंगामा एवं नारेबाजी की। विपक्षी सदस्यों से मुख्यमंत्री नीतीश ने अपनी-अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध किया, लेकिन नहीं माने। ऐसे में मुख्यमंत्री ने परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी से भी राजद सदस्यों को वापस बुलाकर सीट पर बैठाने की अपील की।

बिहार विधानसभा परिसर में बुधवार को प्रदर्शन करते विपक्षी सदस्य। जागरण

विस घेरने निकले एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार

जासं, पटना : रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों पर पटना में विधानसभा घेराव को निकले एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान राजापुर पुल पर पुलिस एवं प्रदर्शनकारी आमने-सामने हो गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इधर, छात्र संगठन के साथ कांग्रेस के वरीय नेताओं ने पुलिस पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विफल है। इससे पूर्व एनएसयूआइ के प्रदेश अध्यक्ष सूरज सिंह यादव के नेतृत्व में सदाकत आश्रम से कार्यकर्ताओं का काफिला नारेबाजी करते रवाना हुआ।

आइएनडीआइए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतार सकता है : सूत्र

उपराष्ट्रपति चुनाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : नई दिल्ली, प्रेट्र : उपराष्ट्रपति पद के लिए सामूहिक निर्णय के बाद आइएनडीआइए एक साझा उम्मीदवार उतार सकता है। ब्लाक के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बहुमत में होने के बावजूद उसे लगता है कि संख्या बल विपक्ष के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने के लिए चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे अन्य कारणों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। 74-वर्षीय धनखड़ ने अगस्त, 2022 में पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल अगस्त, 2027 तक था।

- दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 782 और विजयी उम्मीदवार को 392 वोट हासिल करने होंगे
- लोस में एनडीए के पास 293 का समर्थन, आइएनडीआइए के पास 234

बहरहाल, दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 782 है और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 392 वोट हासिल करने होंगे, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं। लोकसभा में, जहां भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 542 सदस्यीय सदन में 293 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, वहीं आइएनडीआइए के पास 234 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में लगभग 130 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जिसकी प्रभावी संख्या 240 है। उच्च सदन में आइएनडीआइए को 79 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। प्रभावी रूप से, संसद में एनडीए के 423 सदस्य और इंडिया ब्लाक के 313 सदस्य हैं, शेष गुटनिरपेक्ष हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू : चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह जल्द ही तारीखों की घोषणा करेगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड दो के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से खाली हुए इस पद को भरने के लिए चुनाव "यथाशीघ्र" कराया जाएगा। निर्वाचित व्यक्ति "अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे पांच वर्ष की अवधि" तक इस पद पर बने रहने का हकदार होगा।

बंगाल में अगस्त से शुरू हो सकता है मतदाता सूची में संशोधन का काम

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बिहार की मतदाता सूची में संशोधन हेतु चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप नहीं करने पर बंगाल में यह प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो सकती है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय सूत्रों से यह जानकारी मिली है। मालूम हो कि बिहार की मतदाता सूची में संशोधन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, जिसपर आगामी 28 जुलाई को सुनवाई है। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया तो बंगाल में अगस्त से पहले सप्ताह से मतदाता सूची में संशोधन का काम शुरू किया जा सकता है। चूंकि सितंबर के अंत में दुर्गापूजा है इसलिए उससे पहले इस काम को पूरा करना होगा अन्यथा नवंबर अथवा दिसंबर में इसे शुरू करना पड़ेगा। सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।

'आप भी तो हाईजैक करना चाहते थे, कहां कर पाए?'

राज्य ब्यूरो, जागरण. पटना

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को याद दिलाया कि महागठबंधन के साझा सरकार के दिनों में आप (तेजस्वी) भी सरकार को हाईजैक करना चाहते थे, कहां कर पाए। तेजस्वी ने अपने भाषण के दौरान चौधरी को सलाह दी कि वे मुख्यमंत्री को बताएं कि किस तरह उन्हें भाजपा हाईजैक कर रही है। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। आपने भी प्रयास किया था। सफल नहीं हो पाए।

तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर मजाक के अंदाज में ही तीखी टिप्पणी की। कहा-लखीसराय में एक केंद्रीय मंत्री हैं, जो इन्हें चैन से जीने नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी पर लंबे कद के सम्राट चौधरी आगे खड़े हो जाते हैं। उनके पीछे विजय सिन्हा नजर नहीं आते हैं। सिन्हा ने प्रतिवाद किया। बोले-मैं दो मुख्यमंत्री का बेटा नहीं हूं। शिक्षक का बेटा हूं। जमीन पर रहता हूं। आपकी तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ हूं।

- तेजस्वी को विजय चौधरी ने याद दिलाया, कहा- शिक्षक का बेटा हूं, आपकी तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ हूं

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी को टोका-आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने कार्यकाल की किसी एक योजना का नाम बता दें, जिसकी शुरुआत आपने की है। तेजस्वी ने बाद में दामाद के बहाने अशोक चौधरी को घेरा। कहा कि एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग या नेशनल दामाद अलांयस है। कहा कि चौधरी के दामाद तो आरएसएस कोटा से मेंबर (धर्मिक न्यास पर्षद) बने हैं। पता नहीं कब से सरकार में आरएसएस कोटा लागू हो गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को एकबार बेचारा कह दिया।

हम अंदर होते तो उनका बुखार छुड़ा देते : तेजप्रताप

राज्य ब्यूरो, जागरण● पटना: राजद का आरोप है कि भाजपा विधायक जनक सिंह ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मां-बाप की गाली दी। उस संदर्भ में एक न्यूज पोर्टल ने प्रश्न किया तो परिवार-पार्टी से निष्कासित तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप अपनी रौ में आ गए। एक्स पर प्रसारित हो रहे वीडियो में तेजप्रताप कह रहे कि अंदर हम तो नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार छुड़ा देते। सभी का अस्तित्व गिर चुका है। वह भाजपा से हैं, आरएसएस और नाथूराम गोडसे वाले, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। गुंडे लोग हैं। किस तरह की छवि दिखा रहे। किसी के बाप को गाली दे देते हैं। अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा, अशोभनीय बात है। इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। जनता का मुद्दा है, जिसे संगठन ने उठाया है, उस पर गाली-गलौज कर रहे तो क्या होगा। बेकाबू ही होगा न। राजद वाले तो काला वस्त्र इसलिए पहने हैं न कि सरकार मुद्दा ही नहीं मान रही। दैनिक जागरण इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा।

बंगाल सरकार व चुनाव आयोग में सीईओ कार्यालय को लेकर टकराव

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: बंगाल सरकार व केंद्रीय चुनाव आयोग में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को लेकर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को सीईओ कार्यालय को स्वतंत्र विभाग में बदलने का निर्देश दिया है।

आयोग की ओर से बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र लिखकर कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में सीईओ कार्यालय में प्रशासनिक व आर्थिक स्वायत्तता का अभाव है। वह बंगाल सरकार के गृह विभाग के अधीन है और फंड के लिए वित्त विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिए उसे स्वतंत्र कार्यालय में बदलना जरुरी है ताकि किसी अन्य विभाग से उसका कोई संबंध न रहे और वह स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। बंगाल सरकार इसके पक्ष में नहीं है और वह इसे चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-नेशनल कान्फ्रेंस गठबंधन में बढ़ रही दूरियां

राज्य ब्यूरो, जागरण ● जम्मू

जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार में कांग्रेस को शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने इससे मना कर दिया है। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि वह दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी और राज्य का दर्जा बहाली उनके एजेंडे में सर्वोपरि है।

नेशनल कान्फ्रेंस के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस उन्हें राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर नीचा दिखा रही है। उमर अब्दुल्ला निकट भविष्य में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें वह मौजूदा मंत्रियों में से एक-दो को हटाकर नए चेहरों को शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने प्रस्तावित विस्तार में कांग्रेस का भी एक सदस्य अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का मन बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने इन्कार कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख तारिक हमीद करा ने कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वे सरकार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह उनका नया स्टैंड नहीं है, बल्कि पिछले वर्ष जब सरकार बनी थी तभी से उनका यही रुख है।

दोनों के टकराते हैं हित

कश्मीर मामलों के जानकार रशीद राही ने बताया कि कांग्रेस और नेकां के राजनीतिक हित कई जगह टकराते हैं, जिससे दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कांग्रेस के अभियान से कहीं न कहीं नेकां को नुकसान पहुंचा है, लेकिन बात यहीं तक नहीं है, कांग्रेस अपने लिए मंत्रिमंडल में एक प्रभावी पोर्टफोलियो के साथ राज्यसभा के लिए दो सीटों की आकांक्षी है।

भाषा को लेकर मारपीट की तो कड़ी कार्रवाई होगी : फडणवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में मराठी भाषा का आग्रह होना स्वाभाविक है। लेकिन भाषा को लेकर विवाद होना, किसी के साथ मारपीट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं पर हमने पहले भी कड़ी कार्रवाई की है। आगे भी कोई ऐसी घटना करने का प्रयास करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह बात गुरुवार को दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही।

देवेंद्र फडणवीस। फाइल

मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठी भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त होने के बाद देश की राजधानी में स्थित जेएनयू में मराठी शोध केंद्र की शुरुआत होना गर्व की बात है। मराठी देश की अति प्राचीन भाषा है। देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसे शोध केंद्र शुरू होने चाहिए। भाषा संवाद का माध्यम है। इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। मातृ भाषा पर सभी को अभिमान होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों का मराठी पर अभिमान करना भी स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं पर भी अभिमान होना चाहिए। फडणवीस ने हिंदी का नाम न लेते हुए कहा कि जब हम किसी भारतीय भाषा का तिरस्कार करते हैं और उसके स्थान पर सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो दुख होता है।

महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) और मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मराठी न बोल पाने पर मारपीट की घटनाओं के विरोध में गुरुवार को जेएनयू में एसएफआइ ने देवेंद्र फडणवीस के विरोध में प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा संसद भवन में महाराष्ट्र की महिला सांसदों वर्षा गायकवाड़, शोभा बच्छाव एवं प्रतिमा धानोरकर ने झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद डा. निशिकांत दुबे को घेरकर पिछले दिनों उनके द्वारा दिए गए एक बयान पर विरोध जताया। दुबे ने पिछले दिनों कहा था कि मुंबई में हिंदी भाषियों के साथ मारपीट करने वाले इधर आएंगे तो उन्हें पटक-पटक के मारेंगे।

****

बांग्ला भाषा पर ममता का एकाधिकार नहीं : मिथुन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : जाने-माने अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दूसरे राज्यों में प्रवासी बांग्लाभाषियों पर हमले के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही कहा कि बांग्ला भाषा पर ममता का एकाधिकार नहीं है। गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में मिथुन ने कहा कि देश में कहीं भी बांग्लाभाषियों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। ममता के आरोपों का उद्देश्य विवाद खड़ा करके बंगाल के लोगों में अनावश्यक दहशत फैलाना है। वह इसे लेकर राजनीति कर रही हैं। कारण, तृणमूल के पास अगले विधानसभा चुनाव से पहले कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए मुख्यमंत्री झूठा नैरेटिव गढ़कर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। यह तरीका वह पहले भी अपनाती रही हैं लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मिथुन ने कहा कि सबसे अधिक घुसपैठिये, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे बंगाल में ही हैं।

ममता बनर्जी ने कहा-अब राष्ट्रीय स्तर पर होगा आंदोलन

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अन्य राज्यों में बांग्लाभाषी प्रवासी श्रमिकों पर हमलों को लेकर गुरुवार को एक बार फिर इशारों में भाजपा व केंद्र पर निशाना साधते हुए घेरा। एक कार्यक्रम में उन्होंने बांग्ला भाषा, संस्कृति और सिनेमा की अवहेलना के खिलाफ एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना आंदोलन छेड़ने की घोषणा की।

न्यूज गैलरी

राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि केस में टली सुनवाई

सुलतानपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में चल रही मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को टल गई। भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के कारण एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तिथि निर्धारित की है। (जासं)

पिता ने डेढ़ वर्षीय बेटे को बोरवेल में फेंका

जयपुर : जयपुर में एक पिता ने अपने डेढ़ साल के बेटे को 200 फीट गहरे बोरवेल में फेंक दिया। पिता बेटे की बीमारी और पत्नी के मायके जाने से परेशान था। जमवारामगढ़ थाना अधिकारी रामपाल शर्मा के अनुसार, दीपोली गांव निवासी ललित सैनी के तीन बच्चे हैं, जिनमें से छोटा बेटा कई बीमारियों से ग्रस्त है। झगड़ा कर करीब आठ महीने पहले पत्नी के मायके जाने के बाद ललित अकेले बच्चों की देखभाल कर रहा था। बुधवार रात उसने छोटे बेटे को खुले बोरवेल में फेंक दिया। (जासं)

सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मामले में राहुल को जमानत

मुंबई : वीर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल को नासिक की एक अदालत से जमानत मिल गई है। गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरसी नरवाडिया के समक्ष वीडियो लिंक के माध्यम से पेश हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्वयं को निर्दोष बताया। नासिक निवासी देवेंद्र भुटाडा ने अपने वकील मनोज पिंगले के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत उनके विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। राहुल द्वारा स्वयं के निर्दोष होने की दलील दिए जाने के बाद उनके वकीलों ने जमानत की मांग की। वकील पिंगले ने बताया कि अदालत ने 15,000 रुपये के मुचलके पर राहुल गांधी की याचिका मंजूर कर ली है। (राब्यू)

मणिपुर में आठ उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल: सुरक्षा बलों ने इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, तेंगनौपाल और चंदेल जिलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि सभी उग्रवादी जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल थे। गिरफ्तार उग्रवादी प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (ताइबांगनबा), केसीपी (एमसी), युनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी, केसीपी (पीडब्ल्यूजी), प्रेपक और पीएलए के सदस्य हैं। (प्रेट्र)

बेंगलुरु में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

बेंगलुरु: गोविंदपुरा पुलिस ने गुरुवार को एक युवती से छेड़छाड़ और उत्पीड़न करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपित मोहम्मद मारूफ शरीफ ने महिला का उस समय पीछा किया जब वह राशन खरीदने के लिए बाहर गई थी और सार्वजनिक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार किया। गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपित का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच जारी है। (प्रेट्र)

असम राइफल्स ने तीन करोड़ रुपये की मेथ टैबलेट जब्त की

आइजल: असम राइफल्स के जवानों ने पूर्वी मिजोरम के चम्फाई जिले में तीन करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मेथामफेटामाइन की गोलियां जब्त कीं और एक म्यांमार नागरिक को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया गया कि विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर जवानों ने बुधवार को म्यांमार सीमा के पास जिले के जोटे गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान टीम ने म्यांमार के नागरिक के कब्जे से 3.03 करोड़ की 1.11 किलो मेथामफेटामाइन गोलियां बरामद कीं। (प्रेट्र)

ठेले वाले को पीटा, दारोगा-सिपाही लाइन हाजिर

हमीरपुर : दारोगा और सिपाही ने हाथठेले पर 10 रुपये के गोलगप्पे खाए। ठेला लगाए युवक ने पैसे मांगे तो उसे धमकाया और पीटा। ठेले वाले ने सीओ कार्यालय में शिकायत कर दी। जांच के बाद बुधवार को एसपी डा. दीक्षा शर्मा ने आरोपित दारोगा शिवमदत्त और सिपाही अमित कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। मामला उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र का है। औंता गांव निवासी शिवा ने बताया कि वह अपने गांव में गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। सोमवार को दारोगा शिवमदत्त और सिपाही अमित कुमार आए और पांच-पांच रुपये के गोलगप्पे खाए। जब गोलगप्पे के दस रुपये मांगे तो दारोगा और सिपाही ने गाली-गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से उनके चेहरे में सूजन है और कान में भी दर्द है। सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि जांच में आरोप सही मिले थे। (जासं)

भागवत की इमामों के साथ बैठक से निकला संदेश-दूरियां घटाएं, लड़ें नहीं हिंदू-मुस्लिम

हरियाणा भवन में साढ़े तीन घंटे चली बैठक में 60 इमाम, मुफ्ती व मोहतमिम शामिल हुए

मंदिरों-मस्जिदों और गुरुकुल-मदरसों के बीच की दूरियां घटाने पर जोर

नेमिष हेमंत ● जागरण

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र के बीच बड़े घटनाक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इमामों के साथ गुरुवार को बड़ी बैठक की। हरियाणा भवन में साढ़े तीन घंटे चली बैठक में 60 इमाम, मुफ्ती व मोहतमिम शामिल हुए। बैठक का आयोजन अखिल भारतीय इमाम संगठन (एआइआइओ) द्वारा किया गया। बंद कांफ्रेंस रूम में हुई बैठक में खुलकर संवाद हुआ। इस दौरान अवरोध के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के साथ जोर देश को विश्व गुरु बनने की राह में बड़ा रोड़ा हिंदू-मुस्लिमों के बीच दूरियों को पाटने पर रहा। बैठक में शामिल लोगों ने इसे शानदार पहल बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ इमाम के

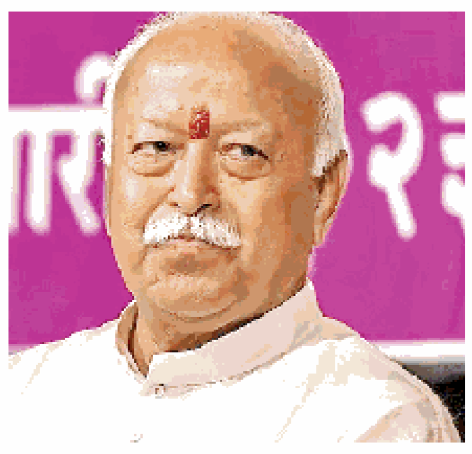
मोहन भागवत। फाइल

अनुसार, सवाल उठा कि कैसे मंदिर-मस्जिद के बीच की दूरियां घटें? कैसे गुरुकुल और मदरसों के छात्रों का आपसी संवाद बढ़े? संवाद से ही समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है। कैसे इस संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए देशभर में लेकर जाया जाए? कैसे विभाजन का करण बने 'हिंदू-मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते' कि धारणा को बदला जाए। कैसे, हिंदू-मुस्लिम से ऊपर सबकी एक पहचान भारतीय बने?

संवाद के कार्यक्रम जारी रखने पर बनी सहमति : बैठक में शामिल एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, तय हुआ कि संवाद के ये कार्यक्रम मुस्लिम बहुल इलाकों में नीचे तक भी जाएं, अलग-अलग ढंग से संवाद की यह प्रक्रिया जारी रहे और आपसी मतभेदों को पाटा जाए। इसमें लंबा वक्त लगेगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इस प्रक्रिया में सुननी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी।

बैठक में आम राय बनी कि हम सब विदेशी नहीं हैं, आक्रमणकारियों की पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। अब उस विचार से बाहर निकलना होगा। हम सभी भारत की संतान हैं। हम जब एक होंगे तब भारत मजबूत होगा और विश्व गुरु बनेगा। बैठक में एआइआइओ के अध्यक्ष डा. इमाम उमेर अहमद इलियासी, संघ के सहसरकार्यवाह डा. कृष्ण गोपाल व अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल तथा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार की विशेष मौजूदगी रही।

एक-दूसरे को समझने पर रहा जोर : बैठक में शामिल एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संघ प्रमुख ने जोर देकर कहा कि एक-दूसरे को नजदीक आना होगा और समझना होगा।

इसी तरह संघ के शांति व संवाद की प्रक्रिया को समझने के लिए आपस में नजदीकी बढ़ानी होगी। यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है, जब संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस क्रम में धर्म, पंथ व विचारधारा से ऊपर सभी को भारतीय के तौर पर जोड़ने को लेकर गृह संपर्क अभियान चलाने वाला है। इसी तरह, एआइइओ के भी 50 वर्ष तथा संघ प्रेरणा से हिंदू-मुस्लिम सद्भाव पर काम कर रही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना के 25 वर्ष हो गए हैं।

पहले भी हो चुका है संवाद

मुस्लिम समाज से मोहन भागवत की संवाद की यह प्रक्रिया नई नहीं है। वर्ष 2016 और 2022 में भी इसी तरह मुस्लिम बुद्धिजिवियों के साथ उनकी बैठक हरियाणा भवन में हुई थी। वर्ष 2022 में उमेर अहमद इलियासी के बुलावे पर संघ प्रमुख जनपथ रोड स्थित मस्जिद तथा आजाद मार्केट के मदरसे में भी गए थे।

दलों में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने को याचिका

- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पार्टियों से यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून का पालन करने की मांग
- 2013 के अधिनियम और विशाखा मामले में ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रविधानों का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि राजनीतिक दल 2013 के अधिनियम के दायरे में आते हैं, इसलिए वे इसमें उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। याचिका में कहा गया है कि 2024 में याचिकाकर्ता वकील योगमाया एमजी ने सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसने उन्हें सक्षम प्राधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता दी थी।

याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग को एक प्रतिवेदन भेजा था, लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष योगमाया ने राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उससे निपटने के लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह ठहराने के निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने के लिए 2013 के अधिनियम और विशाखा मामले में ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वकील श्रीराम पी. के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, ''यह रिट याचिका कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सुरक्षा के दायरे से महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बाहर रखने को चुनौती देती है।'' याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के प्रगतिशील उद्देश्य के बावजूद, महिला राजनीतिक कार्यकर्ता, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार और पार्टी कार्य के दौरान यौन शोषण की चपेट में रहती हैं। ''संयुक्त राष्ट्र महिला (2013) और अंतर-संसदीय संघ (2016) द्वारा किए गए अध्ययनों का हवाला देते हुए, जो राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के व्यापक मनोवैज्ञानिक और यौन उत्पीड़न को उजागर करते हैं, याचिका में यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत ऐसे कार्यकर्ताओं के समावेश और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।''

चंडीगढ़ व आसपास के फर्जी काल सेंटरों पर ईडी के छापे

- विदेशी नागरिकों से टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश
- बगैर लाइसेंस चल रही थीं कंपनियां, प्रमोटर, निदेशक व कर्मियों का रिकार्ड नहीं

जागरण संवाददाता, ● चंडीगढ़

ईडी ने बुधवार रात चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में कई फर्जी काल सेंटरों पर छापेमारी की। ये काल सेंटर विदेशी ग्राहकों को टेक्निकल सपोर्ट देने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। ये कंपनियां वेबसाइटों पर वेब डिजाइनिंग, वायरलेस इंटरनेट सेवाएं और अन्य साफ्टवेयर सेवाओं का झूठा प्रचार कर रही थीं। इन कंपनियों के प्रमोटर, निदेशकों और कर्मचारियों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। फर्जी कंपनियों ने विदेश में भी अपनी इकाइयां खोली थीं, ताकि अवैध रूप से कमाए गए पैसे को पेमेंट गेटवे के माध्यम से भारत लाया जा सके। इन फंड को हवाला के जरिए देश में भेजा जाता था। काल सेंटरों में काम कर रहे कर्मचारी तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे।

ईडी की कार्रवाई में जीरकपुर स्थित एफएसएएल टेक्नोलाजी के खिलाफ गंभीर साक्ष्य मिले हैं। यह कंपनी अमेरिका स्थित एक फर्जी इकाई "बायोस टेक" के माध्यम से माइक्रोसाफ्ट, एचपी, अर्लो जैसे ब्रांड्स के नाम पर टेक्निकल सपोर्ट देने का दावा कर रही थी, जबकि इसके पास ऐसे किसी काम का लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा एफएसएएल टेक्नोलाजी पर आरोप है कि यह अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी "गीक स्क्वाड" की नकल कर बनाई गई एक जाली वेबसाइट थी।

इस पूरे नेटवर्क के पीछे कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बरामद दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और काल रिकार्डिंग्स का विश्लेषण जारी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस फ्राड के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी की गई है।

कंबोडिया में साइबर ठगी, पकड़े गए 3000 में 105 भारतीय

- कंबोडिया से ठगी करने वाली खुशबू दिल्ली एयरपोर्ट से की गई थी गिरफ्तार
- सूरत की रहने वाली खुशबू दो साल से साइबर ठगों के लिए कर रही थी काम

विनय त्रिवेदी ● जागरण

गुरुग्राम : कंबोडिया में साइबर ठगी के मामलों में हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। यह कार्रवाई भारतीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की गुजारिश पर कंबोडिया सरकार ने की है।

गुरुग्राम साइबर पुलिस ने 25 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट से खुशबू नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया था, जो कंबोडिया के नोम पेन्ह स्थित एक काल सेंटर में काम कर रही थी। गुजरात के सूरत की रहने वाली खुशबू करीब दो साल से साइबर ठगी में लिप्त थी। गुरुग्राम में रहने वाली एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से करीब तीन करोड़ की ठगी के मामले की जांच करते हुए बैंक खाता धारक समेत कुल 16 लोगों को पकड़ा गया था। अंतिम पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में बताया था कि उसने बैंक खाता दुबई में रहने वाले अपने भाई के माध्यम से खुशबू को बेचा था। खुशबू से पूछताछ में पता चला

एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान।

था कि नोम पेन्ह में सैकड़ों काल सेंटर हैं, जहां भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के दस हजार से ज्यादा लोग ठगी कर रहे हैं। काल सेंटरों में तीन लेयर में काम होता है। पहली लेयर में बैठे लोग फोन करने और दूसरे व तीसरे लेयर में बैठे लोग ठगी की वारदात करते हैं। खुशबू पहले लेयर में काम करती थी। पांच दिन की पूछताछ के बाद गुरुग्राम साइबर पुलिस ने ये जानकारी गृह मंत्रालय से पत्राचार कर साझा की थी।

गुरुग्राम साइबर पुलिस के एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि यह पहली बार है जब विदेश से साइबर ठगी के मामले में किसी सक्रिय कालर को पकड़ा गया है। भारतीय सरकार को इस बात की चिंता थी कि हर साल भारतीय नागरिकों के साथ हजारों करोड़ रुपये की ठगी हो रही है। कंबोडिया में कार्रवाई के बाद भारतीय गृह मंत्रालय जल्द ही गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी साझा करेगा।

अंतरराष्ट्रीय ठग संग बनाई शेल कंपनियां, विदेश में 10 बैंक खाते

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अवैध दूतावास मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन आम ठग नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले फर्जीवाड़े के नेटवर्क का अहम चेहरा है। तुर्किए की नागरिकता लेकर लंदन में बैठा एहसान अली सैयद और हर्षवर्धन जैन मिलकर वर्षों से अलग-अलग देशों में शेल कंपनियों की आड़ में करोड़ों की ठगी कर रहे थे। एसटीएफ को हर्षवर्धन के विदेश में 10 बैंक खातों की जानकारी मिली है। एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को आरोपित की कस्टडी के लिए कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया जाएगा। एसटीएफ ने हर्षवर्धन को माइक्रोनेशन (स्वयंभू देश) के अवैध दूतावास और हवाला कारोबार के आरोप में मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया था। हर्षवर्धन से पूछताछ और दस्तावेज खंगालने के बाद एसटीएफ को पता चला कि तांत्रिक चंद्रास्वामी ने उसकी मुलाकात सऊदी अरब के आर्म्स डीलर अदनान खशोगी और हैदराबाद के एहसान अली सैयद से लंदन में रहने के दौरान कराई थी। एहसान के साथ हर्षवर्धन ने विदेश में कई कंपनियों को पंजीकृत कराया। इनमें इंग्लैंड में स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन एलटीडी, ईस्ट इंडिया कंपनी यूके एलटीडी तथा यूएई आइलैंड जनरल ट्रेडिंग, मारीशस में इंदिरा ओवरसीज एलटीडी, अफ्रीकी देश कैमरून में कैमरो इस्पात का पंजीकृत होने की जानकारी मिली है।

वाड्रा के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में नोटिस को लेकर 31 को आ सकता है आदेश

- गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में विशेष अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा
- ईडी ने दी दलील, झूठे दस्तावेजों से जमीन खरीदी और ऊपरी दबाव से लिया गया लाइसेंस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद व कारोबारी राबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी करने के बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने ईडी की प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद कहा कि वह दस्तावेज की जांच के बाद 31 जुलाई को नोटिस जारी करने या नहीं करने को लेकर आदेश पारित करेंगे।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने दलील दी कि यह एक स्पष्ट और क्लासिक मनी लांड्रिंग मामला है, जिसमें अपराध से अर्जित धन और झूठे दस्तावेजों से कई संपत्तियां (जमीन) खरीदी गईं। ईडी ने दलील दी कि स्काइलाइट ने वाणिज्यिक आवासीय विकास के लिए लाइसेंस ऊपरी दबाव के जरिये प्राप्त किया। लाइसेंस के लिए फाइलें जल्दबाजी में तैयार की गईं और कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच नहीं की गई।

ईडी ने दलील दी कि स्काइलाइट हास्पिटैलिटी कंपनी, जिसकी 99 प्रतिशत हिस्सेदारी राबर्ट वाड्रा के पास थी, ने 7.5 करोड़ रुपये में 3.53 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन चेक द्वारा दिखाई गई इस राशि का कभी भुगतान नहीं किया गया। यह जमीन बाद में डीएलएफ को ऊंचे दामों में बेची गई। ईडी ने दलील दी कि जांच में सामने आया कि जमीन के विक्रेता ओंकारेश्वर प्रापर्टीज के निदेशक सत्यानंद यादव ने इस लेनदेन में वाड्रा की कंपनी को जानबूझकर मदद दी।

धारा 70 के तहत वाड्रा को ठहराया जिम्मेदार : ईडी ने कहा कि यह अपराध जारी है क्योंकि इन संपत्तियों का उपयोग जुलाई 2025 तक होता रहा, जब तक लगभग 37.64 करोड़ रुपये की 43 संपत्तियों को अटैच नहीं कर लिया गया। ये सभी संपत्तियां वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी हैं। ईडी ने पीएमएलए की धारा 70 के तहत वाड्रा को व्यक्तिगत रूप से और कंपनियों के हिस्सेदार व लाभार्थी मालिक के रूप में जिम्मेदार ठहराया है। ईडी ने दलील दी कि मामला भले ही हरियाणा से जुड़ा हो, लेकिन दिल्ली में अपराध की प्रक्रिया हुई है, इसलिए अदालत को अधिकार प्राप्त है।

यह है मामला : यह मामला वर्ष 2008 में गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव में जमीन खरीद से जुड़ा है, जिसे राबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। ईडी ने 17 जुलाई 2025 को दाखिल अपनी शिकायत में वाड्रा, उनकी कंपनी स्काइलाइट हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सत्यानंद यादव, केवल सिंह वीरक समेत 11 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपित बनाया है।

कार्यकर्ताओं पर मुकदमे के विरोध में थाने में धरने पर बैठीं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला

- एसपी के आश्वासन के बाद सवा नौ बजे समाप्त हुआ साढ़े छह घंटे से जारी धरना
- राज्यमंत्री ने कहा-कोतवाल व चौकी इंचार्ज न हटाए गए तो आज फिर धरने पर बैठेंगे
- डीएम-एसपी समेत अन्य अधिकारियों के समझाने के बाद भी रात सवा नौ बजे मामला सुलझ सका

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात

अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बदलापुर गांव में सड़क निर्माण को लेकर उपजा विवाद गुरुवार को गर्मा गया। कार्यकर्ताओं पर हुए एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे के विरोध में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला गुरुवार दोपहर पौने तीन बजे अकबरपुर थाने में धरने पर बैठ गईं।

उन्होंने कोतवाल व चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की। देर शाम उनके पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी भी आ गए और धरने पर बैठ गए।

डीएम-एसपी समेत अन्य अधिकारियों के समझाने के बाद भी रात सवा नौ बजे मामला सुलझ सका। एसपी अरविंद मिश्र ने कहा कि जांच कर शुक्रवार सुबह तक निर्णय ले लेंगे। आश्वासन पर मंत्री मानीं और कहा कि मांग पूरी न होने पर शुक्रवार को फिर धरने पर बैठेंगी।

बदलापुर में करीब 25 वर्षों से बदहाल पड़ी सड़क का निर्माण विधायक निधि से कराया जा रहा है। दो दिन पूर्व सभासद शमसाद ने काम रुकवा दिया। इसके बाद सभासद पर सरकारी कार्य में बाधा डालने व रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

गुरुवार को सभासद के समर्थक बाबूराम गौतम ने राज्यमंत्री के समर्थकों अबरार, मो. यूसुफ, असलम, यासिर व शिवा पांडेय पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप लगाया कि आपस में चर्चा होने पर उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्हें जातिसूचक शब्द कहे गए।

कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे के विरोध में गुरुवार दोपहर करीब 2:45 बजे राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर थाने पहुंच गईं। कोतवाल सतीश सिंह व लालपुर चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग को लेकर थाने के मुख्यद्वार पर करीब 70-80 कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गईं। दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब एएसपी राजेश पांडेय थाने पहुंचे। आधे घंटे बाद एसपी अरविंद मिश्रा भी पहुंच गए।

उन्होंने राज्यमंत्री से कार्यालय में बैठकर वार्ता करने की बात कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जो भी बात करनी है, यहीं करें। हम शांतिप्रिय लोग हैं, आप कोतवाल व चौकी इंचार्ज को हटा दें, हम शांति से वापस चले जाएंगे। डीएम आलोक कुमार सिंह भी आए, लेकिन बात नहीं बन सकी। रात सवा नौ बजे एसपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ।

कर्नाटक में नाबालिगों की सगाई भी माना जाएगा दंडनीय अपराध

- कर्नाटक कैबिनेट ने बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2025 को दी मंजूरी
- विधेयक विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा

बेंगलुरु, प्रेट्र: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए गुरुवार को बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जिसमें नाबालिगों की सगाई को भी दंडनीय अपराध बनाने का प्रविधान है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और विधेयक विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यह विधेयक एक कड़ा संदेश देता है कि न केवल बाल विवाह, बल्कि नाबालिग से सगाई करना भी अस्वीकार्य है और इसके कानूनी परिणाम होंगे। हमने सामाजिक स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तन लाए हैं, जो लोग कानूनी कार्रवाई से बच रहे थे, वे अब बच नहीं सकते। बाल विवाह रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि 2023-24 के दौरान राज्य में लगभग 700 बाल विवाह की सूचना मिली थी।

यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया है, जिसमें जिलों के उपायुक्तों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे।

'जो 27 वर्षों तक चुप रहा, उसे न्याय मांगने का अधिकार नहीं'

- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- साझेदारी विलेख की वैधता पर कोई फैसला नहीं, कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेसर्स ला पब्लिशर्स नामक प्रतिष्ठित कानूनी प्रकाशन व्यवसाय को लेकर चल रहे पारिवारिक समझौता विवाद में दायर अपील खारिज कर दी है। अपील में अंतरिम व्यादेश (ऐसा आदेश, जो किसी व्यक्ति/संस्था को कुछ करने या न करने का निर्देश दे) जारी करने की मांग की गई थी। इसे कोर्ट ने 27 वर्षों की अनुचित चुप्पी और देरी के आधार पर अस्वीकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा, 'अपीलकर्ता स्मृति 'स्लीपिंग पार्टनर' के रूप में स्वयं को दर्शाने में असफल रहीं और उनकी याचिका में न तो प्रथमदृष्टया बल था, न ही संतुलन का आधार और ना ही किसी अपूरणीय क्षति की संभावना थी।' कोर्ट ने कहा, 'अपीलकर्ता अपने अधिकारों को लेकर दशकों तक मौन रहीं और अब अचानक उत्पन्न हुई उनकी मांग को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।'

इलाहाबाद हाई कोर्ट। फाइल

मामला पारिवारिक व्यापार में हिस्सेदारी संबंधी दावे का है। मुख्य अपीलकर्ता विभा सागर ने दावा किया था कि वह 1976 से मेसर्स ला पब्लिशर्स की साझेदार हैं। उनके पारिवारिक सहयोगी, जिनमें वीरेंद्र सागर और उनके स्वजन हैं, प्रयागराज की बहुमूल्य अचल संपत्तियों को उनकी अनुमति बिना स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत अंतरिम राहत की मांग की थी। किराये की आय को कोर्ट में जमा कराने और संपत्ति के स्थानांतरण पर रोक की प्रार्थना की गई थी।

निचली वाणिज्यिक अदालत में याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने धारा 37 के तहत हाई कोर्ट में अपील की थी। एडवोकेट प्रियंका मिधा, अभिषेक घोष और राम कौशिक मुख्य अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए। तर्क दिया कि उनकी मुवक्किल साझेदारी से कभी नहीं हटीं और 1996 का साझेदारी विलेख अब भी लागू है। उनके नाम पर किसी भी सेवानिवृत्ति की सूचना, लेखा-जोखा निपटान, या किसी प्रकार का अधिकार-त्याग दस्तावेज रिकार्ड में नहीं है। उन्होंने साझेदारी कानून की धारा 32 (ग) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 112 का हवाला दिया।

माब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को माब लिंचिंग से जुड़े मामलों में तहसीन पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हर घटना अलग है, इसे जनहित याचिका में उठाना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि माब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार के लिए भी बाध्यकारी हैं। इस याचिका की मांग वही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जारी दिशा-निर्देश हैं। कोर्ट ने जमीयत उलमा ए हिंद (अरशद मदनी) की आपराधिक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया है। जमीयत उलमा ए हिंद ने अलीगढ़ में 24 मई, 2025 को हुई माब लिंचिंग की घटना की जांच के लिए एसआइटी गठित करने या स्वतंत्र व निष्पक्ष एजेंसी से विवेचना कराने का समादेश जारी करने की मांग की थी।

****

15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए बंगाल के तीन जिलों में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। मरने वाले सभी खेतों में काम कर रहे थे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 25 जुलाई, 2025

उप्र के चार शहरों की युवतियों समेत एक दर्जन का मतांतरण स्वीकारा

आपरेशन अस्मिता ▸ जेल भेजे सरगना के बेटों से पूछताछ में पर्दाफाश, पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा

दिखाए जाते थे भगोड़े जाकिर नाइक, कलीम सिद्दीकी और पाकिस्तान के वीडियो

जागरण संवाददाता, आगरा

सात राज्यों में नेटवर्क स्थापित कर चुका अवैध मतांतरण गिरोह आगरा के अलावा प्रदेश के चार शहरों की युवतियों समेत एक दर्जन से ज्यादा का मतांतरण करा चुका है। सरगना पिता अब्दुल रहमान के साथ काम करने वाले बेटे अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं। युवतियों को भगोड़े धर्मगुरु जाकिर नाइक, कलीम सिद्दीकी और पाकिस्तान के धार्मिक वीडियो दिखाए जाते थे। 24 घंटे तक पूछताछ के बाद सरगना अब्दुल रहमान के दोनों बेटों और हरियाणा की युवती से जबरन निकाह करने वाले जुनैद कुरैशी को पुलिस ने जेल भेज दिया।

तीनों आरोपितों ने बताया कि वे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवतियों को अपने प्रेमजाल में फंसाते थे। इसके बाद युवतियों को दिल्ली बुलाया जाता था। वहां शाहीन बाग या अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित घर पर बड़ी स्क्रीन पर जाकिर नाइक, सामूहिक मतांतरण में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कलीम सिद्दीकी और कुछ पाकिस्तानी धार्मिक वीडियो दिखाकर ब्रेनवाश कराया जाता। एक बार में दो-दो घंटे तक वीडियो दिखाए जाते थे। युवतियों के मतांतरण के बाद उन्हें कोलकाता भेज दिया जाता था। वहां गिरोह के अन्य सदस्य उनके रहने खाने-पीने और काम की व्यवस्था करते थे। तीनों आरोपितों ने महाराष्ट्र, मप्र, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली और गाजियाबाद की दर्जनभर युवतियों के जबरन मतांतरण की बात भी स्वीकारी है।

सरगना से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि उसको लंदन और कनाडा से मतांतरण के लिए फंडिंग की जा रही थी। बैंक खातों से इसके सुराग मिले हैं। रहमान के खातों में ही 50 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। हवाला के माध्यम से भी बड़ी रकम दूसरे देशों से अब्दुल रहमान को भेजी जा रही थी। अब्दुल रहमान इस रकम को गिरोह का वित्तीय प्रबंधन देख रही गोवा की आयशा के खाते में भेजता था। इसमें से पांच से 10 हजार रुपये तक के ट्रांजेक्शन गूगल पे के माध्यम से भी किए गए हैं। आयशा मतांतरित युवक और युवतियों को आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करती थी। पुलिस की टीमें अब अब्दुल रहमान और आयशा के बैंक खातों से मिली जानकारी के आधार पर फंडिंग करने वालों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

अब्दुल्ला को तैयार कर रहा था सरगना

सरगना अब्दुल रहमान अपनी विरासत छोटे बेटे अब्दुल्ला को सौंपना चाहता था। उसे कई जमातों में भी भेजा गया। वहीं, बड़ा बेटा अब्दुल रहीम कंप्यूटर का जानकार है। वह गिरोह का फंड मैनेजमेंट संभालने वाली आयशा के संपर्क में रहता था।

आगरा: गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर में मतांतरण के आरोपितों को सीजेएम की अदालत में पेश करने के लिए लेकर जाती पुलिस। जागरण

एटीएस को छांगुर के नौ गुर्गों की तलाश

मतांतरण का मास्टरमाइंड

अमित श्रीवास्तव • जागरण

▸ 18 नामजदों में से आठ आरोपित हो चुके गिरफ्तार, एक की हो चुकी है मौत

बलरामपुर : हिंदू युवतियों को मतांतरित कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अपने सात गुर्गों के साथ जेल में है, लेकिन एटीएस की एफआइआर में शामिल नौ अन्य लोग अभी पकड़ से दूर हैं। इसमें नागपुर, महाराष्ट्र का ईदुल इस्लाम, पिंकी, हाजिरा, शंकर, सगीर शामिल हैं। एटीएस की एफआइआर में 18 लोगों के नाम है, जिनमें से गोंडा निवासी रहमान की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ एटीएस और ईडी ने छांगुर, नीतू और नवीन आदि के 22 खातों में मिले 60 करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ फंडिंग के अन्य स्रोत का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

ईदुल इस्लाम खुद को भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ का महासचिव बताता है। उसने छांगुर को इसी संस्था का अवध प्रांत का प्रमुख नियुक्त करके 2023 में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डीआइजी देवीपाटन मंडल को उसकी प्रति भेजी थी। इसके एटीएस के हाथ लगने पर भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ की सच्चाई का भी पता चलेगा। इससे छांगुर के मुंबई समेत दुबई के नेटवर्क का भी पता चलेगा। महाराष्ट्र में ईदुल इस्लाम ही छांगुर के काले साम्राज्य को हैंडल करता था। महाराष्ट्र में छांगुर के कितने गुर्गे छिपे हैं, यह राज ईदुल इस्लाम ही खोलेगा। इसीलिए एटीएस की एक टीम उसकी तलाश में जुटी है।

बताते हैं कि छांगुर की कोठी से जो डायरी एटीएस की टीम के हाथ लगी है, उसमें एक पूर्व विधायक को भी छांगुर ने बड़ी रकम दी थी। इसी का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां छांगुर, नीतू और नवीन के बैंक खातों का डाटा एकत्र कर रही हैं।

इनकी हो चुकी गिरफ्तारी

जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन, छांगुर के बेटे महबूब, भतीजे सबरोज, शहाबुद्दीन, कोर्ट कर्मी राजेश उपाध्याय व रसीद को एटीएस ने गिरफ्तार कर चुकी है। नामजदों में से गोंडा के रेतवागाड़ा के रमजान की मौत हो चुकी है। बाकी फरार चल रहे हैं।

छांगुर के गुर्गे पर केस, इंस्पेक्टर की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, मेरठ : हिंदू युवतियों का मतांतरण कराने के बाद सुर्खियों में आए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के लिए बदर अख्तर सिद्दीकी भी लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाता था। छह साल पहले उसने आशा नेगी को प्रेमजाल में फंसाया था, तब से आशा का कोई पता नहीं है। उस समय स्वजन ने बदर पर अपहरण और मतांतरण कराने का आरोप लगाया था। सिविल लाइंस थाने के तत्कालीन प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। छांगुर गिरोह के मामले उजागर होने पर आशा के परिवार ने दोबारा से बदर के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बदर ने 2019 में प्रिया त्यागी को प्रेमजाल में फंसाकर अगवा किया। इसका मुकदमा भी दर्ज है। छांगुर के पकड़े जाने के बाद एटीएस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि इसी बीच आशा नेगी का मामला सामने आ गया। 2009 में मेरठ के एक काल सेंटर में आशा नौकरी करती थी। भाई अनिल नेगी ने बताया कि आशा का बीमा होना था। इसके लिए एलआइसी एजेंट महमूद अख्तर सिद्दीकी ने जरूरी कागजात लिए थे। इसके बाद से महमूद के बेटे बदर का फोन आशा पर आने लगा। दोनों में बातचीत होने लगी।

रोहित बनकर हिंदू युवती से शादी करने वाले नईम को 20 साल की कैद

जागरण संवाददाता, अमरोहा : रोहित बनकर हिंदू युवती से शादी और दुष्कर्म करने वाले नईम को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 86,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नईम ने खुद को क्राइम ब्रांच में दारोगा बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया और शादी कर ली। युवती ने उसके परिवार से मिलने की बात कही तो वह भाग निकला। वर्तमान में नईम रिश्ते की भांजी से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है।

उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले के गजरौला की हिंदू युवती से नईम की 2021 में मुलाकात हुई। उसने अपना नाम रोहित चौधरी और खुद को दारोगा बताया। युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। शादी को लेकर वह टालमटोल करने लगा। युवती के दबाव बनाने पर उसने 18 मार्च 2022 को गजरौला में किराये के मकान में शादी की। युवती ने अपने परिवार से मिलाने के लिए कहा तो नईम ने माता-पिता की मौत का बहाना बनाया। दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। अप्रैल 2022 में नईम ने अपने प्रमोशन की बात कहकर युवती से दो लाख रुपये लिए।

इस बीच युवती को उसके मुस्लिम होने और दारोगा नहीं होने की जानकारी मिली। इसके बाद दोनों में विवाद होने लगा। 30 अप्रैल 2022 को जब युवती ने उसके घर चलने के लिए कहा तो नईम टैक्सी लाने का बहाना बनाकर चला गया। फिर नहीं लौटा।

'हाईकोर्ट व जिला न्यायपालिका में सामंत व गुलाम जैसे रिश्ते'

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर

▸ मप्र हाई कोर्ट की टिप्पणी, बर्खास्त जज की पेंशन बहाल करने के निर्देश

▸ जिला न्यायालय के जज हाई कोर्ट जजों से मिलते हैं तो उनकी बाडी लैंग्वेज बिना रीढ़ की हड्डी वाली स्तनधारी की जैसी होती है

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल शामिल हैं, ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के बीच सामंत और गुलाम जैसे रिश्ते हैं। युगल पीठ ने यह भी कहा कि जब जिला न्यायपालिका के जज हाई कोर्ट के जजों से मिलते हैं तो उनकी बाडी लैंग्वेज बिना रीढ़ की हड्डी वाली स्तनधारी की तरह होती है। हाई कोर्ट के जज खुद को सवर्ण और जिला न्यायालय के जजों को शूद्र समझते हैं।

दरअसल, व्यापमं मामले में आरोपित को जमानत देने के कारण हाई कोर्ट ने संबंधित जज को बर्खास्त कर दिया था। युगल पीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य से जिला न्यायपालिका में यह संदेश जाता है कि बड़े मामलों में निर्दोष साबित करने या जमानत देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

कोर्ट ने बर्खास्त किए गए न्यायाधीश को बैकवेजेस के साथ पेंशन का भुगतान करने और उन्हें पांच लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए।

यह याचिका 2016 में एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश जगत मोहन चतुर्वेदी द्वारा दायर की गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2015 में व्यापमं मामले के कुछ छात्रों को अग्रिम जमानत दी, जबकि अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इस पर हाई कोर्ट प्रशासन ने उनके खिलाफ कदाचरण की कार्रवाई की और उन्हें बर्खास्त कर दिया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि जिला न्यायपालिका को दंड के भय में रखा जाता है। सुनवाई के दौरान उन्होंने हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका के बीच निराशाजनक संबंध की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि एक अहंकारी उच्च न्यायालय छोटी-छोटी गलतियों के लिए जिला न्यायपालिका को फटकारता है, जिससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जाति व्यवस्था की छाया न्यायिक ढांचे में स्पष्ट दिखाई देती है। इससे जिला न्यायपालिका मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है, जो अंततः उनके न्यायिक कार्यों में परिलक्षित होती है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। फाइल

पेपर लीक करना हत्या से भी गंभीर कृत्य : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट ने परीक्षा नियंत्रक सहित तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना है और यह कृत्य हत्या से भी गंभीर है। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की कि यह मामला बाड़ द्वारा फसल खाने के समान है। यह घोटाला सीजीपीएससी 2020 परीक्षा से संबंधित है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक कर डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनों को चयनित किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने अपने भतीजों नितेश और साहिल सोनवानी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर के माध्यम से उद्योगपति श्रवण गोयल तक पहुंची, जिन्होंने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को यह पेपर दिलवाया। भाजपा नेता ननकीराम कंवर की याचिका में कहा गया कि इस परीक्षा में कई नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को अनुचित लाभ देकर चयनित किया गया। हाई कोर्ट ने भी यह टिप्पणी की कि एक साथ इतने रिश्तेदारों का चयन संयोग नहीं हो सकता।

मंडी में बस खाई में गिरी, आठ की मौत

जागरण संवाददाता, मंडी : बाढ़-भूस्खलन की मार झेल रहे मंडी जिले में लगातार वर्षा अब सड़क हादसों का कारण भी बनने लगी है। वर्षा से सड़कों के किनारे बनी सुरक्षा दीवार भी कमजोर हो गई है। सरकाघाट उपमंडल के मसेरन के तारंगला में वीरवार सुबह करीब नौ बजे सुरक्षा दीवार धंसने के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस 75 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई व 21 घायल हुए हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।

सरकाघाट डिपो की बस (एचपी-28ए-3717) सरकाघाट से दुर्गापुर जा रही थी। इसमें 29 लोग सवार थे। तारंगला के पास कार को पास देने के लिए चालक ने बस जैसे ही सड़क से बाहर निकाली, सुरक्षा दीवार धंस गई। इससे बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। यात्रियों की चीख-पुकार सुन लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर सभी घायलों को एंबुलेंस व निजी वाहनों से नागरिक अस्पताल सरकाघाट पहुंचाया।

श्री अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा-अर्चना

▸ हर-हर महादेव से गूंज उठा पूरा वातावरण

▸ जम्मू-कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई

शिवलिंग का जलाभिषेक करते महंत दीपेंद्र गिरि। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

श्री अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक को श्रावण अमावस्या के अवसर पर गुरुवार को श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के लिए ले जाया गया। गोपाद्री पर्वत पर स्थित इस मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, और वातावरण हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। हर वर्ष श्रावण अमावस्या के दिन पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा की जाती है। सुबह दशनामी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरि ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान शिव की पूजा की और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा लौटाया गया। महंत ने बताया कि छड़ी मुबारक को लाल चौक के पास दशनामी अखाड़ा से मंदिर लाया गया, जहां पूजा सम्पन्न हुई।

शुक्रवार को छड़ी मुबारक को हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर ले जाया जाएगा। रविवार को श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना की रस्म होगी, और मंगलवार को नाग पंचमी के अवसर पर अखाड़े में छड़ी पूजन किया जाएगा।

महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव में 1.5 लाख 'गोविंदाओं' का होगा बीमा

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले 1.5 लाख 'गोविंदाओं' के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है, जिसके तहत मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह कदम दही हांडी उत्सव से एक महीने से भी कम समय पहले उठाया गया है। दही हांडी उत्सव में, 'गोविंदा' उन युवकों या पुरुषों के समूह को कहा जाता है जो एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं और दूध, दही तथा मक्खन से भरी हांडी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। बीमा पैकेज में मानव पिरामिड बनाने के दौरान चोट लगने पर भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार इस वर्ष 16 अगस्त को मनाए जाने वाले इस उत्सव के दौरान मानव पिरामिड बनाने वाले पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए बीमा खर्च वहन करेगी। महाराष्ट्र राज्य गोविंदा एसोसिएशन, मुंबई को 'गोविंदाओं' के प्रशिक्षण, आयु और भागीदारी का सत्यापन करने तथा उनका विवरण पुणे में खेल एवं युवा सेवा आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया है।

बीएसएफ ने अमृतसर व तरनतारन में मार गिराए छह पाकिस्तानी ड्रोन

जागरण संवाददाता, अमृतसर

▸ बुधवार रात और गुरुवार सुबह की गई कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज किया केस

▸ चार पिस्तौल, छह मैगजीन और एक किलो हेरोइन बरामद

पंजाब सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बुधवार रात और गुरुवार सुबह छह पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस दौरान चार पिस्तौल, छह मैगजीन और एक किलो हेरोइन बरामद की गई। यह कार्रवाई अमृतसर और तरनतारन जिले में की गई।

बुधवार रात अमृतसर जिले के मोडे गांव के पास बीएसएफ जवानों ने पांच ड्रोन को मार गिराया। इन ड्रोन के जरिये भेजे जा रहे चार पैकेट में तीन पिस्तौल, तीन मैगजीन और एक किलो सत्तर ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बीएसएफ को इंटेलिजेंस विंग से तरनतारन जिले के डल गांव के एक खेत में आपत्तिजनक वस्तु पड़ी होने की भी सूचना मिली। बीएसएफ और पुलिस ने खेत में पड़ी पिस्तौल की ऊपरी स्लाइड और एक मैगजीन बरामद की।

गुरुवार तड़के बीएसएफ के जवानों ने अटारी गांव के पास एक और ड्रोन को मार गिराया। सर्च आपरेशन के दौरान खेतों में से एक पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद की गईं। पुलिस ने तीनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है।

अमृतसर के अजनाला से बरामद किए गए हथियार और ड्रोन। सौ. बीएसएफ

मप्र के पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में मानस के दोहे और चौपाइयों का होगा वाचन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों (पीटीएस) में अब कानून-व्यवस्था और शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण के साथ श्री रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों का वाचन भी कराया जाएगा।

एडीजी (प्रशिक्षण) राजाबाबू सिंह ने मंगलवार को 4000 नए पुलिस आरक्षकों के प्रशिक्षण की शुरुआत के अवसर पर यह निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह सीख उन्हें इस कारण देनी पड़ी, क्योंकि बड़ी संख्या में नए आरक्षकों ने आवेदन कर घर के पास के केंद्र में प्रशिक्षण दिलाने की मांग की थी। उन्होंने संदेश दिया कि भगवान श्रीराम ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था, प्रशिक्षु आरक्षकों को उनसे सीखना चाहिए। राजाबाबू सिंह ने कहा कि श्री रामचरितमानस पढ़ना पुलिसकर्मियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह आदर्श और मूल्य आधारित जीवन का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र में यह पाठ स्वैच्छिक होगा और दूसरे मत के लोगों को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

छग में 2.64 करोड़ के इनामी 66 माओवादियों का समर्पण

टीम नईदुनिया, जगदलपुर

▸ बीजापुर में सर्वाधिक 25 माओवादियों का समर्पण, इनमें 35 लाख का इनामी रामन्ना भी शामिल

▸ नारायणपुर में समर्पित महिला माओवादी की इच्छा - मेरी एक बेटी हो, वह बड़ी होकर शिक्षक बने

छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में गुरुवार को 2.64 करोड़ के इनामी 66 माओवादियों ने समर्पण किया। इनमें 35 लाख का इनामी माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर (एसजेडसीएम) रामन्ना ईरपा उर्फ जगदीश भी शामिल है, जो ओडिशा के सब जोनल ब्यूरो का प्रमुख था। बीजापुर में 25, दंतेवाड़ा में 15, कांकेर में 13, नारायणपुर में आठ और सुकमा में पांच सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है।

बता दें कि पिछले 18 महीनों में बस्तर रेंज में कुल 1,570 माओवादियों ने समर्पण किया है।

नारायणपुर में समर्पण करने वाली माओवादी रीना कुर्साम ने कहा कि उसका सपना है कि उसकी एक बेटी हो और वह बड़ी होकर शिक्षक बने, ताकि वह दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा सके। माओवादी लखमा लेकाम ने नसबंदी कराई थी और अब वह पिता बनना चाहता है। वहीं, आठ लाख रुपये के इनामी माओवादी हिमांशु मिड़ियाम ने आत्मसमर्पण किया, ताकि वह अपने जनजातीय लोगों को बेहतर जीवन के लिए प्रेरित कर सके। आइजी सुंदरराज ने कहा कि माओवादी संगठन को लगातार नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में और भी माओवादी हथियार डालेंगे।

बेंगलुरु भगदड़ में आयोजकों व वरिष्ठ पुलिस अफसरों को ठहराया जिम्मेदार

बेंगलुरु, प्रेट्र : चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास चार जून को हुई भगदड़ की जांच कर रहे एक सदस्यीय जांच आयोग ने 11 लोगों की जान लेने वाली इस त्रासदी के लिए आयोजकों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों दोनों को जिम्मेदार ठहराया है।

जांच आयोग का नेतृत्व कर रहे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस माइकल डी'कुन्हा ने 11 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को दो खंडों वाली एक रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली और रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) और डीएनए नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जाए। रिपोर्ट के अनुसार, "आयोजकों का कर्तव्य था कि वे कम से कम सात दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करके पूर्व अनुमति प्राप्त करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।"

'महाभारत की कथाओं में कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थान का भी जिक्र करें कथावाचक'

जीतेंद्र सिंह जीत • जागरण

▸ सभी 182 तीर्थों के नाम, महाभारत से जुड़े प्रसंग की भी जानकारी दी

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने देश के टाप 19 कथावाचकों को पत्र लिखकर उनसे अपनी कथाओं के दौरान महाभारत काल के विभिन्न स्थानों का सही उल्लेख करने का अनुरोध किया है। ये स्थान केडीबी के तीर्थों में शामिल हैं। पत्र में कहा है कि वे सभी अपनी कथाओं में पहले से महाभारत काल की घटनाओं का जिक्र करते हैं लेकिन वे सही स्थान के नाम का उल्लेख करेंगे तो कथा की सार्थकता और प्रामाणिकता दृढ़ होने के साथ सनातन प्रेमियों में धर्म के प्रति आस्था प्रगाढ़ होगी और तथ्यों में एकरूपता बनी रहेगी। उन्होंने अनुरोध मान लिया तो आगे से उनकी कथाओं में महाभारत काल के किस्सों में स्थान का भी सही उल्लेख सुनने को मिलेगा।

कथावाचकों की ओर से सुनाए जाने वाले प्रसंगों में अधिकांश महाभारत युद्ध से जुड़े होते हैं। यह युद्ध कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि में लड़ा गया था। इस 48 कोस में केडीबी के 182 तीर्थ स्थल हैं। हर तीर्थ स्थल से महाभारत का कोई न कोई प्रसंग जुड़ा है। ऐसे में केडीबी ने सभी तीर्थों के नाम, उनकी महाभारत से जुड़े होने के प्रसंग आदि की जानकारी भी कथावाचकों को दी है।

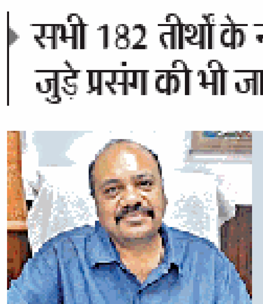

उपेंद्र सिंघल।

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने प्रमुख 19 कथावाचकों को पत्र लिखकर किया अनुरोध

पंजाब में अभियान 'जीवनजोत' का दिखा असर, चौराहों से गायब हुए भिखारी

जागरण संवाददाता, बठिंडा

▸ गुरुवार को संगरूर और मालेरकोटला में आठ बच्चों को भिक्षावृत्ति से बचाया गया

▸ अब तक राज्य में 177 बच्चों को बचाया जा चुका, 13 बच्चों के लिए डीएनए सैंपल

पंजाब सरकार की ओर से राज्य भर में भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए गए अभियान जीवनजोत का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश भर में जिन चौराहों पर हमेशा भीख मांगने वाले दिखाई देते थे, वे अब वहां से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। उधर, गुरुवार को संगरूर जिले के धूरी और मालेरकोटला जिले में आठ बच्चों को भिक्षावृत्ति से बचाया गया। सभी बच्चों को उनके स्वजन की ओर से सुबूत देने के बाद उन्हें सौंप दिया गया। टीमों ने स्वजनों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में वे बच्चों से भीख मंगवाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। यही नहीं, बार-बार पकड़े जाने के बाद इन बच्चों को प्रशासन अपने संरक्षण में रखेगा और बच्चे कभी अभिभावकों को नहीं सौंपे जाएंगे। बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला व पटियाला के जिन चौराहों पर हमेशा भीख मांगते बच्चे दिखाई देते थे, अब वे वहां से नदारद हो गए हैं। ऐसे ही हालात राज्य के अन्य छोटे शहरों के भी हैं। उल्लेखनीय है कि जीवनजोत अभियान का गुरुवार को आठवां दिन था। अब तक राज्य में 177 बच्चों को भिक्षावृत्ति से बचाया जा चुका है। इन बच्चों को छुड़वाने के बाद उन्हें अपना बताने वालों से इसके सुबूत भी मांगे जा रहे हैं। जिन बच्चों के सुबूत नहीं मिल रहे उनके डीएनए टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं ताकि वे बच्चे असल में किसके हैं, इसका पता चल सके। पिछले दो दिनों में ही ऐसे 13 बच्चों के डीएनए सैंपल लेकर उन्हें खरड़ स्थित लैब में भेजा जा चुका है।

दैनिक जागरण ने भिक्षावृत्ति के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत भिखारियों द्वारा भीख मांगने के तरीकों, जनता को परेशान करने और भीख की कमाई से ऐश करने जैसे समाचार प्रकाशित किए गए थे। अभियान का सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि प्रदेश सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया और भिखारियों के विरुद्ध शिकंजा कसा है।

अराजकतत्व खेलने-कूदने के बहाने करने लगे थे जमीन पर कब्जा

प्रथम पृष्ठ से आगे

गुरुद्वारा और मंदिर के बीच विवाद पर उन्होंने बताया कि कुछ अराजकतत्व खेलने-कूदने के बहाने धीरे-धीरे वहां की जमीन पर कब्जा करने लगे थे। मना करने पर गुरुद्वारा के ग्रंथी को जान से मारने की धमकी दी थी। प्रशासन में शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई न होने से अराजकतत्वों का मन बढ़ता गया। बाद में ग्रंथी ने वहां जाना छोड़ दिया। यही हाल हनुमान मंदिर के साथ हुआ। मंदिर के लोगों को लगा कि गुरुद्वारा के लोग ऐसा करवा रहे हैं। यहीं से मनमुटाव पैदा हुआ और गलतफहमी के चलते दोनों धार्मिक स्थल 1984 में बंद हो गए।

पिछले दिनों ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 1799 में विद्रोह करने वाले बाबू जगत सिंह पर शोध कर रही समिति को पुराने दस्तावेज से ज्ञात हुआ कि उन्होंने उस क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे के लिए भूमि दान की थी। बाबू प्रदीप नारायण सिंह से अपने पूर्वजों की धरोहर की दुर्दशा देखी न गई। उन्होंने विवाद को हल कराने का बीड़ा उठाया और दोनों पक्षों से समाधान की बात की। उस स्थान पर अवैध अतिक्रमण भी था। दोनों पक्ष के लोगों को साथ लेकर वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि वह स्थान अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए तथा ऐतिहासिक मंदिर और पवित्र गुरुद्वारा भव्य रूप से अपने अस्तित्व में आना चाहिए। प्रशासन सक्रिय हुआ और भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई। दोनों पक्ष जगत सिंह द्वारा दान की गई भूमि पर ही अपना दावा स्वीकार करने को सहमत हो गए और अदालत में समझौता पत्र जमा कराया। इसके तहत लगभग 4000 वर्ग फीट भूमि को आपस में आधा-आधा बांट लिया गया।

****

3.66 करोड़ रुपये की संपत्ति दान की है दिवंगत आइआरएस अधिकारी वाईवीएस भास्कर राव ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को। वसीयत के तीन ट्रस्टियों ने गुरुवार को संपत्ति के दस्तावेज और दान के चेक टीटीडी को सौंप दिए।

न्यूज गैलरी

पति को छुड़वाने के नाम पर दुष्कर्म, सैन्यकर्मी गिरफ्तार

कोलकाता : जेल में बंद पति को जमानत दिलाने का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोप में कोलकाता के वाटगंज इलाके से पुलिस ने एक सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया है। महिला ने कुछ दिन पहले कोलकाता के पार्क स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें महिला ने आरोप लगाया कि जेल में बंद उसके पति को छुड़वाने के नाम पर सैन्यकर्मी ने उसके साथ अनेकों बार दुष्कर्म किया। महिला से पैसे भी ऐंठ लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपित सैन्यकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। (राब्यू)

मुर्शिदाबाद में तृणमूल कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर हत्या

कोलकाता : बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर इलाके में कुछ रात अज्ञात बदमाशों ने एक तृणमूल कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मृतक का नाम 55 वर्षीय षष्ठी घोष था। घर से करीब 300 मीटर दूर सड़क पर उनका शव मिला। मृतक के परिवार ने दावा किया कि षष्ठी घोष की हत्या तृणमूल कांग्रेस से जुड़े होने के कारण की गई है। विपक्षी भाजपा का कहना है कि तृणमूल के भीतर अंदरूनी लड़ाई में षष्ठी घोष की जान गई है। स्थानीय तृणमूल नेतृत्व ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है। मालूम हो कि षष्ठी घोष को लेकर बंगाल में बीते 15 दिनों के भीतर सत्तारूढ़ दल के पांच नेताओं की हत्या हो चुकी है। (राब्यू)

पुरुष से महिला को ट्रांसजेंडर पहचान पत्र से मिला पासपोर्ट

कोलकाता : कोलकाता के बालीगंज इलाके की रहने वाली अनुप्रभा दास मजूमदार को ट्रांसजेंडर पहचान पत्र से पासपोर्ट मिला है। 32 साल की अनुप्रभा पुरुष से महिला बनी हैं। मालूम हो कि भारत में पासपोर्ट बनवाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान पत्र स्वीकार करने का पहले नियम नहीं था, जिससे तृतीय लिंग वालों के लिए पासपोर्ट बनवाना मुश्किल था। लैंगिक अधिकार कार्यकर्ता अनुप्रभा के लिए भी पासपोर्ट पाने की राह आसान नहीं रही। कोलकाता स्थित पासपोर्ट कार्यालय के कई बार चक्कर लगाने के बाद जब प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद उन्हें पासपोर्ट जारी कर दिया गया। अनुप्रभा ने कहा-'इतने दिनों बाद राहत महसूस हुई है।' अनुप्रभा 2023 से ट्रांसजेंडरों के लिए पासपोर्ट के अधिकार के लिए लड़ रही थीं। गत 18 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अब से पासपोर्ट के लिए ट्रांसजेंडर पहचान पत्र भी स्वीकार किया जाएगा। (राब्यू)

सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एअर इंडिया को चार नोटिस, हो सकती है कार्रवाई

डीजीसीए ने दी चेतावनी, एयरलाइन ने कहा- खुद दी थी जानकारी, नोटिसों का देंगे जवाब

एअर इंडिया को पूर्व में भी दी जा चुकी हैं कई चेतावनियां

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, रायटर : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया को चेतावनी दी है कि चालक दल के विश्राम प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विमानन नियामक ने इस तरह के उल्लंघनों के लिए एअर इंडिया को चार कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

एयरलाइन ने अहमदाबाद दुर्घटना के कुछ दिनों बाद पिछले महीने डीजीसीए को इस वर्ष और पिछले वर्ष हुई समस्याओं की सूचना स्वयं दी थी। 23 जुलाई को जारी चार नोटिसों में सुरक्षा अनुपालन में बार-बार चूक के लिए एअर इंडिया को आलोचना की गई है और अतीत में दी गई अन्य चेतावनियों का उल्लेख किया किया गया है। संभावित कार्रवाई में जुर्माना या अधिकारियों को नौकरी से हटाने का आदेश शामिल हो सकता है। इनमें कुल 29 उल्लंघनों का जिक्र है, जिनमें पायलटों को अनिवार्य रूप से आराम नहीं देना, सिम्युलेटर प्रशिक्षण आवश्यकताओं का खराब अनुपालन, बहुत ऊंचाई वाले हवाई अड्डे के लिए प्रशिक्षण का अभाव और अपर्याप्त केबिन क्रू के साथ अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरना शामिल है। एअर इंडिया ने एक बयान में कहा कि वे नोटिस पिछले एक वर्ष में स्वैच्छिक रूप से दी गई जानकारियों से संबंधित हैं और वह इनका निर्धारित समय में नियामक को जवाब देगी।

एक नोटिस में कहा गया है कि जून, 2024 में दो पायलटों और जून, 2025 में एक पायलट के लिए साप्ताहिक विश्राम नियमों का उल्लंघन किया गया, हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि पायलटों ने कितने अतिरिक्त घंटों की उड़ान भरी। एक अन्य नोटिस में कहा गया है कि पिछले वर्ष दो पायलटों ने सिम्युलेटर प्रशिक्षण लिया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा के भीतर उड़ान शुरू नहीं की, जिसके कारण उन्हें दोबारा प्रशिक्षण लेना होगा।

नोटिस में आगे कहा गया है कि इस वर्ष अप्रैल में एक पायलट ने आवश्यक विशेष सिम्युलेटर प्रशिक्षण के बिना काठमांडू से उड़ान भरी थी। काठमांडू में पहाड़ी इलाका और एक बेहद ऊंचाई वाला टेबल-टाप रनवे है। टेबल-टाप रनवे के एक सिरे पर या दोनों सिरों पर खड़ी ढलान होती है। चेतावनियों में यह भी चिंता व्यक्त की गई थी कि केबिन क्रू दलों ने नियमों का बार-बार पालन नहीं किया, क्योंकि इस वर्ष अप्रैल और मई में चार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आवश्यक 15 से कम केबिन क्रू के साथ उड़ान भरी गई थी। नोटिसों की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रशासन चिंतित है कि एअर इंडिया चीजों को हल्के में ले रही है, हमने उन्हें कई चेतावनियां दी हैं।

यात्री वाहनों में छह एयरबैग अनिवार्य करने की मांग खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : यात्री वाहनों में छह एयरबैग लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। साथ ही कहा कि यह मामला पूरी तरह से नीतिगत दायरे में आता है। कोर्ट ने याची से कहा कि वह इस संबंध में सरकार को प्रतिवेदन दे। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 17 मई को ही सरकार को एक प्रतिवेदन दे चुके हैं। पीठ ने कहा, "रिट याचिका में की गई मांगें पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा बनाई जाने वाली नीति के दायरे में आती हैं। इसलिए, हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।" पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता ने केंद्र को कोई प्रतिवेदन दिया है, तो उस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि वह छह एयरबैग अनिवार्य नहीं करने को संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 का उल्लंघन घोषित करे। साथ ही इसमें संबंधित अधिकारियों को वाहन सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। गौरतलब है कि अनुच्छेद-14 जहां कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद-21 जीवन की सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है।

पिता सीतामढ़ी में मौलवी, बेटा मेरठ के मंदिर में 10 साल से पुजारी

जागरण संवाददाता, मेरठ

- हनुमान चालीसा याद किया, यू-ट्यूब से सीखे मंत्र, हाथ देख देता था सलाह
- 15 साल पहले बिहार से भागकर दिल्ली आया था, गिरफ्तार

मुस्लिम युवक कासिम धर्म छिपाकर मेरठ जिले में दादरी गांव के शिव मंदिर में 10 साल से पुजारी कृष्णा बनकर रह रहा था। यू-ट्यूब से दुर्गा और हनुमान चालीसा और मंत्र याद किए। हाथों की रेखा देखकर उपाय भी बताता था। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान उजागर करने के मामले को लेकर वह डर गया और कांवड़ लेने का बहाना बनाकर 15 दिन पहले मंदिर से चला गया। इसके बाद मुजफ्फरनगर के काली माता मंदिर में रहने लगा। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद वापस आया। दानपात्र में रकम कम मिलने पर ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीणों ने कासिम से आधार कार्ड मांगा तो वह नहीं दे पाया।

सीतामढ़ी (बिहार) के अब्बास वहां की एक मस्जिद में मौलवी हैं। उसके पांच बेटों में सबसे छोटा कासिम पारिवारिक कलह के चलते 15 साल पहले घर छोड़कर दिल्ली आ गया था। पांच साल दिल्ली में रहने के बाद वह दादरी स्थित शिव मंदिर में पहुंचा। वहां पर साफ-सफाई और पूजा-पाठ करने लगा। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कासिम ने दिल्ली में रहते हुए दुर्गा और हनुमान चालीसा याद कर लिया था। साथ ही मंत्र, पूजा-पाठ एवं हस्तरेखा का ज्ञान भी हासिल कर लिया था। दादरी पहुंचने पर उसने अपना नाम कृष्णा बताया। अभी कांवड़ यात्रा के

कासिम। पुलिस

दौरान पहचान उजागर करने का मामला उठा तो कासिम डर गया। वह ग्रामीणों को कहकर गया कि कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहा है। दानपात्र की चाबी ले गया और मुजफ्फरनगर में काली माता मंदिर में जाकर रहने लगा। बुधवार को वह गांव लौट आया।

ऐसे उठा पर्दा : ग्राम प्रधान प्रवीण मोतला ने बताया कि कासिम उर्फ कृष्णा के आने पर दानपात्र खोला गया। दानपात्र में रकम कम मिलने पर शक हुआ तो कृष्णा से आधार कार्ड मांगा गया। कार्ड नहीं देने पर पुलिस को बुलाकर उसे सौंप दिया गया। पुलिस ने बिहार पुलिस के माध्यम से कासिम के स्वजन से फोन पर बात की। कासिम के खिलाफ धर्म छिपाने और मंदिर के दानपात्र में चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया है। गुरुवार को आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

नई दिल्ली-मुंबई की उड़ान में तकनीकी खराबी, टेकआफ रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- काकपिट में उड़ान उपकरणों की स्क्रीन में गड़बड़ी के कारण रोका गया
- दूसरे विमान से यात्री तीन घंटे से अधिक की देरी से हुए रवाना

नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आइएक्स 1163 का टेक आफ बुधवार रात 9:20 पर निर्धारित प्रस्थान से पहले तकनीकी खराबी के कारण रद कर दिया गया। इस घटना से विमान में सवार 160 से अधिक यात्रियों को असुविधा हुई, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए काकपिट क्रू ने त्वरित निर्णय लेते हुए यह फैसला किया। बाद में यात्रियों के लिए दूसरे विमान का प्रबंध कर उन्हें रात 12:29 पर मुंबई भेजा गया।

काकपिट में उड़ान उपकरणों की स्क्रीन, जो टेकआफ के दौरान विभिन्न तरह की गति दर्शाती है, में खराबी पाए जाने के बाद पायलटों ने आइजीआइ एयरपोर्ट के व्यस्त रनवे से टेकआफ रोक दिया। एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने देरी के लिए खेद व्यक्त करते हुए बताया कि चालक दल ने मामूली तकनीकी समस्या के चलते टेकआफ रद करने का

प्रतीकात्मक

निर्णय लिया, जो हमारी मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप था।

टेकआफ रद करने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतारा गया और टर्मिनल पर वापस लाया गया। प्रभावित विमान को निरीक्षण के लिए ग्राउंडेड रखा गया है। बता दें कि मंगलवार को भी दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान संख्या 2403 में तकनीकी खराबी आ गई थी।

मुंबई में छात्र के यौन शोषण के मामले में शिक्षिका को जमानत

मुंबई, प्रेट्र: मुंबई के एक विशेष कोर्ट ने नाबालिग छात्र का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार 40 वर्षीय शिक्षिका को जमानत दे दी और कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे। यहां के एक प्रतिष्ठित स्कूल की शिक्षिका को छात्र का बार-बार यौन शोषण करने के आरोप में इसी महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। ये आरोप लगाए गए हैं कि महिला फाइव स्टार होटलों में ले जाकर छात्र का यौन शोषण करती थी। संबंध बनाने से पहले उसे शराब भी पिलाती थी। विशेष जज सबीना मलिक ने सोमवार को शिक्षिका को जमानत दी। शिक्षिका के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि पीड़ित की उम्र 16 वर्ष से अधिक है और दोनों पक्षों से मिले साक्ष्य दर्शाते हैं कि उनके बीच सहमति से संबंध बने थे। आरोपित शिक्षिका ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए दोनों में अब संबंध नहीं है।

सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल की जाए

- वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध
- किशोरों की यौन गतिविधियों को अपराध माने जाने को दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए वैधानिक उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का अनुरोध किया है, ताकि किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को अपराध न माना जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि मौजूदा कानून किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध मानता है और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

''निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ'' मामले में शीर्ष अदालत की सहायता कर रहीं जयसिंह ने पाक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों से जुड़ी यौन गतिविधियों को पूरी तरह से अपराध घोषित करने के फैसले को चुनौती देते हुए लिखित दलीलें दी हैं।

जयसिंह ने कहा कि कानूनी ढांचा किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को दुर्व्यवहार के बराबर मानता है और उनकी स्वायत्तता, परिपक्वता और सहमति देने की क्षमता को नजरअंदाज

इंदिरा जयसिंह। फाइल

करता है। सहमति की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने को सही ठहराने के लिए कोई तर्कसंगत कारण या अनुभवजन्य आंकड़े मौजूद नहीं हैं। पराधिक कानून अधिनियम, 2013 द्वारा इसे बढ़ाए जाने से पहले 70 से ज्यादा वर्षों तक यह 16 ही थी। यह वृद्धि बिना किसी बहस के की गई तथा यह सहमति की आयु 16 वर्ष बनाए रखने की समिति की सिफारिशों के विरुद्ध है।

कम कीमत पर कबूतर बेचने पर पिता ने कर दी पुत्र की हत्या

जासं, कदवा (कटिहार) : बिहार के कटिहार जिले में कम कीमत पर कबूतर बेचने से आक्रोशित पिता ने अपने 14 वर्षीय पुत्र के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटका दिया। मृतक का नाम अमित कुमार शर्मा था। आरोपित के बड़े पुत्र राजकुमार शर्मा ने पिता के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। स्वजन ने बताया कि बुधवार की शाम अमित बाजार में कबूतर बेचने गया था। कम कीमत पर कबूतर बेचने से पिता इतना आक्रोशित हो गया कि उसने अपने पुत्र के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को घर में फंदे से लटका दिया। ग्रामीणों को उसने बताया कि उसका पुत्र कहीं गुम हो गया है। बाद में ग्रामीणों ने खोजबीन की तो घर में ही फांसी के फंदे से शव लटका हुआ मिला। ग्रामीणों ने बताया कि उसके पिता ने दो शादियां की हैं। पहली पत्नी की 15 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। संतोष पहली पत्नी के साथ भी मारपीट करता था।

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में हाई कोर्ट जाने की दी छूट

- याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इन्कार, मैरिट पर विचार नहीं
- मामूली चोट के रूप में गलत वर्गीकृत करने से कम मुआवजे का आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के मामले में एक याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। इसमें दावा किया गया था कि हादसे में कई गंभीर रूप से घायल बचे लोगों को ''अस्थायी विकलांगता'' या मामूली चोटों के रूप में ''गलत वर्गीकृत'' किए जाने के कारण कम मुआवजा दिया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता संगठनों को इस मामले में क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता दी है।

कोर्ट ने गुरुवार को यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की मैरिट पर विचार नहीं किया है। 1984 के 2-3 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से अत्यधिक विषैला गैस मिथाइल आइसोसायनेट लीक हुआ, जिससे 5,479 की मौत हो गई और पांच लाख से अधिक लोग घायल हुए।

जब मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि इस हादसे को दशकों बीत चुके हैं। पीठ ने पूछा, 'क्या हमारे पास यह विशेषज्ञता है कि किसी व्यक्ति को ए श्रेणी या बी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए?'' याचिकाकर्ता संगठनों के वकील ने कहा कि उन्होंने याचिका में एक सीमित प्रार्थना की है और वे कुछ भी फिर से खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से यह निर्देश मांगा कि वे उन लोगों की पहचान और मुआवजा देने के लिए उचित कदम उठाएं, जिन्हें 'अस्थायी विकलांगता' या 'मामूली चोट' के रूप में गलत वर्गीकृत किए जाने के कारण कम मुआवजा मिला है, जो भोपाल गैस लीक आपदा अधिनियम, 1985 और योजना के प्रविधानों के तहत है। वकील ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग गैस त्रासदी के कारण किडनी फेलियर और कैंसर से पीड़ित हुए और उन्हें मामूली चोट के मामलों के रूप में देखा जा रहा है।

विस्फोट की एनआइए जांच का मुकदमा करने वाले तृणमूल नेता निष्कासित

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले के राजुआ गांव में हुए बम विस्फोट की घटना की एनआइए जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा करने वाले तृणमूल कांग्रेस नेता सुवेंदु दास को पार्टी नेतृत्व ने निष्कासित कर दिया है। सुवेंदु तृणमूल के युवा संगठन की पूर्व बर्द्धमान जिला कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। तृणमूल के पूर्व बर्द्धमान के जिलाध्यक्ष व कटवा से विधायक रवींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुवेंदु ने पार्टी विरोधी कार्य किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बम धमाके की घटना को रवींद्रनाथ ने उनपर जानलेवा हमला बताया था। सुवेंदु ने कहा-'जब विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं तो जनता का क्या होगा? आम लोगों की सुरक्षा के लिए ही मैंने एनआइए जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में मुकदमा किया है। यह कोई छोटी घटना नहीं थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि कई जख्मी हो गए थे।'

असम में विध्वंस कार्रवाई पर राज्य के प्रमुख सचिव को नोटिस

- असम में जून में बेदखली और विध्वंस की कार्रवाई से 667 से अधिक परिवार हुए हैं प्रभावित

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असम सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के गोलपाड़ा जिले में हाल ही में की गई विध्वंस कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया।

याचिका में कहा गया है कि जून में हुई बेदखली व विध्वंस की कार्रवाई से 667 से अधिक परिवार प्रभावित हुए और यह कार्रवाई बिना व्यक्तिगत सुनवाई या अपील का अवसर दिए, मनमाने ढंग से की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने याचियों की ओर से कहा कि सिर्फ दो दिन का नोटिस दिया गया और उसके तुरंत बाद मकान गिरा दिए गए। ये वे लोग हैं जो 60-70 वर्षों से वहां रह रहे थे। ब्रह्मपुत्र की धारा समय-समय पर बदलती है, जिससे लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसने को विवश होते हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कार्रवाई अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर की गई।

सुप्रीम कोर्ट।

याचिका में क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और ध्वस्त घरों, स्कूलों आदि के पुनर्निर्माण के लिए अंतरिम राहत के निर्देश भी मांगे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार यह साबित करती है कि यह जमीन सरकारी है, तो सुप्रीम कोर्ट की 13 नवंबर 2024 की उस व्यवस्था के अनुसार राहत नहीं दी जा सकती, जिसमें स्पष्ट था कि सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भूमि, नदी किनारे या जल निकायों पर अवैध कब्जों में बिना 15 दिन के नोटिस के भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट से अन्य

डीजीपी नियुक्ति में सुनवाई पर सहमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी। याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मामला अगले सप्ताह 30 और 31 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने कहा कि झारखंड के मौजूदा डीजीपी रिटायरमेंट के बावजूद अपने पद पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि तीन जजों की पीठ को अदालत के पिछले निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मामले की सुनवाई करनी थी। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि ऐसी स्थिति में अगले हफ्ते नियमित मामलों की सुनवाई के दौरान सुनवाई की जाएगी।

नई ओबीसी सूची पर रोक के खिलाफ 28 को सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : ओबीसी की नई सूची पर रोक लगाए जाने के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की नई सूची पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ बंगाल ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने गुरुवार को राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने के बाद मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई।

सिब्बल ने कहा कि इस संबंध में हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसी कोई अवमानना नहीं की गई है।

जागरण विशेष

एक रुपये स्वच्छता अभियान से बदल रही गांवों की तस्वीर

लखनऊ की सौ ग्राम पंचायतों में जगी स्वच्छता की अलख, कचरा निस्तारण में रहे बने माडल

राजीव बाजपेयी • जागरण

लखनऊ : वर्ष 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव महानगर ही नहीं, सुदूर गांवों में दिखने लगा है। सफाई अब मजबूरी या सरकार के कार्य का नहीं, बल्कि आम लोगों में संस्कार का रूप ले चुकी है। गांवों में भी लोग गीले व सूखे कचरे की चिंता कर हैं। जिले की सौ ग्राम पंचायतों में प्रति दिन एक रुपये स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिसमें ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं। इसमें डोर टू डोर वेस्ट क्लेक्शन और निस्तारण किया जा रहा है। कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों का प्रकोप कम हुआ है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लखनऊ की ग्राम पंचायतों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर्स का निर्माण हो रहा है। इसके तहत कचरे को एकत्र कर उससे खाद बनाने और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की भी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण ओम प्रकाश बताते हैं कि गांव में शहर की तरह सफाई हो सकती है यह हम लोगों ने साबित किया है। अब पलायन रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस पहल को जिले की सभी ग्राम पंचायतों लागू करने की तैयारी की जा रही है।

मलिहाबाद तहसील की पंचायत नबीपनाह के प्रधान प्रकाश सिंह बताते हैं 1261 घरों से डोर टू डोर कलेक्शन कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत में कचरे के भंडारण और निस्तारण के लिए रिसोर्स रिकवरी सेंटर भी बना है। जहां खाद बनाने के साथ प्लास्टिक को निस्तारित कर दाना बनाने की मशीन लगाई जा रही है।

लखनऊ की नबीपनाह पंचायत में बना रिसोर्स रिकवरी सेंटर • जागरण

एकत्र राशि का स्वच्छता के लिए उपयोग

लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी बताते है कि एक रुपये स्वच्छता अभियान से गांवों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन से ग्राम पंचायत के परिवारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से एकत्रित शुल्क सफाई पर व्यय किया जा रहा है। जून माह में इन पंचायतों में करीब 17 लाख रुपये की धनराशि एकत्र की गई है। 100 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू कराने के बाद दूसरे चरण में शेष पंचायतों को लिया जाएगा। नबीपनाह के ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह बताते हैं कि अब गांव में कहीं पर भी कूड़ा पड़ा नजर नहीं आता है। स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण को भी और बेहतर किया जाए इसके लिए भी पंचायत की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता के प्रति ग्रामीण भी सजग हैं। गांव में लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर दिखता है।

विशाख जी, जिलाधिकारी

शादी बरात के लिए भी कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था

नबीपनाह पंचायत में शादी बरात, सार्वजनिक कार्यक्रमों अथवा भंडारा आदि के समय भी सफाई टीम भेज कर कूड़ा कलेक्शन कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। पंचायत ने खुले में कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। प्रति माह पंचायत सचिव और डीएम द्वारा नामित अधिकारी स्वच्छता का आडिट करते हैं। समाजसेवी भीम प्रकाश के अनुसार लोगों को पता है कि यह उनकी बेहतरी के लिए हो रहा है। अब गांवों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

फर्जी बिल पास कराने के दबाव में महिला इंजीनियर ने दी जान

- असम का मामला, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार

बोंगाईगांव, प्रेट्र: असम में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 30 वर्षीय महिला इंजीनियर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने महिला पर फर्जी बिल पास कराने को लेकर दबाव बना रहे थे। मृतका का शव मंगलवार दोपहर को उनके किराए के मकान में मिला। वह मूलरूप से गुवाहाटी की रहने वाली थीं और बोंगाईगांव में कार्यरत थीं।

महिला इंजीनियर ने एक सुसाइड नोट में दो अधिकारियों का नाम लिखा था और दावा किया कि कार्यस्थल पर उन पर अत्यधिक दबाव था। बंगाईगांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मोहन लाल मीणा ने बताया कि हमने सुसाइड नोट में नामजद दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पीडब्ल्यूडी का कार्यकारी अभियंता है और दूसरा उप-मंडल अधिकारी है। दोनों का इस महीने की शुरुआत में जिले से बाहर तबादला कर दिया गया था। कार्यकारी अभियंता को पदोन्नत कर नलबाड़ी जिले में और उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) का कामरूप जिले में तबादला किया गया था। पुलिस उन आरोपों की पुष्टि कर रही है, जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है। बताया जा रहा है कि अभियंता ने सुसाइड नोट में लिखा है कि दोनों अधिकारियों ने बंगाईगांव में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण को लेकर उस पर दबाव बनाया था। उसने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने एक ठेकेदार द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर जमा किए गए बिलों को मंजूर करने के लिए उस पर दबाव डाला था।

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 25 जुलाई, 2025

दैनिक जागरण

विवेक की शक्ति से ही उचित-अनुचित का बोध संभव है

चुनाव आयोग के सही सवाल

चुनाव आयोग को इन साहसिक और सर्वथा उचित सवालों के लिए धन्यवाद कि क्या संविधान के विरुद्ध जाकर फर्जी वोट डालने का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाए? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी पूछा कि क्या निराधार बातों से डरकर मृत लोगों, दूसरी जगह पर स्थायी रूप से बस गए व्यक्तियों और विदेशी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? ये वे सवाल हैं जिनके जवाब ईमानदारी से दिए जाने चाहिए। ये जवाब उन राजनीतिक दलों और नेताओं को विशेष रूप से देने चाहिए जो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आसमान सिर पर उठाए हुए हैं और संसद के भीतर एवं बाहर संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए हंगामा कर रहे हैं। इस हंगामे से न तो लोकतंत्र का भला होने वाला है और न भारतीय राजनीति का और न ही चुनाव प्रक्रिया का। वस्तुतः यह हंगामा आम मतदाताओं के हितों की अनदेखी के साथ ही अनुचित, अवैध तरीके से मतदाता बने लोगों की पक्षधरता भी है। आखिर विपक्षी दल यह बेकार की जिद क्यों पकड़े हुए हैं कि जो लोग वैध मतदाता नहीं हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में बने रहने दिए जाएं? वे इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि ऐसे सारे लोग उनके वोटर हैं और अनिवार्य रूप से उन्हें ही वोट देंगे।

हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सही बताए जाने के बाद भी लोगों को गुमराह करने के साथ ही यह समझाने में लगे हुए हैं कि आयोग मोदी सरकार और भाजपा के अनुचित हितों की पूर्ति के लिए बड़ा ही गैर-संवैधानिक काम कर रहा है। एक सही पहल पर लोगों को गुमराह करना तो राजनीतिक पाप है। यह पाप वे लोग कर रहे हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं और उसकी प्रतियां लहराते हुए घूम रहे हैं। अच्छा हो कि वे संविधान को फिर से पढ़ें और यह भी देखें कि चुनाव आयोग को क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जो राजनीतिक दल एक संवैधानिक संस्था का अनादर करने में लगे हुए हैं, उनके बारे में यह कहना कठिन है कि उन्हें संविधान में कोई श्रद्धा है। संविधान बचाने के नाम पर उससे ही खिलवाड़ करने की जो घटिया राजनीति हो रही है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में ऐसे भी राजनीतिक दल होंगे जो इतनी क्षुद्र राजनीति करेंगे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि क्षुद्र राजनीति करने में वह कांग्रेस सबसे आगे है जिसने लंबे समय तक देश पर शासन किया है और समय-समय पर चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की पहल भी की। साफ है कि आज की कांग्रेस अपने ही कई नेताओं के खिलाफ खड़ी होने का काम कर रही है।

लापता पुलिस

बिना कोई कारण बताए लापता हुए उत्तर प्रदेश में कानपुर के पुलिसकर्मियों का कृत्य आपराधिक है, किंतु इन पुलिसकर्मियों की जिन अधिकारियों के प्रति सीधी जवाबदेही है, उनका कृत्य भी लापरवाहीपूर्ण और अक्षम्य है। कानपुर कमिश्नरेट के विभिन्न थानों, पुलिस लाइन से 53 महिला और पुरुष पुलिसकर्मी छह माह से लापता हैं। इनमें 19 पुलिसकर्मी कुछ समय का अवकाश लेकर गए, लेकिन फिर लौटे ही नहीं। 12 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से निलंबित कर दिया गया तो वे वापस नहीं आए। अन्य की गुमशुदगी के भी ऐसे ही कारण हैं। कमिश्नरेट में करीब सात हजार पुलिसकर्मी हैं जिनमें से यदि 53 लापता हैं तो समझा जा सकता है कि सबसे अनुशासित कहे जाने वाले बल में किस तरह की लापरवाही हो रही है। यदि यह प्रवृत्ति कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में है तो अन्य कमिश्नरेट या जिलों में स्थिति बहुत भिन्न नहीं होगी। इतने लंबे समय तक कोई सरकारी सेवा के प्रति उपेक्षित रुख अपना रहा तो ऐसे लोगों को सेवामुक्त कर नए होनहारों को अवसर देना चाहिए। यदि पुलिसकर्मी इतने समय से गायब हैं तो उनके विरुद्ध पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अतीत में कई लापता पुलिसकर्मी आपराधिक गिरोहों से जुड़े पाए जा चुके हैं। इसलिए लापता पुलिसकर्मियों की मौजूदा गतिविधियों की गहराई से जांच और जरूरी हो जाती है। यदि इस दिशा में समय रहते उपाय नहीं किए गए तो पुलिस विभाग के प्रति धारणा और प्रभावित होगी। पुलिस की छवि को लेकर अक्सर सवाल उठते भी रहते हैं। इस कारण तत्काल प्रभावी कार्रवाई और आवश्यक हो गई है ताकि पुलिस के प्रति भरोसा बना रहे।

> यदि यह प्रवृत्ति कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में है तो अन्य कमिश्नरेट या जिलों में स्थिति बहुत भिन्न नहीं होगी

सभी हितों को साधने वाला व्यापार समझौता

पीयूष गोयल

ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से एक प्रमुख बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होने के साथ ही सेवा प्रदाताओं एवं किसानों के हितों की भी रक्षा होगी

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर सहमति बन गई है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) के अस्तित्व में आने से रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और व्यवसायों को नई वैश्विक पहचान मिलेगी। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की किफायती दरों पर पहुंच भी सुनिश्चित होगी। सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं।

पिछली यूपीए सरकार ने भारत के दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था। यूपीए सरकार में विकसित देश भारत से व्यापार समझौते के अनिच्छुक थे, क्योंकि तब देश की गिनती दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी थी। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिकी की काया ही पलट गई। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2014 से लगभग तिगुना बढ़कर करीब 331 लाख करोड़ रुपये हो गया है। क्रांतिकारी सुधारों, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आकर्षक आर्थिक गंतव्य के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं।

ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। यह करीब 99 प्रतिशत टैरिफ समाप्त करता है, जो लगभग शत प्रतिशत व्यापार मूल्य को कवर करता है। यह 56 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपार अवसर बनाएगा, जिसके 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। इससे छोटे व्यवसाय समृद्ध होंगे, क्योंकि भारतीय उत्पादों को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी। खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के कारोबार में भारी विस्तार होगा। विश्व के एक आकर्षक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त चमड़ा और जूते, वस्त्र, समुद्री उत्पाद और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। इन क्षेत्रों में, जहां कई छोटे व्यवसाय संचालित होते हैं, निवेश और रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। भारत के चमड़ा और जूता निर्यात में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत वस्त्र, चमड़ा और जूते के क्षेत्र में ब्रिटेन के शीर्ष तीन आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की बेहतर स्थिति में है।

अवधेश राजपूत

इस समझौते के बाद 95 प्रतिशत से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे कृषि निर्यात और ग्रामीण समृद्धि में तेज वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे अगले तीन वर्षों में कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान है, जो 2030 तक भारत के 100 अरब डालर के कृषि-निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देगा। इससे भारतीय किसानों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाजार के द्वार खुलेंगे, जो जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों को मिलने वाले फायदे के बराबर या उससे भी अधिक होगा। हल्दी, काली मिर्च, इलायची, प्रसंस्कृत उत्पादों, अचार और दालों को भी शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। निर्यात बढ़ने से कृषि आय में वृद्धि होगी तथा गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कृषि मूल्य शृंखला में रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए एफटीए में भारत के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। भारत ने डेरी उत्पादों, सेब, जई और खाद्य तेलों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। यह मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषक समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को दर्शाता है। समझौते से भारतीय मछुआरों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु के मछुआरों की ब्रिटिश बाजार में पहुंच सुगम होगी। यह समझौता सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवा और शिक्षा सहित अन्य सेवाओं में भारतीयों के लिए नए अवसर बनाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे कराधान का मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

व्यापार समझौते प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, जिससे हमारे उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर उच्च-गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। मोदी सरकार ने गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत समर्थन दिया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं और मुक्त व्यापार समझौतों पर बात आगे बढ़ाई है। सरकार ने किसी भी एफटीए पर हस्ताक्षर से पहले उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया है। यह जानकर खुशी होती है कि उद्योग जगत ने इन व्यापार समझौतों का समर्थन किया है। ब्रिटेन के साथ समझौता बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों के लिए एक मानक है। यह हमारे मूल हितों से समझौता किए बिना, वंचित समुदायों के लिए आकर्षक वैश्विक अवसरों के द्वार खोलता है। यह इस बात का एक प्रखर उदाहरण भी है कि नया भारत व्यापार किस प्रकार करता है।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं)
response@jagran.com

पड़ोसियों को पटरी पर लाता भारत

श्रीराम चौलिया

भारत ने शांत, संयमित और संवेदनशील रवैये से काम लिया और तभी मालदीव में स्थिति बदल पाई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव के महत्वपूर्ण दौरे पर होंगे। सामरिक मायनों में अहम माने जाने वाले इस द्वीपसमूह के साठवें स्वाधीनता दिवस में मोदी सम्मानित अतिथि ही नहीं, बल्कि वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शासनकाल के दौरान वहां राजकीय यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता भी हैं। प्रतीकात्मक और ठोस मानदंडों के आधार पर देखें तो यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम' विदेश नीति में एक मील का पत्थर है, जिसे मोदी सरकार की परिपक्व कूटनीति का उदाहरण माना जा सकता है। यह संयोग नहीं है कि एक समय भारत विरोध का राग अलापने वाले मुइज्जू आज मोदी के स्वागत में लाल कालीन बिछा रहे हैं। यह बदलाव भारत जैसी बड़ी शक्ति द्वारा एक छोटे पड़ोसी देश के साथ धैर्यपूर्वक और कुशलतापूर्वक व्यवहार का परिणाम है। मुइज्जू के कार्यकाल की शुरुआत में उनके समर्थकों ने भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और भारत को मालदीव में एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में पेश किया था, पर भारत ने ऐसे बयानों को लेकर औपचारिक स्तर पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अन्यथा द्विपक्षीय रिश्ते और बिगड़ जाते।

मालदीव से प्रतिकूल संकेतों के बीच भी भारत ने इस पड़ोसी देश की विकास सहायता राशि 470 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी। इसके अलावा दो प्रकार की मुद्रा विनिमय व्यवस्थाएं भी बनाईं, जिनके तहत 40 करोड़ डालर के साथ-साथ 3,000 करोड़ रुपये भी मालदीव को उपलब्ध कराए गए। इन प्रविधानों से उसे अपनी डगमगाती आर्थिक स्थिति को सुधारने और ऋण के बोझ को घटाने में सहायता मिली। बदहाली के शिकार मालदीव को संकट के समय उबारने वाला एकमात्र देश भारत था। जबकि मुइज्जू जिस चीन के मुरीद रहे थे, उसने उन्हें कोई रियायत नहीं दी। यह भी एक तथ्य है कि मालदीव की मुश्किलें चीनी कर्ज के जाल में फंसने से ही बढ़ी थीं। भारत ने मालदीव की दयनीय दशा को बखूबी भांपते हुए अपनी उदारता से सिद्ध किया कि भारत बड़े दिल वाला पडोसी है, जो न केवल प्राकृतिक आपदा में काम आता है, अपितु राष्ट्रीय संकटों से भी निजात दिलाने की मंशा और क्षमता रखता है। ऐसी ही परिस्थितियों से भारत ने 2022 में श्रीलंका को उबारा था। चीनी कर्ज बोझ से कराह रहे श्रीलंका को तब लगभग चार अरब डालर की आपात सहायता प्रदान की थी। इसका ही परिणाम है कि आज श्रीलंका में सत्तारूढ़ जनता विमुक्ति पेरमुना जो पूर्व में भारत विरोधी पार्टी थी, वह आज भारत को घनिष्ठ मित्र के रूप में देखती है। आज वहां की सरकार भारत के विरुद्ध हिंद महासागर में चीनी साजिशों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं।

असर दिखाती मोदी सरकार की कूटनीति। फाइल

ऐसी कवायदों से यह लग सकता है कि जैसे भारत मौद्रिक सहायता के बदले अपने प्रति निष्ठा चाह रहा है या वित्तीय कूटनीति के खेल में दक्षिण एशिया में चीन को मात दे रहा है। हालांकि यह केवल आर्थिक उदारता ही नहीं है जिसकी वजह से मालदीव और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को यह अहसास हुआ कि भारत उनके भविष्य के लिए अपरिहार्य है। अक्टूबर 2024 में भारत और मालदीव ने 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी' का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत रक्षा सहयोग का विस्तार हुआ है। आज संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, भारत द्वारा मालदीव के सैनिकों का प्रशिक्षण और मालदीव को जहाज उपलब्ध कराना इत्यादि सक्रिय रूप से जारी है। इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि घरेलू राजनितिक कारकों और 'संतुलित विदेश नीति' के नाम पर भारत के छोटे पड़ोसी समय-समय पर चीन या अन्य बाहरी शक्तियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और भारत ऐसी युक्तियों को अवरुद्ध भी नहीं कर सकता। भारत के हाथ में बस इतना है कि वह छोटे देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दे, इन पड़ोसियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से बचे और ऐसे विकल्प पेश करे जो चीन की तुलना में अधिक भरोसेमंद और निर्देशात्मक न होकर परामर्शात्मक हों।

मुइज्जू के सकारात्मक कायापलट को चीन की हार और भारत की विजय कहकर ढिंढोरा पीटना या मालदीव को सबक सिखाना अथवा उसकी हेकड़ी निकालना जैसे दावे उचित नहीं। मालदीव के लोगों की आजीविका के बड़े स्रोत पर्यटन में चीन, रूस और ब्रिटेन जैसे देश भारत से आगे निकल गए हैं। मोदी की मालदीव यात्रा के बाद भारत पुनः मालदीव में पर्यटक भेजने वाला अव्वल देश बन सकता है। पर्यटन के जरिये लोगों के बीच मेल-मिलाप और सांस्कृतिक विनिमय से कूटनीतिक संबंध प्रगाढ़ ही होते हैं। मालदीव के शिक्षा, स्वास्थ्य और यहां तक की खेलकूद के क्षेत्र में भारत का योगदान निरंतर बढ़ रहा है और यही असली गारंटी है कि चाहे वहां सरकार बदलें या कायम रहें, भारत का प्रभाव इसी प्रकार बना रहेगा।

विदेश नीति आक्रोश भरी प्रतिक्रियाओं या जल्दबाजी के आधार पर सफल नहीं हो सकती। पड़ोसी देशों के संदर्भ में भूगोल चुना नहीं जाता, बल्कि वह पूर्वनिर्धारित होता है। इसलिए भारत ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए शांत, संयमित और संवेदनशील रवैये से काम लिया और तभी मालदीव में पिछले डेढ़ वर्षों में स्थिति बदली है। मोदी सरकार की इस उपलब्धि पर हमें गर्व करना चाहिए और आगे इसी प्रकार के सूझबूझ भरे राजनय की आशा रखनी चाहिए।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सुख की चाह

दुनिया में हर कोई व्यक्ति सुख की चाह में दौड़ता रहता है। वह जीवन भर सुखी रहना चाहता है, लेकिन सुख की यह चाह कब पूरी होगी, वह नहीं जानता। मृगमरीचिका की भांति वह बस भटकता ही रहता है। सुख की चाह ऐसी प्रबल होती है कि वह दुख का कारण बनने लगती हैं। सुख कब दुख में बदल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। जो सुख के क्षण उसके करीब होते हैं वह उसे भी अनुभव नहीं कर पाता। उसे बड़ी खुशी की लालसा रहती है। उसे दीर्घकालिक सुख चाहिए होता है। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि उसका वर्तमान ही उसके सुख का कारण बन सकता है। अगर वह अभी सुख का अनुभव कर रहा है तो निश्चित ही कल भी सब ठीक ही होगा। अगर उसे दुख और विपत्ति को भी हंसते हुए टालने का हुनर आ जाए तो वह दुख के नागपाश में कभी नहीं बंध सकता। फिर वह हर क्षण को सुख से जीने लगेगा। उसे हर परिस्थिति में आनंद की अनुभूति होने लगेगी।

सुख की चाह में दुख की राह का पथिक बनना उचित नहीं है। हमें लगता है कि भौतिक संसाधन सुख का कारण हैं और उनसे हम सुखी रह पाएंगे, यह सत्य नहीं है। संसाधन की अधिकता ही सुख का कारण हो, यह अंतिम सत्य नहीं है। वास्तविक सुख हमारे हृदय के भीतर छिपा हुआ है। उस सुख की खोज हमें स्वयं करनी होगी। हमें अंतर्मन की ओर झांकना होगा। हमारे ऋषि-मुनियों ने कभी संसाधन नहीं जुटाएं। बड़े महल और अट्टालिकाएं नहीं बनाईं। वे झोपड़ी में रहकर भी संतुष्ट थे। यही संतुष्टि उनके सुख का कारण थी। जितना हम आवश्यकताओं एवं अभिलाषाओं का विस्तार करेंगे, उतना ही दुख के निकट होते जाएंगे। सुखी होने के कई कारण हो सकते हैं। दूसरे को खुश देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे की प्रशंसा करके भी सुखी हुआ जा सकता है। बस हमें सुखी होने और खुश रहने के अवसर खोजते रहने चाहिए।

ललित शौर्य

अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली पहल

डा. मोनिका शर्मा

मध्य प्रदेश सरकार ने देहदान और अंगदान करने वालों को गार्ड आफ आनर के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है

मध्य प्रदेश सरकार ने देहदान और अंगदान करने वालों को गार्ड आफ आनर के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर उनके परिजनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है। यह पहल अंगदान और देहदान को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय है। यह किसी का जीवन बचाने में भी सहायक साबित होगी। इससे देहदान के प्रति लोगों की हिचक दूर होगी और अंगदान करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में बदलती जीवनशैली के कारण कई लोग कम आयु में ही गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं।

दुखद यह है कि अंगदान के प्रति सजगता की कमी के कारण कई लोगों का जीवन छिन जाता है। वहीं देहदान के प्रति बेरुखी से चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में बाधा उत्पन्न होती है। देशभर में कई लोग गुर्दा, लिवर, कार्निया और हृदय प्रत्यारोपण के इंतजार में हैं। अंग प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची में शामिल 85 प्रतिशत लोगों को किडनी की आवश्यकता होती है। हमारे देश में औसतन हर 10 लाख लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही अंगदान करता है, जबकि आर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क इंडिया के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख लोगों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट है कि अंगदान के प्रति आमजन की उदासीनता और जागरूकता की कमी के साथ-साथ सरकारी स्तर पर इसकी उपेक्षा भी एक बड़ी समस्या है। जन-जागरूकता लाने और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ऐसी सार्थक पहल स्वागतयोग्य है। केंद्र सरकार ने भी अंगदान करने वालों के परिजनों को रेल में मुफ्त यात्रा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने जैसे निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अंगदान करने वालों के स्वजनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का फैसला किया है।

हालांकि हमारे देश में अंगों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। देहदान के प्रति लोगों में उदासीनता का भाव है। नेशनल आर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट आर्गनाइजेशन की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में कुल 1,099 अंग डोनेट किए गए, जिनमें से तेलंगाना में 252 डोनेशन हुए, जबकि मध्य प्रदेश में यह संख्या मात्र 8 थी। इसलिए, सरकार की सार्थक पहल लोगों को जागरूक बनाकर अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में बैठे मरीजों का जीवन सहेजने में सहायक हो सकती है। नागरिकों की ओर से स्वैच्छिक अंगदान ही अंग प्रत्यारोपण का एकमात्र वैध तरीका है। इस दिशा में प्रशासनिक स्तर पर प्रोत्साहन देने वाली यह पहल अनुकरणीय है। समाज को भी इस मुद्दे पर सकारात्मक भूमिका निभानी होगी और अंगदान करने वालों के परिजनों के योगदान को पहचानने और सराहने का भाव विकसित करना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सैन्य कार्रवाई पर न हो राजनीति

'सैन्य कार्रवाई पर चर्चा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंथन किया गया है। आपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा की मांग इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संसद में अहम विषयों पर विमर्श एक स्वस्थ परंपरा है और सैन्य अभियानों पर चर्चा को लेकर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि अफसोस की बता यही है कि संवेदनशील विषय को भी राजनीतिक रंग देकर केवल हंगामे का माध्यम बना दिया गया है। इसके चलते संसदीय कार्यवाही शोर-शराबे की भेंट चढ़ गई, जबकि इस विषय पर विस्तृत बहस के लिए 29 जुलाई की तिथि पहले ही तय की जा चुकी है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस इस विषय पर जिस प्रकार व्यवहार कर रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक लाभ उठाने की लालसा में विपक्षी दल राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को भी बहस का खिलौना बना रहे हैं। सैन्य अभियानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य गोपनीय रहते हैं, जिन्हें सार्वजनिक करना देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना की गरिमा और गोपनीयता सर्वोपरि है। यह भी सच है कि संसद सवाल पूछने का मंच है, परंतु राष्ट्रहित से ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब देश की सेना शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देती है, तब हमें एकजुट होकर उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए संदेह और शंका फैलानी चाहिए। यही समय की मांग और राष्ट्रधर्म है।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार (हरियाणा)

मेलबाक्स

चिंता बढ़ाती फर्जी मतदाताओं की संख्या

एक सर्वेक्षण के अनुसार 77 लाख फर्जी मतदाता बिहार में हैं, तो यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे देश में इनकी संख्या कितनी होगी। चुनाव आयोग द्वारा फर्जी, मृत और अवैध मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटाने का अभियान 'विशेष गहन पुनरीक्षण' है। चुनाव में सही मतदाता ही वोट करें और फर्जी मतदान न हो सके, ताकि लोकतंत्र की पारदर्शिता-शुचिता बनी रहे, इस हेतु यह एक आवश्यक और अनिवार्य प्रक्रिया है। विपक्ष इस निराधार मुद्दे को जबरदस्ती मुद्दा बना रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। बेहतर होगा कि स्वायत्त संस्थान चुनाव आयोग को अपना कर्तव्य निर्वहन करने दें और इसमें बाधक न बनें। मतदाता सूची के शुद्धीकरण से जुड़ा राष्ट्रहित से जुड़ा यह अभियान देशव्यापी बनाया जाना चाहिए। विपक्ष द्वारा इस अभियान की आलोचना करना भ्रामक और लोकतंत्र के विरुद्ध है। एक आम भारतीय नागरिक जो सही मतदाता है, वह इस अभियान में सहयोग करेगा, न कि इसका विरोध। यह पूरे देश में लागू हो, ताकि फर्जी मतदान पर रोक लग सके। उच्चतम न्यायालय ने अवैध घुसपैठियों को फर्जी मतदान से रोकने की चुनाव आयोग की इस पहल की सराहना की है। यह कोई नागरिकता साबित करने का अभियान नहीं है, लेकिन इससे यह साबित होगा कि आम मतदाता नागरिक वास्तव में भारत का ही है या नहीं। चुनाव आयोग यदि अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है और अपने कर्तव्य का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन कर रहा है तो कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष को उनके इस अभियान पर अंगुली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष यह समझे कि निराधार मुद्दों को जनमानस के बीच मुद्दा बनाने से उनकी ही नकारात्मक छवि बनेगी।

sonimohit895@gmail.com

दूसरे देश भी भारत की राह पर चलें

भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम और सूर्य घर योजनाओं, सोलर पार्कों और विंड कारिडोर जैसी पहलों ने इस पहल से आमजन और उद्योगों को जोड़ा है। जैव ऊर्जा के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। परिणामस्वरूप, भारत जी-20 देशों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनकर उभरा है। दूसरे देश भी भारत प्रेरणा लें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुत सहायता मिलेगी।

budawanwalas55@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

30 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है झारखंड का, जो इसे जैव-विविधता का केंद्र बनाता है। सारंडा का जंगल एशिया का सबसे सघन वन क्षेत्र माना जाता है।

आजकल

मतांतरण के निशाने पर हिंदू

डा. अनुराग सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां विचारों का वैविध्य है। अलग-अलग धर्म, संस्कृति और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। इस वैविध्य के बावजूद देश की एकता बनी हुई है, लेकिन जब भी जलालुद्दीन यानी छांगुर जैसे लोगों द्वारा हिंदुओं के मतांतरण की घटनाएं सामने आती हैं, तो समाज में रहने वाले एक पंथ-समुदाय के लोगों के मन में दूसरे पंथ-समुदाय के खिलाफ असुरक्षा का भाव जागता है। लोग इसे सामूहिक दोष के रूप में लेते हैं, जिससे धार्मिक विद्वेष बढ़ता है

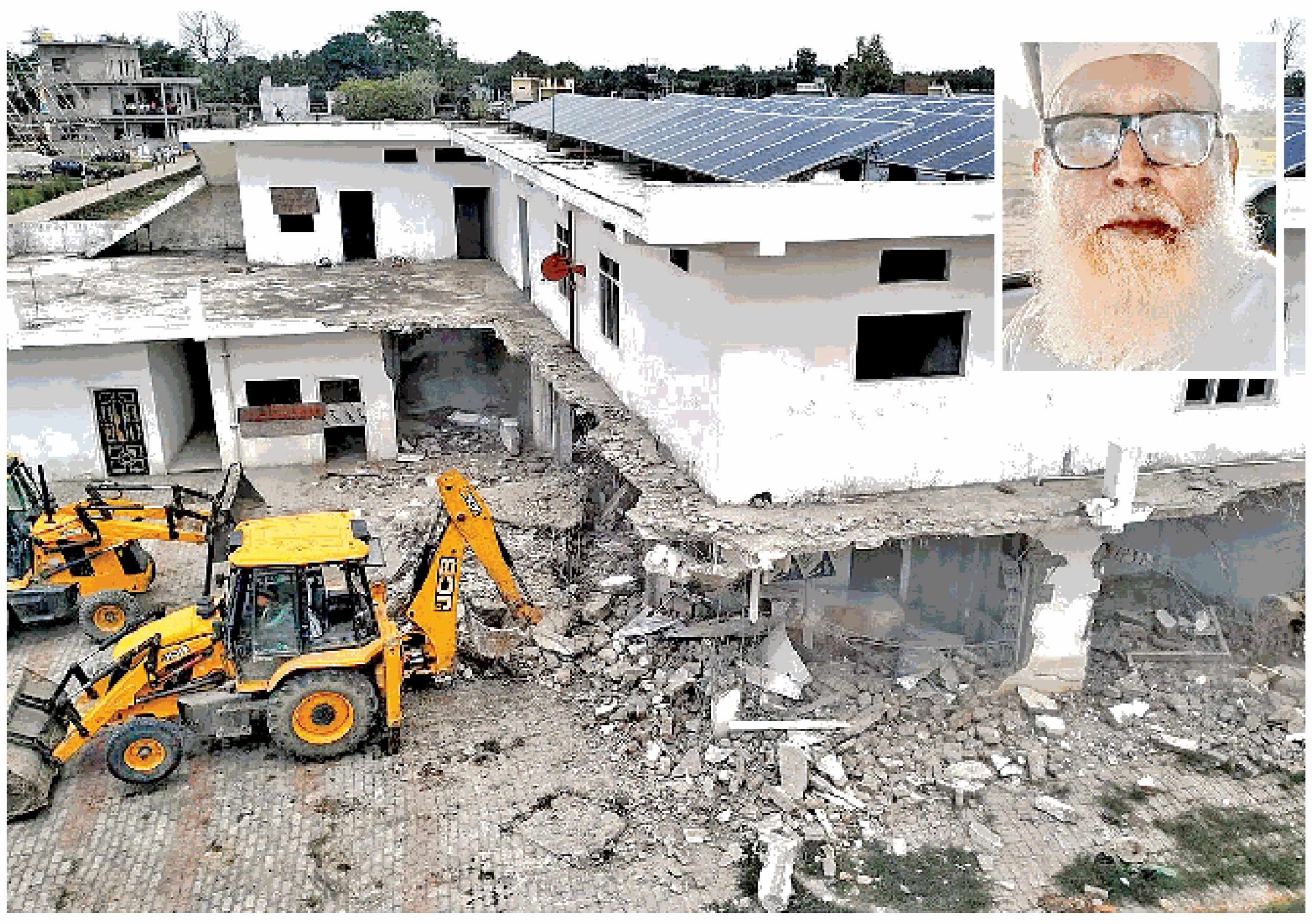
हिंदुओं को साजिशन मतांतरित करने वाले जलालुद्दीन की कोठी पर चला बुलडोजर। फाइल

मानव का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन एक संगठित समाज के रूप में रहने के प्रमाण केवल दस हजार वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। इन वर्षों में मानव समाज ने धीरे-धीरे विकास किया है। विभिन्न सभ्यताओं के विकास के क्रम में मनुष्य ने कलाओं और धर्म का विकास किया, जो उन सभ्यताओं की नींव बने। धर्म हमेशा से समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। भारतीय परंपरा में इसे 'धार्यते इति धर्मः' के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म ने लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा दी, नैतिक मूल्यों का विकास किया और आदर्श स्थापित किए, जिससे इसकी जड़ें समाज में मजबूती से जम गईं। हालांकि वर्तमान समय में कुछ लोग धर्म को व्यापार का साधन बना रहे हैं और इसके माध्यम से अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। हाल में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में छांगुर के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर, जिसका असली नाम जलालुद्दीन है, हिंदू युवतियों और अन्य गैर-मुस्लिम युवतियों को आर्थिक प्रलोभन और धोखे से इस्लाम में मतांतरित करने का कार्य कर रहा था। इसके लिए उसने एक रेट कार्ड तैयार किया था, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के अनुसार छह से 15 लाख रुपये तक का भुगतान कर उन्हें इस्लाम में मतांतरित किया जाता था।

इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में सक्रियता दिखाई और कहा जा रहा है कि इसने अब तक सैकड़ों हिंदुओं के इस्लाम में मतांतरण कराए हैं। जांच के दौरान छांगुर और इसके सहयोगियों के कई बैंक खातों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का पता चला है, जिसमें से बहुत सारा धन विदेश से आया है। छांगुर ने कई बार विदेश यात्रा भी की है। यह स्पष्ट है कि यह पूरा नेटवर्क विदेशी फंडिंग से संचालित हो रहा था। इस मामले में कुछ अधिकारियों की संलिप्तता का संदेह भी उठ रहा है, जो भारतीय समाज और प्रशासन के लिए चिंताजनक है। सवाल यह है कि सैकड़ों मतांतरण कराने वाला व्यक्ति समाज में आराम से कैसे रह रहा था? मत परिवर्तन का यह खेल चल रहा था, तो कानून-प्रशासन और समाज कहां थे? छांगुर, जो पहले साइकिल पर घूमकर माला, अंगूठी और ताबीज बेचता था, ने अचानक एक आलीशान कोठी कैसे बना लिया? यह कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिसे अब उजागर होने के बाद तोड़ दिया गया है। क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह जिस जमीन पर कोठी बना रहा था, वह उसकी नहीं है?

जब जबरन मतांतरण पर राज्य सरकारें कानून बना रही थीं, तब कुछ राजनीतिक दलों ने काफी हो-हल्ला मचाया था, लेकिन इसी तरह की घटनाओं के कारण यह कानून अब आवश्यक लगने लगा है। हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन यहां तो धन और अन्य प्रलोभनों के माध्यम से कम उम्र के युवाओं का मानसिक बहलाव कर उनके पंथ को बदलने का पूरा धंधा चल रहा है। दुनिया के कई देशों में ईसाई और इस्लाम पंथ के द्वारा प्रलोभन देकर धार्मिक मतांतरण का खेल छुपा हुआ नहीं है। भारत के कई गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई धार्मिक समूहों द्वारा इस तरह के कुकृत्य सामने आते रहे हैं। जानबूझकर गरीब लोगों को ये समूह अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए पेट का सवाल होता है और धन के लालच में वे बहकावे में आ जाते हैं। इन सबमें बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग शामिल है। यदि मदद करने का भाव है, तो क्या बिना पंथ बदले यह नहीं किया जा सकता? क्या गरीबों की आर्थिक मदद के लिए मत परिवर्तन करना सौदेबाजी की संज्ञा में नहीं आएगा? मदद का भाव बिना किसी आशा और उम्मीद के होता है, जिसमें आत्मसंतोष का प्रमुख भाव होता है। धर्म बदलने की शर्त ही इस पूरे खेल को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। यहां भाव मदद करने या मानवता का नहीं है, बल्कि अपने पंथ का प्रसार करना है।

भारत में अंग्रेजी हुकूमत के समय ईसाई मिशनरियों ने भी अपने धर्म का प्रचार-प्रसार ही लक्ष्य बनाया था। वर्तमान समय में अपनी पहचान छुपाकर युवतियों से प्रेम प्रसंग के मामले इसका एक अन्य कुत्सित रूप है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां विचारों का वैविध्य है। अलग-अलग धर्म, संस्कृति और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। इस वैविध्य के बावजूद देश की एकता बनी हुई है, लेकिन जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो समाज में रहने वाले एक पंथ-समुदाय के लोगों के मन में दूसरे पंथ-समुदाय के खिलाफ असुरक्षा का भाव जागता है। सामान्य शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोग इसे सामूहिक दोष के रूप में लेते हैं, जिससे धार्मिक विद्वेष बढ़ने की आशंका बनती है। ऐसे कृत्य सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। मतांतरित व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित करने वाला, आत्मग्लानि और अंतर्द्वंद्व से भरने वाला होता है। मूल पहचान और संस्कृति को छोड़ने पर मजबूर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है।

संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से धर्म अपनाने, प्रचार करने और आचरण करने का अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कर इसका भी हनन किया जाता है। जब धर्म जबरन थोपा जाने लगे, तो उसकी मूल भावना विकृत हो जाती है। इसलिए जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें बिना किसी लाग-लपेट के इसका तार्किक खंडन करना चाहिए।

सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा पर भी संकट

ममता कुशवाहा

हाल में उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में मतांतरण के मामलों ने कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं। यह विषय केवल एक धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि देश की समग्र अखंडता, युवाओं के मानसिक गठन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। यह नेटवर्क विशेषकर कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों की युवतियों को निशाना बना रहा था। उन्हें शिक्षा, नौकरी, शादी और बेहतर जीवन के सपने दिखाकर मत परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस क्रम में ''लव जिहाद'', ''प्रोजेक्ट'', ''प्लान'' जैसे शब्दों का प्रयोग करके योजनाएं चलाई जा रही थीं, जिनके तहत लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर दबाव या छल से मतांतरण कराया जाता है। मतांतरण के लिए पैसे का लेन-देन भी सामने आया है, जिसमें प्रति व्यक्ति 100 से 500 डालर तक की रकम दान के रूप में दी गई। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भावनात्मक प्रभाव डालने, मुस्लिम पहचान छुपाकर संपर्क बनाने और इस्लामी शिक्षकों द्वारा आनलाइन 'इस्लामिक मिशन'' चलाने जैसी गतिविधियों की भूमिका भी उजागर हुई है।

धार्मिक स्वतंत्रता भारत का संवैधानिक अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, परंतु जब इस अधिकार का प्रयोग धोखे, दबाव, प्रलोभन या भय के माध्यम से कराया जाए, तो वह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है। यह न केवल व्यक्ति की आस्था के साथ छल है, बल्कि संविधान और कानून की भावना के विरुद्ध भी है। यदि यह साजिश जारी रही, तो यह देश की बहुलतावादी संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता के लिए घातक सिद्ध होगी। इन गतिविधियों से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक तंत्र को इस विषय पर और अधिक सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों के बीच के संजाल को तोड़ने के लिए तकनीकी संसाधनों और मानव नेटवर्क की मजबूती की आवश्यकता है। मिशन अस्तित्व जैसे अभियानों को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए, ताकि धार्मिक छलावे के शिकार लोगों को बचाया जा सके और युवाओं को जागरूक किया जा सके। साथ ही इस प्रकार के मामलों की विवेचना केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे समाप्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करनी होगी।

सरकार के साथ-साथ समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों को चाहिए कि वे समाज में सौहार्द और संवाद का वातावरण बनाएं। लोगों को उनके धर्म, संस्कृति और परंपराओं की वास्तविक समझ दी जाए, ताकि वे प्रलोभन या छल से प्रभावित न हों। खासकर युवा वर्ग को डिजिटल साक्षरता, मानसिक परिपक्वता और संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा देकर उन्हें ऐसे तत्वों से दूर रखा जा सकता है। धार्मिक नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कट्टरता या नफरत फैलाने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये घटनाएं केवल धार्मिक या सुरक्षा संकट नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक-राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह भारत जैसे लोकतांत्रिक, बहुसांस्कृतिक और संवेदनशील राष्ट्र की स्थिरता को अंदर से खोखला कर सकती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि शासन, प्रशासन, मीडिया, समाज और धर्माचार्य मिलकर इस प्रकार के षड्यंत्रों को बेनकाब करें और राष्ट्र की एकता, अखंडता और आत्मा की रक्षा करें। मतांतरण के नाम पर फैलाए जा रहे इस विध्वंसक जाल को केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और साझा जिम्मेदारी से ही काटा जा सकता है।

(लेखिका शिक्षक हैं)

खरी-खरी

सावन में पवन का शोर

रोहित कौशिक

'सावन का महीना, पवन करे शोर'- यह गीत गुनगुनाने वाले शायद ही जानते हैं कि सावन में पवन का शोर क्यों होता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एक व्यक्ति ने सोचा कि शायद पवन का शोर इसलिए है, क्योंकि सावन में लोग बाहर निकलते हैं। इसी सोच के चलते डाक्टरों ने सलाह दी कि सावन में सुपाच्य भोजन करना चाहिए, लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने इस विचार को नकारते हुए कहा कि असल में सावन में बारिश का शोर ज्यादा होता है। पवन का शोर तो अप्रैल-मई में होता है, जब तेज आंधी-तूफान आते हैं। इसलिए उसके अनुसार, यह गीत होना चाहिए 'सावन का महीना, बारिश करे शोर'।

फिर एक तीसरे व्यक्ति ने दोनों की बातों को खारिज करते हुए कहा कि सावन में बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं। इन आपदाओं के कारण बड़े-बड़े मकान धराशायी होते हैं और सरकारी घोषणाओं का शोर भी सुनाई देता है। इस प्रकार, यह गीत वास्तव में सरकारी घोषणाओं के शोर को दर्शाता है। हमारे देश में घोषणाओं का शोर इतना अधिक है कि यह सब कुछ गड्डमड्ड कर देता है। सरकार चाहती है कि शोर होता रहे, ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। पूरे साल मंत्री दौरे नहीं कर पाते, लेकिन सावन में बाढ़ के दौरे करने का मौका मिल जाता है। इस कारण, सावन में सरकारी घोषणाओं का शोर बढ़ जाता है। सावन में कुछ लोग 'सावन में लग गई आग' गुनगुनाते हैं। जब एक दल की घोषणाओं की खबर दूसरे दल को मिलती है, तो आग लगना स्वाभाविक है। इस आग के चलते दूसरे दल के लोग इन घोषणाओं को फर्जी बताने लगते हैं। इस प्रकार, सावन में आग लगना और पवन का शोर करना महत्वपूर्ण घटनाएं बन जाती हैं। सावन में राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सावन सभी आरोपों को धो भी देता है।

जब एक युवती बारिश में 'टिप-टिप बरसा पानी' गाती है, तो कुछ को गंदगी नजर आती है, जबकि कुछ इसे पावन मानते हैं। इससे उनकी भक्ति पवित्र हो जाती है। प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है, इसलिए सावन में प्रेम की भावना उमड़ने लगती है।

X पोस्ट

कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री ने एलान किया कि भारत 'विश्व की फूड बास्केट' के रूप में उभरेगा। क्या वह इसे संभव बनाने का कोई खाका बता सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज चेन के अभाव में उपज का एक बड़ा हिस्सा तो सड़कर बेकार चला जाता है।

तवलीन सिंह @tavleen_singh

मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे क्रिकेट के कुछ यादगार क्षणों का साक्षी बनने का अवसर मिला, लेकिन पैर में तगड़ी चोट के बावजूद रिषभ पंत का मैनचेस्टर में बल्लेबाजी के लिए उतरना और हर किसी की उस पर गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया बहुत भावुक करने वाली रही।

हर्षा भोगले @bhogleharsha

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के सार को समझें तो इसके अस्तित्व में आने से जहां ब्रिटेन से भारत आने वाली कारें, व्हिस्की, चाकलेट, बिस्कुट सस्ते होंगे, वहीं भारत से जाने वाले कपड़े, जूते, ज्वैलरी, स्मार्टफोन,फल, दवाई और मसालों पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और उनके लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा।

मिलिंद खांडेकर @milindkhandekar

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा को फिर से शुरू करने का फैसला सही है?

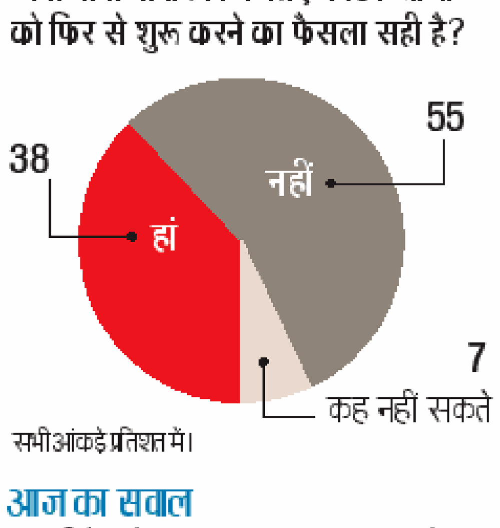

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नया बहाना ढूंढकर हंगामा हो रोज,
देखो कैसे सांसद लाते हैं हम खोज!
लाते हैं हम खोज समय करते जो जाया,
चुनकर ऐसे लोग भला हमने क्या पाया??
लोकतंत्र का आप बिगाड़ें ताना-बाना,
हंगामे हित ढूंढ-ढूंढ नित नया बहाना!!

- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

पर्यटन के क्षेत्र में नया अध्याय

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध खनिज संपदा और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। अब यह प्रांत पर्यटन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि सैलानियों का ध्यान न केवल इसकी खनिज संपदा, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, झरनों, जंगलों, वन्यजीवों और सांस्कृतिक धरोहर की ओर भी जाए। इस मुहिम को और आकर्षक बनाने के लिए झारखंड के गौरव, क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धौनी को चुना गया है। धौनी अब झारखंड की खूबसूरती को विश्व पटल पर लाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। झारखंड का प्राकृतिक सौंदर्य किसी कविता से कम नहीं है। रांची के आसपास के खूबसूरत झरने जैसे दशम फाल्स, जोन्हा फाल्स और हुंडरू फाल्स सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन झरनों की शीतल धारा और आसपास की हरियाली मन को शांति प्रदान करती है। पतरातू की घुमावदार घाटी, जो अपने मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। इसके अलावा, नेतरहाट, जिसे ''झारखंड की रानी'' कहा जाता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। ये स्थान न केवल सौंदर्य के प्रतीक हैं, बल्कि साहसिक गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी के लिए भी उपयुक्त हैं।

झारखंड का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो इसे जैव-विविधता का केंद्र बनाता है। सारंडा का जंगल, जो एशिया का सबसे सघन वन क्षेत्र माना जाता है, अपनी 700 पहाड़ियों और अनगिनत वन्यजीवों के साथ सैलानियों को रोमांचित करता है। यहां की वनस्पतियां और जीव-जंतु, विशेष रूप से हाथी और बाघ इसे वन्यजीव पर्यटन के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। झारखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी खजाना है। देवघर, जहां देश के ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम स्थित है, देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। श्रावण मास में यहां का मेला और कांवड़ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा, रजरप्पा मंदिर, मलूटी के प्राचीन मंदिर और पारसनाथ की पहाड़ियां जैन धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं। झारखंड की सांस्कृतिक विविधता भी इसे खास बनाती है। आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य जैसे छऊ, पाइका और पारंपरिक हस्तशिल्प सैलानियों को झारखंड की जीवंत परंपराओं से परिचित कराते हैं। सरकार इन सांस्कृतिक धरोहरों को पर्यटन के साथ जोड़कर स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।

धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का खजाना है झारखंड। फाइल

झारखंड ने पर्यटन के क्षेत्र में एक अनूठा कदम उठाया है-खनन पर्यटन। सैलानी अब गहरे खदानों में उतरकर खनन की प्रक्रिया को करीब से देख सकेंगे। यह न केवल रोमांचकारी अनुभव होगा, बल्कि झारखंड की खनिज संपदा और इसके आर्थिक महत्व को समझने का अवसर भी प्रदान करेगा। कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध झारखंड इस अनूठी पहल के माध्यम से पर्यटकों को एक नया दृष्टिकोण देगा। झारखंड का पर्यावरण वन्यजीवों के लिए अनुकूल है। यहां हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं। हाल के वर्षों में बाघों की वापसी ने इस क्षेत्र को और आकर्षक बना दिया है। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को संतुलित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे इको-टूरिज्म सर्किट का विकास और जंगल सफारी की व्यवस्था।

सरकार ने महेंद्र सिंह धौनी को झारखंड पर्यटन का ब्रांड एंबेसडर बनाकर एक मास्टरस्ट्रोक खेला है। धौनी का जुड़ाव झारखंड को पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धौनी की अपील और उनके प्रचार अभियानों के जरिए सैलानियों को न केवल झारखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की ओर आकर्षित किया जाएगा, बल्कि यह संदेश भी दिया जाएगा कि झारखंड हर प्रकार के पर्यटक के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आता है। धौनी का प्रचार इसे वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि पर्यटन के विकास में कई चुनौतियां भी हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे सड़क, परिवहन और आवास सुविधाएं, अभी भी कई क्षेत्रों में अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, जागरूकता की कमी और प्रचार की अपर्याप्त रणनीतियां भी बाधा बन सकती हैं। हालांकि, सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे इको-टूरिज्म सर्किट का निर्माण, होटल और रिजार्ट्स की स्थापना, और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से प्रचार। धौनी जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का सहयोग इन चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंथन

शोध को मिलती महत्ता

पीयूष कुमार दुबे
सहायक प्राध्यापक, कालेज आफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय

चार वर्षीय स्नातक पद्धति उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ भविष्य में भारत को एक वैश्विक ज्ञान-शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत की शैक्षिक संरचना में एक युगांतकारी परिवर्तन के रूप में सामने आई है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहु-विषयक तथा वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इस नीति के अनेक नवाचारपूर्ण प्रविधानों में एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि स्नातक उपाधि को चार वर्षीय स्वरूप प्रदान करते हुए उसमें शोधात्मक दृष्टिकोण को समाहित किया गया है। यह प्रविधान विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा के प्रारंभिक चरण से ही जिज्ञासा, नवाचार और आलोचनात्मक चिंतन की भावना को विकसित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब तक देश में स्नातक स्तर की शिक्षा मुख्यतः त्रिवर्षीय पद्धति पर आधारित रही है, जिसमें छात्रों को उनकी अभिरुचि एवं विषयवृत्ति के अनुरूप अनुशासन-केंद्रित अध्ययन का विकल्प उपलब्ध कराया जाता था। नई नीति इस ढांचे से आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को शोध-आधारित अधिगम की ओर प्रेरित करती है, जिससे वे केवल ज्ञान के उपभोक्ता ही न रहें, अपितु ज्ञान के सर्जक भी बन सकें।

चार वर्षीय स्नातक पद्धति की प्रमुख विशेषता इसका लचीलापन है, जो इसे पारंपरिक त्रिवर्षीय पद्धति से विशिष्ट बनाता है। इस पद्धति के लचीलेपन का सर्वाधिक सराहनीय पक्ष यह है कि यह स्नातक के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान किसी कारणवश शिक्षा अधूरी रह जाने की स्थिति में भी एक व्यवस्थित मान्यता प्रदान करती है। इस प्रणाली में छात्र यदि एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हैं तो उन्हें प्रमाणपत्र, दो वर्षों के उपरांत डिप्लोमा, तीन वर्षों पर स्नातक उपाधि और चार वर्षों पर स्नातक के साथ-साथ शोध आधारित उपाधि प्राप्त होती है। छात्रों को यह सुविधा भी है कि वे जब चाहें अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। इसके विपरीत त्रिवर्षीय पद्धति में यदि विद्यार्थी किसी कारणवश शिक्षा बीच में छोड़ देते थे, तो उनके अध्ययन को कोई औपचारिक मान्यता नहीं मिलती थी और वे पूरी शिक्षा पुनः आरंभ करने के लिए विवश हो जाते थे। इस दृष्टि से चार वर्षीय प्रणाली अधिक संवेदनशील, समावेशी और यथार्थपरक है, जो छात्रों की विविध परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में बनाए रखने का अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षा क्षेत्र में न केवल एक संरचनात्मक सुधार है, अपितु शिक्षा को अधिक मानवीय और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल भी है।

चार वर्षीय स्नातक पद्धति का एक लाभ यह भी है कि इसके उपरांत विद्यार्थी सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए पात्र हो जाते हैं और पीएचडी में प्रवेश हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि छात्र अपनी स्नातक उपाधि न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक (या समकक्ष ग्रेड) के साथ पूर्ण करता है, तो उसे परास्नातक डिग्री की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह परिवर्तन न केवल शैक्षणिक मार्ग को अधिक लचीला और सुलभ बनाता है, अपितु समय और संसाधनों की बचत करते हुए विद्यार्थियों को शीघ्र ही अनुसंधान की दिशा में अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों के लिए अकादमिक उत्कृष्टता की राह को अधिक स्पष्ट और सुगम बनाने वाली है।

चार वर्षीय स्नातक पद्धति का एक उद्देश्य देश में शोध की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना भी है। पारंपरिक प्रणाली में प्रायः ऐसा होता था कि अनेक छात्र बिना पर्याप्त अभिरुचि या तैयारी के केवल शैक्षणिक अनिवार्यता के कारण शोध में प्रविष्ट होते थे, जिससे शोध की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। नई प्रणाली इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। इसमें गहन अध्ययन और अनुसंधान के अवसर केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सुलभ होंगे जो वास्तव में गंभीर अध्येता हैं और शोध के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। वहीं जिन छात्रों की रुचि शोध में नहीं है, वे तीन वर्षों के भीतर ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपनी इच्छित दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार यह पद्धति न केवल छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं का सम्मान करती है, अपितु उच्चतर शिक्षा में गुणवत्तायुक्त शोध के प्रोत्साहन की भी मंशा रखती है। चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती महाविद्यालय के शिक्षकों के समक्ष पारंपरिक शिक्षण के साथ इस नवीन अनुसंधान आधारित शिक्षण का तालमेल बिठाने की भी आएगी। यह चुनौती बाह्य व्यवस्था से अधिक शिक्षक की मानसिक तैयारी की है। इससे निपटने का कार्य शिक्षक को स्वयं ही करना होगा। वस्तुतः इस बदलते समय में शिक्षकों को स्नातक स्तर पर छात्रों के अनुसंधान का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही एनईपी-2020 में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया गया है।

शिक्षा को अधिक मानवीय और व्यावहारिक बनाने की पहल। फाइल

****

नेस्ले इंडिया का मुनाफा घटकर 646 करोड़ रुपये

नई दिल्ली : दैनिक उपभोग की वस्तुएं बनाने वाली प्रमुख कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड का अप्रैल-जून 2025 तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 13.4 प्रतिशत घटकर 646.59 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 746.6 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की उत्पाद बिक्री से आय 5.86 प्रतिशत बढ़कर 5,073.96 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले की इसी तिमाही में 4,792.97 करोड़ रुपये थी। (प्रेट्र)

पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआइपी) के जरिये 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाना बैंक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास का प्रतीक है।
— सीएस शेट्टी, चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक

संसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डालर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
82,184.17 ▼ 542.47	25,062.10 ▼ 157.80	₹ 99,620 ▼ ₹1,400	₹1,15,000 ▼ ₹3,000	₹86.40 ▼ ₹0.01	$69.36

किसान, मछुआरे और छोटे उद्यमियों को होगा लाभ

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते से रोजगारपरक सेक्टर से लेकर कृषि उत्पाद के निर्यात में होगी बढ़ोतरी

राजीव कुमार • जागरण

नई दिल्ली: विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते की दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत ने गुरुवार को ब्रिटेन के साथ कंप्रेहेंसिव इकोनमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (सीटा) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से टेक्सटाइल, लेदर और फुटवियर आइटम, इलेक्ट्रानिक्स, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स गुड्स, खिलौने, दवा, केमिकल्स जैसे रोजगारपरक सेक्टर के साथ भारत के कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि इन सभी वस्तुओं के निर्यात पर ब्रिटेन में अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब तक इन वस्तुओं पर आठ प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक का शुल्क लगता था।

कृषि उत्पाद में मुख्य रूप से फल, सब्जी, बासमती चावल, अन्य अनाज, अचार, तैयार भोजन के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगने से किसानों को जहां लाभ मिलेगा वहीं रोजगारपरक सेक्टर का निर्यात बढ़ने से एमएसएमई लाभान्वित होंगे। भारतीय एमसएमई अब ब्रिटेन की सरकारी खरीद में हिस्सा ले सकेंगे। दोनों देशों ने सीटा के तहत अपने वर्तमान के 56 अरब डालर के व्यापार को 2030 तक 112 अरब डालर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। सीटा पर अगले एक साल में अमल होने की उम्मीद है।

- ब्रिटेन संग कंप्रेहेंसिव इकोनमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के एक साल में अमल में आने की उम्मीद
- समझौते के तहत भारतीय एमएसएमई ब्रिटेन की सरकारी खरीद में भी हिस्सा ले सकेंगे

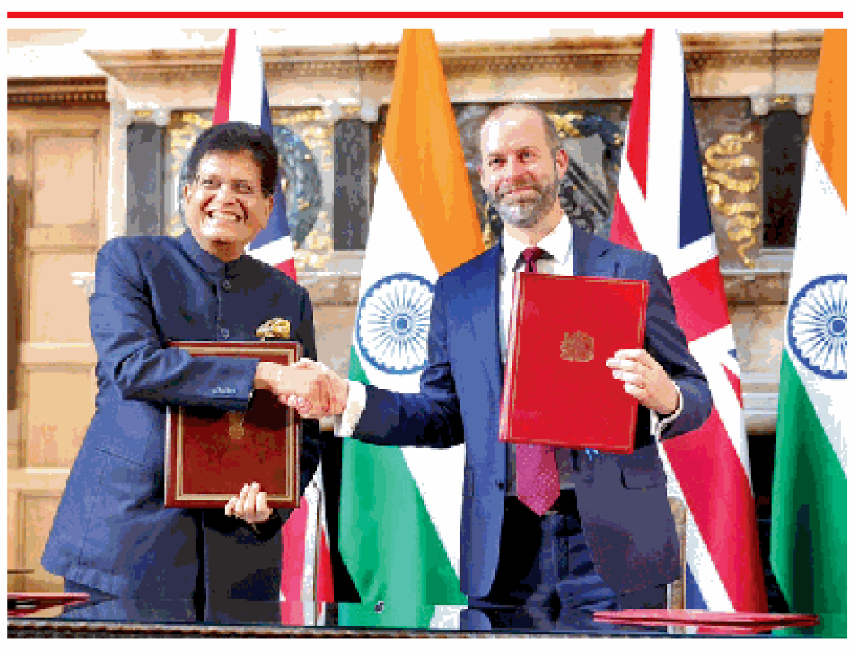

लंदन में गुरुवार को व्यापार समझौते के बाद अपने ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनाल्ड से हाथ मिलाते वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल।

बांग्लादेश के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे भारतीय टेक्सटाइल उत्पाद : वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन अभी सालाना 27 अरब डालर के टेक्सटाइल और गारमेंट का आयात करता है और इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.79 अरब डालर की है। व्यापार समझौता होने से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय टेक्सटाइल उत्पाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों से सस्ते हो जाएंगे। इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। मंत्रालय को उम्मीद है कि ब्रिटेन के बाजार में लेदर व फुटवियर आइटम के निर्यात में भी अगले एक-दो साल में पांच-छह प्रतिशत का इजाफा होगा। ब्रिटेन अभी चीन और वियतनाम से सबसे अधिक इलेक्ट्रानिक्स आइटम का निर्यात करता है, लेकिन शून्य शुल्क होने से इलेक्ट्रानिक्स का निर्यात भी बढ़ेगा। ब्रिटेन में जेम्स व ज्वेलरी निर्यात बढ़ाने की पूरी गुंजाइश है। ब्रिटेन सालाना तीन अरब डालर के ज्वेलरी का आयात करता है जबकि भारत ब्रिटेन में सालाना सिर्फ 40 करोड़ डालर के ज्वेलरी का निर्यात करता है।

व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन के बाजार में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क

आइटम	वर्तमान शुल्क (प्रतिशत तक)	समझौते के बाद का शुल्क
समुद्री उत्पाद	20	शून्य
लेदर फुटवियर	16	शून्य
टेक्सटाइल व अन्य कपड़े	12	शून्य
प्रोसेस्ड फूड्स	70	शून्य
फल, सब्जी, अनाज	8-20	शून्य
इलेक्ट्रिकल मशीनरी	14	शून्य
जेम्स व ज्वेलरी	4	शून्य
केमिकल्स	8-14	शून्य

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय

महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार की अर्थव्यवस्था को होगा फायदा

शुल्क अधिक होने के कारण भारत ब्रिटेन के बाजार में कृषि पदार्थों का काफी कम निर्यात कर रहा था। ब्रिटेन कृषि उत्पाद व अन्य खाद्य पदार्थों का सालाना 37.52 अरब डालर का आयात करता है और इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 81 करोड़ डालर की है। अब शुल्क समाप्त होने से भारत से चाय, बासमती चावल, अंगूर, आम, मसाला, प्याज, मखाना, लीची, सब्जी जैसे विभिन्न आइटम के निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी। कृषि उत्पाद के निर्यात का रास्ता खुलने से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, केरल व उत्तर पूर्व के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा।

ब्रिटेन सालाना 50 अरब डालर के प्रोसेस्ड फूड्स का करता है आयात

इसी तरह, ब्रिटेन सालाना 5.4 अरब डालर के समुद्री उत्पादों का आयात करता है और इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.25 प्रतिशत की है। अब शुल्क समाप्त होने से ब्रिटेन में समुद्री उत्पादों के निर्यात का रास्ता साफ होगा, जिससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, उड़ीसा जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा। समुद्री उत्पाद के साथ प्रोसेस्ड फूड्स के निर्यात को लेकर भी ब्रिटेन में बड़ी संभावना दिख रही है। ब्रिटेन सालना 50 अरब डालर के प्रोसेस्ड फूड्स का आयात करता है और इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 31 करोड़ डालर की है।

कारोबार में गेमचेंजर साबित होगा समझौता : उद्योग जगत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: गुरुवार को लंदन में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को इंडिया इंक ने ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है।

सीआइआइ, फिक्की, एसोचैम, एक्मा, फियो जैसे उद्योग संगठनों के अलावा देश के जाने माने उद्योगपतियों ने भी इसे भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों में युगांतकारी बदलाव लाने वाला बताया है और कहा है कि यह भारतीय उद्योग जगत के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। कुछ लोगों ने इसे दोनों देशों के कारोबारी व निवेश संबंधों के लिए गेमचेंजर बताया है। पीएम नरेन्द्र मोदी के ब्रिटेन दौरे में सीआइआइ के 16 प्रमुख उद्योगपति भी शामिल हैं जो समझौते के साक्षी बने हैं। सीआइआइ ने कहा, 'यह समझौता भारत व ब्रिटेन के बीच कारोबार की कई सारी बाधाओं को समाप्त करेगा, जिससे दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच कई स्तरों पर संयुक्त उद्यमों से लेकर संयुक्त शोध व सहयोग स्थापित होगा। यह दोनों देशों में समावेशी विकास की राह आसान करेगा।' कारोबार सलाहकार फर्म डेलाइट के साझेदार अनिल तलरेजा का कहना है कि यह दोनों देशों के लिए अपने पारंपरिक निवेश व कारोबारी संबंधों में व्यापक बदलाव लाने का अवसर देगा।

भारत-यूके एफटीए भारतीय उद्योग के लिए गेमचेंजर साबित होने जा रहा है। इससे भारत का निर्यात भी बढ़ेगा और मैन्यूफैक्चरिंग को भी बहुत फायदा होगा। टैक्सटाइल व लेदर जैसे उद्योग को खास तौर पर फायदा होता हम देख रहे हैं। भारत ने भविष्य में विश्व के मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने का लक्ष्य रखा है जिसे यह समझौता साकार करेगा।
-संजय नायर, प्रेसिडेंट, एसोचैम

दोनों देश अभी एआइ आधारित व्यवस्था और डिजिटल बदलाव पर जोर दे रहे हैं। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों में सहयोग की बुनियाद तैयार कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्र में भारत में अपार संभावनाएं हैं जिसमें अब ब्रिटिश कंपनियों का सहयोग बढ़ेगा।
कमल नाहटा, एमडी, एचएफसीएल

एक नजर में

पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ इरडा के चेयरमैन नियुक्त

नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को वित्त एवं आर्थिक मामलों के विभाग के पूर्व सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) का चेयरमैन नियुक्त किया। चेयरमैन के रूप में सेठ की नियुक्ति को तीन साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए मंजूरी दे दी है। देबाशीष पांडा के इस साल मार्च में कार्यकाल पूरा होने के बाद लगभग चार महीने पश्चात इरडा के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। (प्रेट्र)

केनरा बैंक के शुद्ध लाभ में 22 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली : केनरा बैंक का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 22 प्रतिशत बढ़कर 4,752 करोड़ रुपये हो गया। गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 3,905 करोड़ रुपये रहा था। समीक्षाधीन अवधि में उसकी कुल आय बढ़कर 38,063 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 34,020 करोड़ रुपये थी। बैंक द्वारा अर्जित ब्याज इस दौरान बढ़कर 31,003 करोड़ रुपये हो गया। (प्रेट्र)

मारुति का निर्यात 96 हजार इकाई के पार

नई दिल्ली : मारुति सुजुकी इंडिया ने अप्रैल-जून तिमाही में 96,000 से ज्यादा गाड़ियों का निर्यात किया है। कंपनी ने बताया कि उसका माडल फ्रान्क्स भारत से सबसे तेजी से एक लाख इकाई के निर्यात को पार करने वाला स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन बन गया है। अप्रैल-जून तिमाही में भारत से यात्री वाहन निर्यात में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत रही। कंपनी वर्तमान में लगभग 100 देशों को 17 माडल का निर्यात करती है। 2024-25 में निर्यात 3.3 लाख इकाइयों को पार कर गया था। (प्रेट्र)

आचरण से करदाताओं का विश्वास अर्जित करें अधिकारी : सीतारमण

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 166वें आयकर दिवस पर सोमवार को आयकर अधिकारियों से नीतियों के क्रियान्वयन में मानक ऊंचा करने और अपने आचरण से करदाताओं का विश्वास अर्जित करने को कहा।

अधिकारियों द्वारा नई तकनीक अपनाने और छह महीनों में नए आयकर विधेयक का मसौदा तैयार करने में उनकी तत्परता की सराहना करते हुए सीतारमण ने उन्हें जल्द से जल्द ओजीई के लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रेरित किया। ओजीई एक ऐसा आदेश है जो एक आयकर अधिकारी को तब पारित करना होता है जब कोई करदाता कर निर्धारण के विरुद्ध अपील में विभाग के विरुद्ध मुकदमा जीत जाता है।

भारत में ब्रिटेन की कार और शराब होगी सस्ती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते से अब ब्रिटिश कार और शराब दोनों ही पहले की तुलना में कम कीमत पर मिलेंगी। भारत ने इन वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में कटौती का फैसला किया है। इसके अलावा ब्रिटेन के मेडिकल उपकरण, अंतरिक्ष यान से जुड़े पार्ट्स, चाकलेट्स और प्रसाधन के सामान और कई खाद्य पदार्थों पर भी शुल्क में छूट दी गई है।

कार व शराब को छोड़ अन्य वस्तुओं पर पहले औसतन 15 प्रतिशत का शुल्क लगता था जो अब तीन प्रतिशत रह जाएगा। हालांकि, भारत की तरफ से डेरी उत्पाद, सेब, ओट्स व खाद्य तेल के आयात पर शुल्क में छूट नहीं दी गई है। अभी ब्रिटेन भारत में 8.6 अरब डालर का निर्यात करता है और इनमें से 94 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क लगता है। सालमन (एक प्रकार की मछली), लैंब (मेमने का गोश्त), एयरक्राफ्ट्स पार्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रानिक्स पर समझौता के अमल में आते ही शुल्क से छूट दे दी जाएगी। वहीं चाकलेट, आटो पार्ट्स, आटोमोबाइल, साबुन, परफ्यूम जैसे सौंदर्य प्रसाधन के सामान पर चरणबद्ध तरीके से 10 साल में शुल्क में कटौती होगी।

पैसेंजर कार के आयात पर शुल्क में छूट के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। 3000 सीसी से ऊपर की क्षमता वाली पेट्रोल कार के आयात पर अभी 110 प्रतिशत का शुल्क लगता है, जिसे घटाकर अब 30 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले साल इस क्षमता वाली 10,000 कार इस दर पर आयात की जा सकेंगी। हर साल शुल्क में पांच प्रतिशत की कटौती की जाएगी जो 10 प्रतिशत पर जाकर स्थिर हो जाएगा। 1500 सीसी क्षमता वाली 20,000 कार पहले साल आयात होंगी और इस पर 66 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। दूसरे साल से हर साल इनके शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती होगी और जो 10 प्रतिशत पर स्थिर हो जाएगा। ब्रिटिश शराब पर अभी 150% का शुल्क लगता है जिसे 10 साल में 75% तक ला दिया जाएगा। समझौते पर अमल के पहले साल ब्रिटिश शराब पर 110% का शुल्क लगेगा।

- चाकलेट, साबुन और परफ्यूम जैसे सौंदर्य प्रसाधन के समान पर भी शुल्क में होगी कटौती
- व्यापार समझौते में डेरी, सेब, ओट्स और खाद्य तेल पर नहीं दी गई है किसी तरह की छूट

हमें उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्काच व्हिस्की व अन्य स्पिरिट कम आयात कीमतों पर भारत में डंप नहीं होंगी। इससे भारतीय ब्रांड की महंगी शराब की बिक्री प्रभावित होगी।
-अनंत एस. अय्यर, महानिदेशक, भारतीय मादक पेय कंपनी परिसंघ

ब्रिटेन ने प्रोफेशनल्स और योग शिक्षकों के लिए खोले दरवाजे

- योग्यता के हिसाब से मिलेगा वर्क वीजा, डिजिटल तरीके से भी ब्रिटेन में सेवाएं दे सकेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत और ब्रिटेन के बीच कंप्रेहेंसिव इकोनमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (सीटा) होने से सिर्फ भारतीय किसान और एमएसएमई को ही फायदा नहीं होगा। भारत के प्रोफेशनल्स युवा से लेकर अनुबंध पर काम करने वाले युवाओं को भी ब्रिटेन में काम करने का मौका मिलेगा। इनकी योग्यता के हिसाब से इन्हें वर्क वीजा मिलेगा। हर साल भारत से 1800 शेफ, संगीतकार और योग शिक्षकों को भी ब्रिटेन वीजा देगा। भारतीय प्रोफेशनल्स डिजिटल तरीके से भी ब्रिटेन में अपनी सेवा दे सकेंगे। इससे आइटी और वित्तीय सेक्टर से जुड़े युवाओं को लाभ होगा। सबसे बड़ी बात है कि अनुबंध पर काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को वीजा देने में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं लादी जाएगी।

दोनों देशों के बीच सीटा से संचार, पर्यावरण, शैक्षणिक, वित्त, स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण और परिवहन सेवा से जुड़े प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन में काम करने का मौका मिलेगा। अनुबंध पर सेवा देने वाले 24 माह में किसी भी 12 महीने में अपनी सेवा वहां दे सकेंगे। स्वतंत्र प्रोफेशनल्स के लिए भी यही नियम लागू होगा। कारपोरेट जगत से जुड़े लोगों को तीन साल और जरूरत पड़ने पर और अधिक समय के लिए वीजा दिया जाएगा। आइटी सेक्टर में सेवा देने के लिए भारतीय कामगारों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। मतलब कितनी भी संख्या में आईटी कामगार ब्रिटेन जा सकेंगे। योगा शिक्षक, संगीतकार और शेफ भी ब्रिटेन में एक साल के लिए अस्थायी रूप से काम करने जा सकेंगे।

सामाजिक सुरक्षा के नाम पर नहीं काटी जाएगी पीएफ राशि

दोनों देश अगले एक साल में कुछ ऐसे व्यवसायों का चयन करेंगे, जिनसे जुड़े प्रोफेशनल्स दोनों देशों में सेवा दे सकेंगे। भारत से तीन साल के लिए जाने वाले कामगारों को अब सामाजिक सुरक्षा के नाम पर घाटा भी नहीं उठाना पड़ेगा। अभी भारतीय कामगार को कोई कंपनी ब्रिटेन भेजती है तो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर भारत के साथ ब्रिटेन में भी पीएफ राशि काटी जाती है। लेकिन ब्रिटेन में कटने वाली राशि कामगार को नहीं मिल पाती है। अब ब्रिटेन में तीन साल के लिए जाने वाले कर्मचारियों से सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कोई कटौती नहीं की जाएगी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

फिजिक्सवाला सहित सात कंपनियों को आइपीओ की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: एडटेक यूनिकार्न फिजिक्सवाला और सात्विक ग्रीन एनर्जी सहित सात कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के जरिये धन जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। नियामक मंजूरी प्राप्त करने वाली अन्य कंपनियों में विनिर इंजीनियरिंग, प्रणव कंस्ट्रक्शन्स, फुजियामा पावर सिस्टम्स, एसआइएस कैश सर्विसेज और एनलान हेल्थकेयर शामिल हैं। जनवरी और अप्रैल के बीच अपने आइपीओ दस्तावेज दाखिल करने वाली इन कंपनियों को 14-18 जुलाई के दौरान सेबी की मंजूरी प्राप्त हुई।

इस बीच, जनवरी में आइपीओ दस्तावेज दाखिल करने वाली गौडियम आइवीएफ और वीमेन हेल्थ ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। मर्चेंट बैंकरों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2025 की जनवरी-जून अवधि के दौरान, 24 कंपनियों ने आइपीओ के माध्यम से 45,351 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 36 फर्मों ने 31,281 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसके अलावा, जुलाई में कम से कम आठ कंपनियों ने अपना पहला आइपीओ लांच किया है और अगले कुछ दिनों में पांच और कंपनियां आइपीओ लाने वाली हैं। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी कई कंपनियां आइपीओ लाने की कतार में हैं।

एनएसडीएल का आइपीओ 30 जुलाई को खुलेगा, 4000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) 30 जुलाई को खुलेगा। आइपीओ दस्तावेज के अनुसार, यह एक अगस्त को बंद होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 29 जुलाई को इसके लिए बोली लगा पाएंगे। आइपीओ 5.01 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है और इसमें कोई नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया (एनएसई), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), एचडीएफसी बैंक, आइडीबीआइ बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटर आफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग आफ यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (एसयूयूटीआइ) अपने शेयर बेच रही हैं। बाजार सूत्रों ने आइपीओ का आकार करीब 4,000 करोड़ रुपये आंका है।

मुनाफावसूली और विदेशी फंडों की निकासी से घरेलू शेयर बाजार लुढ़के

मुंबई, प्रेट्र : ब्लूचिप शेयरों में मुनाफावसूली और विदेशी फंडों की निकासी के चलते गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सकारात्मक शुरुआत के बावजूद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अपनी गति को बरकरार नहीं रख सका और 542.47 अंक गिरकर 82,184.17 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह 679.42 अंक या 0.82 प्रतिशत गिरकर 82,047.22 पर आ गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 157.80 अंक गिरकर 25,062.10 पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक्नोलाजीज और एनटीपीसी सबसे ज्यादा पिछड़े शेयरों में शामिल रहे।

गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को कहा कि खुले बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकारी भंडार से गेहूं बेचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपूर्ति पर्याप्त है और कीमतें स्थिर हैं।

सरकार और भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रबंधित केंद्रीय पूल से सरप्लस भंडार को पूर्व निर्धारित आरक्षित मूल्यों पर सीधे बाजार में बेचकर गेहूं की आपूर्ति और कीमतों को विनियमित करने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना का संचालन करती है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ओएमएसएस के तहत 30 लाख टन गेहूं बेचा, जबकि 2023-24 में करीब 1.01 करोड़ टन गेहूं की बिक्री की थी। देश का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2024-25 में रिकार्ड 11.75 करोड़ टन रहने का अनुमान है। ओएमएसएस से चावल की बिक्री के बारे में चोपड़ा ने कहा कि सरकार पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व हरियाणा सहित 4-5 राज्यों में 50 लाख टन चावल की बिक्री कर रही है।

राष्ट्रीय फलक

मोदी ने खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों और भगोड़ों के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाया

प्रथम पृष्ठ से आगे

पीएम मोदी और पीएम स्टार्मर के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई है। मोदी ने ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियों और भारत में आर्थिक अपराध करके ब्रिटेन में शरण लेने वालों की वापसी का मुद्दा भी उठाया। ब्रिटिश पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रेस कांफ्रेंस में भी पीएम मोदी ने खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों की तरफ इशारा करते हुए कहा- "हम एकमत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि अतिवादी विचारधारा वाली शक्तियों को लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता।

कई मामलों में औपचारिक मंजूरी से पहले ही कर दिया गया ऋण वितरित

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस हेराफेरी की कड़ी में कई मामलों में औपचारिक मंजूरी मिलने से पहले ही ऋण वितरित कर दिया गया और बैंक में आवेदन जमा होने के दिन ही राशि भी जारी कर दी गई। इनमें ऋण पाने वाली कुछ कंपनियों की तो वित्तीय स्थिति भी कमजोर थी और उनके पास उचित दस्तावेज की भी कमी थी। कहा जा रहा है कि रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लि. (आरएचएफएल) द्वारा दिए गए कारपोरेट लोन में भारी उछाल देखने के बाद सेबी ने यह जानकारी ईडी के साथ साझा की थी। ये कारपोरेट लोन 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गए थे। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये उछाल किसी लोन डायवर्जन योजना से तो नहीं जुड़ा था। बता दें कि ईडी की यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकाम) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को फ्राड घोषित किए जाने के बाद शुरू हुई है।

ईडी की छापेमारी पर रिलायंस समूह द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया कि प्रमोटर की कुछ निजी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ऋण उन कंपनियों की योग्यता के आधार पर स्वीकृत किए गए थे। ऋण ब्याज सहित चुका दिए गए हैं, जिससे बकाया राशि अब शून्य हो गई है। समूह के अनुसार समूह की कंपनियों और यस बैंक के बीच सभी लेनदेन नियमों और वित्तीय मानदंडों का पूरी तरह से पालन करते हुए किए गए हैं।

शराब कारोबारी के दिल्ली निवास और रायपुर होटल में ईडी की दबिश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसी ने मूलतः दुर्ग निवासी होटल व शराब कारोबारी के दिल्ली स्थित निवास पर गुरुवार को दबिश दी। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र स्थित एक बड़े होटल भी पहुंची थी।

जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि 14 जुलाई को दुर्ग के दीपक नगर स्थित होटल कारोबारी विजय अग्रवाल समेत करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद 18 जुलाई को चैतन्य की गिरफ्तारी की गई थी। वहां से दस्तावेज के आधार पर विजय के रिश्तेदार के दिल्ली निवास व रायपुर के होटल में ईडी गई थी।

****

तत्काल टिकट बुकिंग में आधार-ओटीपी नियम अब अगस्त महीने से होगा लागू

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- साफ्टवेयर अपडेशन व डाटा सत्यापन में देरी के कारण टला फैसला

रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में आधार कार्ड आधारित ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) सत्यापन को अनिवार्य करने की योजना को अगस्त 2025 तक के लिए टाल दिया है। पहले यह नियम 15 जुलाई से लागू होने वाला था, लेकिन साफ्टवेयर अपडेशन और डाटा सत्यापन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

साफ्टवेयर अपडेशन और आधार डाटा को आइआरसीटीसी सिस्टम के साथ जोड़ने में तकनीकी चुनौतियां सामने आई हैं। केवल 10 प्रतिशत आइआरसीटीसी यूजर्स के अकाउंट ही आधार से लिंक हैं, जिसके कारण डाटा सत्यापन में समय लग रहा है। इसके अलावा, सभी रेलवे जोन और काउंटरों में एकसमान सिस्टम लागू करने के लिए प्रशिक्षण और समन्वय की जरूरत है।

तत्काल टिकट सुविधा के तहत टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक किए जा सकते हैं, लेकिन दलालों और फर्जी बुकिंग की समस्या के कारण आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन शुरू करने का फैसला किया था, ताकि बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। नई प्रणाली में तत्काल टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को अपने आइआरसीटीसी अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा।

एक अगस्त से हरियाणा में जमीन खरीदना होगा महंगा, बढ़ेगा कलेक्टर रेट

राज्य ब्यूरो, जागरण, चंडीगढ़ : हरियाणा में अब सभी जिलों में घर बनाना महंगा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने एक अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू करने की तैयारी कर ली है। नई दरें लागू होने से हरियाणा में जमीनों की खरीद-फरोख्त महंगी हो जाएगी। सैनी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका होगा जब कलेक्टर रेट की नई दरें लागू की जाएंगी।

हरियाणा में कलेक्टर रेट को लेकर पिछले कई माह से विवाद चल रहा है। प्रदेश में पिछले साल पहले लोकसभा व फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते एक दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए जा सके थे। बाद में सरकार ने इसे 30 मार्च तक मान्य कर दिया था। प्रदेश में 2025-26 के लिए कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी।

2019 से 2024 तक बलूचिस्तान में आनर किलिंग के 212 मामले सामने आए। औरत फाउंडेशन की यह रिपोर्ट उस क्षेत्र में लिंग आधारित हिंसा और न्याय प्रणाली की अपर्याप्तता पर गंभीर चिंता पैदा करती है।

शिव मंदिर को लेकर भिड़े थाईलैंड-कंबोडिया, 12 मरे

थाईलैंड ने एफ-16 विमानों से की बमबारी, जवाब में कंबोडिया ने तोप से की गोलाबारी

दोनों देशों के बीच भारी तनाव, सेना सतर्क, लड़ाकू विमानों की तैनाती

बैंकाक, रायटर: सीमा पर स्थित 1100 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर बढ़े विवाद में गुरुवार को थाईलैंड व कंबोडिया भिड़ गए। इस दौरान थाईलैंड ने एफ-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडियाई इलाके में बमबारी की और कंबोडियाई सेना ने तोप से गोले दागे। संघर्ष में एक सैनिक समेत 12 लोगों के मारे जाने की सूचना है। तनाव के बीच थाईलैंड ने कंबोडिया से लगने वाली सीमा पर छह एफ-16 विमान तैनात कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया है। थाई सेना की उप प्रवक्ता रिचा सुक्सुवानोन ने कहा, हमने योजनाबद्ध तरीके से वायुसेना की ताकत का प्रयोग किया। थाईलैंड ने कंबोडिया जाने वाले रास्ते पर आवागमन रोक दिया है।

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थाईलैंड के लड़ाकू विमानों ने नागरिकों के आवागमन वाली सड़क पर दो बम डाले। यह थाईलैंड का कंबोडिया पर हमला का बर्बर और अति निंदनीय कृत्य है। यह कंबोडिया की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। कंबोडिया के पीएम हुन मानेत ने थाईलैंड के हमले पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए जाने की मांग की है। दोनों देशों के बीच बुधवार शाम तनाव तब बढ़ना शुरू हुआ जब विवादित क्षेत्र में थाईलैंड के पांच सैनिक लैंडमाइन में हुए विस्फोट में घायल हो गए। थाईलैंड का आरोप है कि समझौते के बावजूद कंबोडियाई सेना ने विवादित क्षेत्र में लैंडमाइन बिछाई हैं, जिनमें यह विस्फोट हुआ। इसके बाद बुधवार शाम थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को बुला लिया और बैंकाक से कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित कर दिया। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कंबोडियाई सेना की गोलाबारी में एक सैनिक व 11 नागरिक मारे गए, जबकि सात सैनिकों समेत 31 लोग घायल हुए हैं। इन हमलों के बाद सीमांत क्षेत्रों के नागरिक कंक्रीट, रेत की बोरियों व पुराने टायरों से बनाए सुरक्षित स्थलों में चले गए हैं। कंबोडिया ने अपने क्षेत्र में हुई क्षति की जानकारी नहीं दी है। सीमांत छह क्षेत्रों पर दोनों सेनाओं में भीषण गोलाबारी जारी है। दोनों देशों के बीच मई में भी झड़प हुई थी जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई थी। ज्ञात हो, दोनों देश 817 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं।

चीन ने दोनों देशों के टकराव पर चिंता व्यक्त करते हुए तनाव कम करने की अपील की है। चीन ने मध्यस्थता का प्रस्ताव भी रखा है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान की अध्यक्षता कर रहे मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहीम ने दोनों देशों से विवाद शांति व संयम से निपटाने का अनुरोध किया है।

कंबोडिया से संघर्ष के बीच गुरुवार को थाईलैंड के कंथारलक जिले में एक पेट्रोल पंप पर बने डिपार्टमेंटल स्टोर से उठता धुआं का गुबार। रायटर

इसलिए बने जंग के हालात: थाईलैंड व कंबोडिया के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद ने अचानक आग पकड़ ली है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक-दूसरे पर गोलियां बरसाईं वो भी एक ऐसे इलाके में, जहां एक प्राचीन मंदिर प्रासात ता मुएन थोम खड़ा है। आइये जानते हैं कि क्यों दो पड़ोसी माने जाने वाले दोनों देशों के बीच जंग के हालात क्यों बन गए हैं

विवाद की जड़: थाईलैंड-कंबोडिया के बीच सीमा विवाद 118 साल पुराना है। यह विवाद प्रीह विहियर मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर है। खमेर साम्राज्य के दौरान राजा उदयादित्यवर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था। यह शिव मंदिर है और डांगरेक पर्वतों में एक चट्टान के ऊपर स्थित है। जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था तब 1907 में दोनों देशों के बीच 817 किमी की लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि नक्शे में प्रीह विहियर मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इस पर विवाद चलता रहा। 1959 में कंबोडिया मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में ले गया। 1962 में आइसीजे ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने इसे मान लिया पर आसपास की जमीन का विवाद जारी रहा।

मंदिर को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर हुई झड़पें: 2008 में यह विवाद तब और बढ़ गया जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में झड़पें शुरू हो गईं। 2011 में हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दिया सैनिक हटाने का आदेश: 2011 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से सैनिक हटाने को कहा। 2013 में फिर से पुष्टि की कि मंदिर व आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का है।

अच्छे पड़ोसी माने जाते हैं दोनों देश: इस विवाद के बावजूद दोनों देश दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी जाते थे। दोनों देशों के नेताओं का मानना था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी पर हालात बदले और उनके बीच तनाव बढ़ गया। 28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल (जहां थाईलैंड, कंबोडिया व लाओस की सीमाएं मिलती हैं) पर दोनों देशों में संघर्ष हुआ, जिसमें कंबोडियाई सैनिक मारा गया था।

थाईलैंड-कंबोडिया ने एक-दूसरे पर लगाए प्रतिबंध: सैनिक की मौत से खफा कंबोडिया ने सीमा पर और सैनिक व हथियार भेजने के आदेश दिए। थाईलैंड ने जवाब में कहा, ऐसी किसी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंबोडिया ने आइसीजे जाने की धमकी दी तो थाईलैंड ने कहा, वह अदालत के अधिकार को नहीं मानता। इसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया ने एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। -स्रोत: जागरण रिसर्च

विमान दुर्घटनाग्रस्त पर चीनी राष्ट्रपति ने पुतिन को भेजा शोक संदेश

रूस के टिंडा में गुरुवार को एंटोनोव एएन-24 विमान के दुर्घटनाग्रस्त पर पड़े मलबे के बीच उठती आग और धुआं। एएफपी

प्रथम पृष्ठ से आगे

अमूर क्षेत्र के गवर्नर वैसिली ओर्लोव ने तीन दिवसीय शोक की घोषणा की है। रूस की संघीय सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच करने की घोषणा की है। क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है। विमान में कम से कम एक चीनी नागरिक के सवार होने की खबर है और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पुतिन को भेजे संदेश में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

यह विमान साइबेरिया स्थित एक निजी क्षेत्रीय एयरलाइन 'अंगरा' का था। यह 1976 में बना था और 1991 में सोवियत संघ के पतन से पहले एयरोफ्लोट द्वारा संचालित किया जाता था। 'अंगरा' साइबेरिया तथा रूस के सुदूर पूर्व के हवाई अड्डों को सेवा प्रदान करती है। रशियनप्लेंस वेब-पोर्टल के अनुसार, यह 1972 और 1976 के बीच निर्मित 10 एएन-24 विमानों का संचालन करती है। 'अंगरा' उन दो साइबेरियाई एयरलाइंस में से एक थी, जिन्होंने पिछले वर्ष रूसी सरकार से एंटोनोव विमानों की सेवा अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। इनमें से कई विमान 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण रूसी विमान उत्पादन प्रभावित हुआ है। कुछ लोगों द्वारा "उड़ते ट्रैक्टर" कहे जाने वाले प्रोपेलर-चालित एएन-24 विमान साइबेरिया की कठोर परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। ये शून्य से नीचे के तापमान में भी उड़ान भर सकते हैं और इन्हें रनवे पर उतरने की जरूरत नहीं होती। हालांकि प्रतिबंधों की वजह से इनके रखरखाव की लागत बढ़ गई है। कई विमानों को आने वाले वर्षों में सेवा से हटा दिया जाना था, लेकिन क्षेत्रीय एयरलाइंस नए विमान आने तक उन्हें सेवा में रखने की कोशिश कर रही हैं। एएन-24 श्रेणी के नए लाडोगा विमानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2027 से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है।

बांग्लादेश के पूर्व चीफ जस्टिस देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार

ढाका, प्रेट्र: बांग्लादेश के पूर्व चीफ जस्टिस एबीएम खैरुल हक को गुरुवार को देशद्रोह के आरोप समेत तीन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया। वह 2010 से 2011 तक देश के 19वें चीफ जस्टिस रहे। उन्हें 2011 में देश की गैर-दलीय कार्यवाहक सरकार प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने समेत कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में लंबे समय तक विधि आयोग के अध्यक्ष रहे।

ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस के उपायुक्त तलेबुर रहमान ने पत्रकारों को बताया कि जासूसी शाखा के अधिकारियों ने 81 वर्षीय पूर्व जज को राजधानी के धनमंडी इलाके में उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया, 'हक तीन मामलों में आरोपित हैं। कानूनी कार्यवाही चल रही है। पूर्व चीफ जस्टिस को अदालत में पेश किया जाएगा और कम से कम एक मामले में उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी।' पिछले वर्ष पांच अगस्त को शेख हसीना की अगुआई वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद कई वकीलों की तरफ से हक के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मामले दर्ज कराए गए थे। वह हसीना सरकार के दौरान विधि आयोग के अध्यक्ष रहे। उन्हें 2013 की शुरुआत में इस पद पर नियुक्त किया गया था और गत 13 अगस्त को इस्तीफा दिया था। हक के खिलाफ मामलों में कार्यवाहक सरकार से जुड़े 13वें संवैधानिक संशोधन को रद करने वाले फैसले को लेकर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य मामले में कथित भ्रष्ट आचरण और अवैध फैसले सुनाने के आरोप लगाए गए हैं। हक की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब देश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने अहम पदों पर सेवाएं दी थीं।

- कार्यवाहक सरकार प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने का सुनाया था फैसला

एबीएम खैरुल हक।

पूर्व पीएम शेख हसीना के शासन में लंबे समय तक विधि आयोग के अध्यक्ष रहे

चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका फिर खारिज : आइएएनएस के अनुसार, बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को इस्कान के पूर्व पदाधिकारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ पांच मामलों में आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से एक चटगांव के वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की कथित हत्या से संबंधित है। उनकी जमानत याचिका पहले भी कई बार खारिज हो चुकी है। उन्हें पिछले साल 25 नवंबर को ढाका में गिरफ्तार किया गया था।

ढाका विमान हादसे के घायलों के इलाज में जुटी भारतीय टीम

ढाका, एएनआइ: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान एक स्कूल पर गिर गया था। इसमें 32 लोगों की मौत हुई थी और 67 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। भारत ने मदद के लिए एक टीम भेजी है, जो गुरुवार को घायलों के उपचार में जुट गई। यह टीम बुधवार की शाम ढाका पहुंची थी। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने बताया, 'भारतीय चिकित्सा टीम के सदस्यों ने ढाका में डाक्टरों से भेंट की और मरीजों को देखा। वे अपनी गतिविधियों में जुट गए हैं।' टीम में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल के डाक्टर व नर्स शामिल हैं, जो जलने व प्लास्टिक सर्जरी में विशेषज्ञता रखते हैं। बांग्लादेशी लोगों ने पीड़ितों के बेहतर उपचार के लिए इस विकट समय में भारतीय चिकित्सा टीम का स्वागत किया है। चीन निर्मित एफ-7 बीजीआइ प्रशिक्षण विमान सोमवार को ढाका के दियाबारी में स्थित माइलस्टोन स्कूल एवं कालेज की दो मंजिला इमारत से टकरा गया था।

आस्ट्रेलिया में मंदिर पर लिखीं नस्लवादी टिप्पणियां, हिंदुओं में रोष

मेलबर्न, प्रेट्र : हाल ही में मेलबर्न में एक हिंदू मंदिर और दो एशियाई रेस्टोरेंट्स पर नस्लीय और अपमानजनक टिप्पणियां लिखने का शर्मनाक मामला सामने आया है। घटना के बाद आस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदुओं में काफी नाराजगी है। उधर, विक्टोरिया पुलिस ने कहा कि हमारे समाज में नफरत और नस्लीय व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

आस्ट्रेलिया टुडे वेब पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार बोरोनिया उपनगर में वाधुर्स्ट ड्राइव पर स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर सोमवार सुबह लाल रंग से नस्लवादी और आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी मिलीं। इसी तरह बोरोनिया रोड पर स्थित दो एशियाई रेंस्टोरेंट्स की दीवारों पर भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां लिखी गईं। इस घटना से आक्रोशित हिंदू काउंसिल आफ आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया चैप्टर के अध्यक्ष मकरंद भागवत ने कहा कि यह हिंदू समुदाय, उनके पूजा के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने इस शर्मनाक हरकत की निंदा की। विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलेन ने मंदिर प्रबंधन को भेजे गए एक निजी संदेश में इस हमले को नफरत भरा और नस्लीय कदम बताया। उन्होंने कहा- "यह केवल तोड़फोड़ का मामला नहीं था बल्कि यह नफरत भरा एक जानबूझकर किया गया कार्य था और इसका उद्देश्य डराना और भय फैलाना था।" यहां बता दें कि आस्ट्रेलिया में पिछले कुछ वर्षों में मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। इनमें से कई को खालिस्तान समर्थकों ने अंजाम दिया।

- श्री स्वामीनारायण मंदिर के अलावा दो एशियाई रेस्टोरेंट्स की दीवारों पर भी लिखी गईं नस्लीय व अपमानजनक टिप्पणियां
- हिंदू काउंसिल आफ आस्ट्रेलिया ने कहा- यह हिंदू समुदाय, उसके पूजा के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला

जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के ट्रंप के प्रयास को अपील अदालत ने असंवैधानिक बताया

वाशिंगटन, एपी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संघीय अपील अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, ट्रंप का जन्मजात नागरिकता को सीमित करने वाला कार्यकारी आदेश असंवैधानिक है। देश भर में इसके क्रियान्वयन पर रोक लाई जाती है। इस फैसले ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश जान सी. कफेनार के निर्णय को बनाए रखा, जिन्होंने ट्रंप के जन्मजात नागरिकता समाप्त करने के प्रयास पर रोक लगा दी थी और प्रशासन के संविधान की अनदेखी करने के प्रयास की निंदा की थी।

सैन फ्रांसिस्को स्थित नौवें अमेरिकी सर्किट अपील अदालत द्वारा यह फैसला 2-1 के बहुमत से दिया गया। इसमें ट्रंप प्रशासन को उस आदेश को लागू करने से रोक दिया गया, जो अवैध रूप से या अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने वालों के बच्चों को नागरिकता देने से इन्कार करता है। फैसले में कोर्ट ने कहा, जिला अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला कि कार्यकारी आदेश की प्रस्तावित व्याख्या, जो अमेरिका में जन्मे कई व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित करती है, असंवैधानिक है। इस पर अभी व्हाइट हाउस व न्याय विभाग ने टिप्पणी नहीं की है। अब यह मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह मामला राज्यों के एक समूह द्वारा दायर किया गया था।

राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा नियुक्त न्यायाधीश माइकल हाकिन्स व रोनाल्ड गोल्ड ने आदेश में कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिला अदालत ने राज्यों को पूर्ण राहत देने के लिए एक सार्वभौमिक निषेधाज्ञा जारी करने में अपने विवेक का दुरुपयोग नहीं किया। वहीं, ट्रंप द्वारा नियुक्त न्यायाधीश पैट्रिक बुमाटे ने इससे असहमति जताई। बुमाटे ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि जन्मजात नागरिकता समाप्त करना संवैधानिक होगा या नहीं। 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे या वहां प्राकृतिक रूप से बसे तथा अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन सभी लोग नागरिक हैं। वाशिंगटन के अटार्नी जनरल निक ब्राउन ने कहा, "अदालत इससे सहमत है कि राष्ट्रपति एक हस्ताक्षर से अमेरिकी होने का अर्थ पुनः परिभाषित नहीं कर सकते।" ज्ञात हो, ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मा बच्चा नागरिक नहीं है अगर उसकी मां के पास कानूनी आव्रजन दर्जा नहीं है या वह देश में कानूनी रूप से लेकिन अस्थायी रूप से रहती है और पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं है।

- अपील कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा

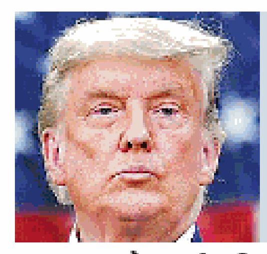

ट्रंप के आदेश के देश भर में क्रियान्वयन पर रोक लगा दी

गाजा में युद्धविराम व सहायता अभियान को भारत का समर्थन

न्यूयार्क, एएनआइ : भारत ने गाजा में तत्काल युद्धविराम, निर्बाध मानवीय सहायता और बंधकों की रिहाई का आह्वान किया है ताकि इस क्षेत्र में गहराते संकट का समाधान किया जा सके। पश्चिम एशिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की त्रैमासिक खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि सिर्फ युद्धविराम बिगड़ती मानवीय स्थिति का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

हरीश ने कहा, "युद्ध के दौरान बीच-बीच में यह विराम उन मानवीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जिनका सामना लोग कर रहे हैं, जो रोजाना भोजन और ईंधन की भारी कमी, अपर्याप्त चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच की कमी से जूझ रहे हैं।" उन्होंने गाजा में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्था के चरमराने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि गाजा के लगभग 95 प्रतिशत अस्पताल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 6,50,000 से अधिक बच्चे 20 महीने से भी अधिक समय से स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।"

तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान करते हुए हरीश ने कहा, "मानवीय पीड़ा को तत्काल दूर किया जाना चाहिए। मानवीय सहायता निरंतर और समय पर प्रदान की जानी चाहिए। शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्धविराम अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग हैं। इसके अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है।"

हरीश ने फलस्तीन के प्रति भारत के ऐतिहासिक समर्थन को भी दोहराया। उन्होंने कहा, "भारत के अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ ऐतिहासिक और मजबूत संबंध हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और फलस्तीनी हितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले गैर-अरब देशों में थे।" उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में प्रत्यक्ष सहायता और यूएनआरडब्ल्यूए जैसे संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से फलस्तीनी लोगों की सहायता के लिए चार करोड़ डालर से अधिक की विकास परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। फलस्तीन शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए 1949 में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को स्थापित किया गया था।

- क्षेत्र में गहराते संकट के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंधकों की रिहाई का भी किया आह्वान
- भारत के स्थायी प्रतिनिधि बोले, सिर्फ युद्धविराम बिगड़ती मानवीय स्थिति का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं

पर्वतनेनी हरीश। फाइल

ट्रंप प्रशासन के आगे झुकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, देगी 22 करोड़ डालर

न्यूयार्क, एपी: अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को आखिरकार ट्रंप प्रशासन के सामने झुकना पड़ा है। उसने संघीय फंड बहाल कराने के लिए प्रशासन के साथ समझौता कर लिया है, जिसके तहत वह संघीय सरकार को 22 करोड़ डालर से ज्यादा (करीब 1900 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी। यूनिवर्सिटी ने बुधवार को इसकी घोषणा की। प्रशासन ने यहूदी विरोधी भावनाओं से निपटने में नाकामी के नाम पर यूनिवर्सिटी का फंड रोक दिया था।

व्हाइट हाउस ने बताया कि यूनिवर्सिटी समझौते के तहत मामला निपटाने के लिए तीन वर्षों में 20 करोड़ डालर का भुगतान करेगी। वह अमेरिकी समान रोजगार अवसर आयोग की तरफ से शुरू की गई जांच के निपटारे के लिए भी 2.1 करोड़ डालर का भुगतान करेगी। यह जांच सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के बाद यहूदी कर्मचारियों के नागरिक अधिकारों के कथित उल्लंघनों को लेकर चल रही थी। यूनिवर्सिटी की कार्यकारी अध्यक्ष क्लेयर शिपमैन ने कहा, 'संघीय जांच और संस्थागत अनिश्चितता के लंबे दौर के बाद यह समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है।'

यूनिवर्सिटी को अरबों डालर के नुकसान की धमकी दी गई थी, जिसमें 40 करोड़ डालर का अनुदान शामिल है, जिसे इस वर्ष रोक दिया गया था। 270 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी उन पहले अमेकिरी विश्वविद्यालयों में शामिल है, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके परिसरों में फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों को लेकर निशाना बनाया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के टास्क फोर्स ने भी पिछले वर्ष यह पाया था कि प्रदर्शनों के दौरान यहूदी छात्रों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था।

- संघीय फंड बहाल कराने के लिए किया प्रशासन के साथ समझौता
- यहूदी विरोधी भावनाओं से निपटने में नाकामी पर रोक दिया था फंड

उत्तरी सीरिया में विस्फोट में छह की मौत, दर्जनों घायल

दमिश्क, एपी : उत्तरी सीरिया के इदलिब प्रांत में हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी संस्था सीरियन आब्जर्वेटरी फार ह्यूमन राइट्स ने बताया कि विस्फोट एक गोला-बारूद डिपो में हुआ।

सीरियन सिविल डिफेंस ने बताया कि गुरुवार को इदलिब शहर के उत्तर में मरात मिसरिन कस्बे में यह विस्फोट हुआ। व्हाइट हेल्मेट्स ने कहा कि यह केवल उन लोगों की मौत का आंकड़ा है, जिन्हें सीरियाई सिविल डिफेंस टीमों ने बरामद किया है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। सीरिया के आपातकालीन और आपदा प्रबंधन मंत्री राएद अल-सलेह ने एक्स पर कहा कि टीमें घायलों को ले जा रही हैं। क्षेत्र में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जिससे प्रयासों में बाधा आ रही है।

देश-दुनिया की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

फ्लोरिडा पुलिस ने अश्वेत छात्र को कार से घसीटकर मारे मुक्के

वाशिंगटन, एपी : एक अश्वेत छात्र को ट्रैफिक पर रोकने के दौरान फ्लोरिडा के पुलिस अधिकारियों ने कार से खींचकर घसीटा और घूंसे मारे। यह घटना फरवरी की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। मुक्का लगने से उसका एक दांत टूटकर होंठ में घुस गया, जिसके कारण कई टांके लगे। इस फुटेज के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। डैशकैम वीडियो में मैकनील ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और जैक्सनविले के पुलिस सुपरवाइजर से बात करने की गुहार लगा रहे हैं, तभी एक पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उनके चेहरे पर मुक्का मारा और गाड़ी से बाहर खींचकर फिर से मुक्का मारा। एक अन्य पुलिसकर्मी ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और पैर पर वार किया।

22 वर्षीय छात्र विलियम मैकनील जूनियर ने कहा कि उस दिन मैं बस यह जानना चाहता था कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस डरा हुआ था। लिविंगस्टोन के अध्यक्ष एंथनी डेविस ने बताया कि मैकनील जीवविज्ञान में स्नातक हैं। लिविंगस्टोन कालेज उत्तरी कैरोलिना के सैलिसबरी में अश्वेत ईसाई कालेज है। शेरिफ ने कहा कि एक आंतरिक जांच जारी है। वहीं, राज्य अटार्नी कार्यालय द्वारा की गई अलग जांच में अधिकारियों को किसी भी आपराधिक गड़बड़ी से मुक्त कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका में पुलिस द्वारा आम लोगों खासकर अश्वेत लोगों को इस प्रकार निशाना बनाने की घटनाएं पहले भी होती रही है। पुलिस की पिटाई से लोगों की मौत तक हो चुकी है। इसे लेकर कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं।

- छात्र के कार के लगे डैशकैम का वीडियो प्रसारित होने के बाद सामने आया मामला

एपस्टीन की फाइलों में ट्रंप का नाम होने की खबर फर्जी : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन, रायटर: अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने वाल स्ट्रीट जर्नल अखबार की उस खबर को फर्जी करार दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि बाल यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन की फाइलों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। अखबार ने अधिकारियों के हवाले से बुधवार को दावा किया कि अटार्नी जनरल पाम बोंडी ने ट्रंप को मई में बताया था कि उनका नाम एपस्टीन को लेकर न्याय विभाग की फाइलों में आया है। इस बीच, दक्षिण फ्लोरिडा के संघीय जज ने एपस्टीन से जूरी की गवाही के दस्तावेज सार्वजनिक करने की न्याय विभाग की मांग खारिज कर दी।

इधर, पाम बोंडी ने बुधवार को कहा, "फाइलों में ऐसा कुछ नहीं है। हमने अदालत से एपस्टीन मामले में जूरी की गवाही सार्वजनिक करने की अनुमति मांगी है।" इस बीच, अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जानसन ने कहा कि एपस्टीन मामला कोई धोखा नहीं है।

****

मैक्रों ने पत्नी के बारे में फूहड़ दावा करने वाली इन्फ्लुएंसर पर किया मुकदमा

पेरिस, रायटर : फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट ने बुधवार को अमेरिकी इन्फ्लुएंसर कैंडेस ओवेंस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। ओवेंस का दावा है कि फ्रांस की प्रथम महिला का जन्म पुरुष के रूप में हुआ था। मैक्रों ने डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट में दायर शिकायत में कहा कि ओवेंस ने अपने पाडकास्ट को बढ़ावा देने के लिए झूठा वैश्विक अपमान का अभियान चलाया है। इन झूठों में यह भी शामिल है कि 72 वर्षीय ब्रिजिट मैक्रों का जन्म जीन-मिशेल ट्रोग्नेक्स नाम से हुआ था, जबकि यह उनके बड़े भाई का वास्तविक नाम है। यह किसी विश्व नेता द्वारा मानहानि का मुकदमा दायर करने का एक असाधारण मामला है।

शिकायत में कहा गया है कि ओवेंस ने उनके रूप-रंग, शादी, दोस्तों, परिवार और उनके निजी इतिहास का विश्लेषण किया है और इसे एक विचित्र कहानी में बदल दिया है, जिसका उद्देश्य उन्हें भड़काना और अपमानित करना है। ओवेंस के प्रवक्ता ने मुकदमे को धमकाने का प्रयास बताया। कहा, यह एक विदेशी सरकार है, जो अमेरिकी स्वतंत्र पत्रकार के अधिकारों पर हमला कर रही है। वहीं, मैक्रों दंपती के वकील ने कहा, उन्होंने ओवेंस द्वारा मानहानिकारक बयान वापस लेने की तीन मांगों को अस्वीकार करने के बाद मुकदमा दायर किया है। ओवेंस के खिलाफ 219 पृष्ठों की शिकायत में व्यापक सुबूत प्रस्तुत किए गए हैं कि ब्रिजिट मैक्रों एक महिला के रूप में पैदा हुई थीं, वह हमेशा एक महिला रही हैं।

- कैंडेस ओवेंस ने किया था दावा, फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों का जन्म पुरुष के रूप में हुआ था

राष्ट्रपति ने कहा, पाडकास्ट को बढ़ावा देने व उनके अपमान के लिए चलाया जा रहा अभियान

विश्व रैंकिंग में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट पाकिस्तान का

इस्लामाबाद, एएनआइ : हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत आठ स्थानों की छलांग लगाकर जहां 77वें स्थान पर पहुंच गया, वहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट की हालत बद से बदतर बनी हुई है। यह इस वैश्विक रैंकिंग में 96वें स्थान पर है। यह लगातार चौथे वर्ष विश्व स्तर पर यमन के साथ संयुक्त रूप से चौथा सबसे खराब पासपोर्ट रहा है।

डान की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान का यात्रा दस्तावेज दुनिया भर में सबसे कम शक्तिशाली देशों में से एक है, जो केवल 32 स्थानों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में सूची में 96वें स्थान पर है। इससे नीचे इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे संघर्षग्रस्त देशों के पासपोर्ट का स्थान है। इंडेक्स 227 यात्रा स्थलों पर 199 विभिन्न पासपोर्टों के वीजा-मुक्त विशेषाधिकारों का आकलन करता है और उन्हें उन स्थानों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक बिना पहले से वीजा प्राप्त किए जा सकते हैं।

पंत की पारी पर **भारी पड़ी अंग्रेजों की बल्लेबाजी** 358 रन के जवाब में दो विकेट पर 225 रन बनाए

निडर महायोद्धा रिषभ पंत

अभिषेक त्रिपाठी
मैनचेस्टर से

अगर आपने 2002 में एंटीगा में टूटे जबड़े के साथ अनिल कुंबले को गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा, अगर आपने 2023 में लाइर्स में पिंडली की चोट के साथ नाथन लियोन को एक पैर पर दौड़ते हुए नहीं देखा तो आपको पैर में फ्रैक्चर के बावजूद लड़खड़ाते हुए ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच की तरफ बढ़ने और एक टांग के भरोसे 65 गेंद तक मैदान में टिक कर चौके-छक्के मारने वाली रिषभ पंत (54) की बहादुर पारी को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से यह क्रिकेट इतिहास की सबसे जीदार पारी है। जब विपक्षी टीम सहित दुनिया के सभी क्रिकेट प्रशंसक ये मानकर चल रहे थे कि भारतीय विकेटकीपर का इस मैच में उतरना मुश्किल है, तब वह उतरे ही नहीं बल्कि अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत को पहली पारी में 358 रनों तक पहुंचाने में मदद भी की। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 225 रन बना लिए। सीरीज में पहले से ही 2-1 से आगे चल रही इंग्लिश टीम अब पहली पारी में सिर्फ 133 रन पीछे है।

पंत का जवाब नहीं : बुधवार को वोक्स की गेंद रिवर्स स्वीप करने वाले पंत के पैर पर लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां उनका स्कैन हुआ जिसमें फ्रैक्चर निकला। बुधवार की रात भारतीय टीम प्रबंधन ने बैठक की और निर्णय हुआ की जरूरत पड़ने पर पंत बल्लेबाजी करेंगे। पंत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जीदारी के साथ कहा, जरूर खेलूंगा। सुबह मूनबूट पहनकर पंत थोड़ी देर से आए और फिर सफेद जर्सी के साथ पवेलियन में डट गए। रवींद्र जडेजा के जल्दी आउट होने के बाद शार्दुल और वाशिंगटन ने पहले सत्र में नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे इंग्लिश गेंदबाजों का बेहतरीन सामना किया। जब कप्तान बेन स्टोक्स ने ठाकुर की 41 रनों की जबरदस्त पारी का अंत किया तो इंग्लिश टीम उत्साहित थी क्योंकि उन्हें लगा कि अब विपक्षी टीम को वे कुछ ओवरों में ही आउट कर देंगे लेकिन कुछ मीटर की दूसरी पर रेलिंग पकड़कर सीढ़ियों से उतरते हुए रिषभ पंत दिखाई दिए। वह बेहद सावधानी से एक-एक कदम रख रहे थे। सारे कैमरे उनकी तरफ थे। लड़खड़ाते हुए वह बाउंड्री के पास आकर मैदान को छूकर प्रणाम करते हैं। मीडिया बाक्स, ड्रेसिंग रूम, कमेंट्री रूम और दर्शक दीर्घा में बैठे लोग खड़े होकर इस निडर योद्धा का तालियों से स्वागत करते हैं। इंग्लिश टीम भी उन्हें देखकर भौचक्क थी।

पैरों पर आती रहीं गेंदें : पंत टूटे पैर के साथ सिर्फ विकेट पर खड़े नहीं थे बल्कि रन के लिए दौड़ भी रहे थे। सभी थ्रो उनकी तरफ आ रहे थे और वह यह जानकर हेलमेट के नीचे से व्यंगात्मक मुस्कान बिखेर रहे थे। पंत लंच तक टिके रहे और भारत का स्कोर 321 रन हो गया। ठाकुर और वाशिंगटन ने छठे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की थी तो पंत ने वाशिंगटन और बुमराह के साथ मिलकर स्कोर को 349 तक पहुंचाया। पदार्पण करने वाले अंशुल कंबोज शून्य पर आउट हुए। इंग्लिश गेंदबाज पंत की टांगों पर की तरफ कई गेंद फेंक रहे थे लेकिन वह टिके हुए थे।

सीरीज में पांचवीं 50 से अधिक रन की पारी : पंत जब बुधवार को रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से गए थे तब उन्होंने 37 रन बनाए थे और वह 17 रन जोड़कर गुरुवार को आउट हुए। वह एक टेस्ट सीरीज में पांच 50 से अधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए। पंत ने दो भारतीय विकेटकीपरों को इस मामले में पीछे छोड़ा। एक फारुख इंजीनियर, जिनके नाम से इस मैदान में एक स्टैंड बनाया गया है और दूसरे महेंद्र सिंह धौनी, जो पंत के आदर्श हैं। पंत स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे। बस किसी तरह चल रहे थे लेकिन जैसे ही रन लेने की स्थिति बनती वह दौड़ने के लिए तत्पर हो जाते। लोग कहते हैं कि फलाने बल्लेबाज का पैर नहीं हिला तो आउट हो गए लेकिन यहां तो पंत किसी तरह पैरों पर खड़े थे। उन्होंने 111वें ओवर में आर्चर पर मिडविकेट पर छक्का मारा। उन्होंने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में पूरी ताकत लगा दी। आर्चर ने स्लोअर गेंद फेंककर चाल चली लेकिन रिषभ के सामने वह फेल हो गई। उन्होंने इसके साथ सहवाग के 91 टेस्ट छक्कों की बराबरी की।112वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने स्टोक्स की गेंद पर आफ साइड में बेहतरीन चौका मारकर अर्धशतक पूरा किया। यह उनके करियर का 18वां और सबसे शानदार अर्धशतक रहा। पंत 54 रन बनाकर आर्चर की गेंद पर बोल्ड हो गए। ओल्ड ट्रैफर्ड के दर्शक उनकी सराहना करने के लिए खड़े हो गए। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने भी उनका उत्साहवर्धन किया।

कमाल के स्टोक्स: पंत के अलावा इस मैच में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की बात करनी चाहिए। स्टोक्स सीरीज जीतने के लिए लंबे-लंबे स्पैल कर रहे हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। उन्होंने पिछले आठ साल में पहली बार पारी में पांच विकेट लेकर भारतीय टीम को परेशान किया। वह इस सीरीज में 16 विकेट ले चुके हैं। इस मैच में उनका साथ जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट लेकर दिया। उन्होंने इस सीरीज में आठ विकेट लिए जिसमें सात विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाजों के हैं।

आउट होने के बाद पवेलियन लौटते रिषभ पंत ● एपी

8 साल बाद पारी में पांच विकेट लिए बेन स्टोक्स ने। पदार्पण कर रहे अंशुल कंबोज को आउट करके उन्होंने इस पारी का पांचवां विकेट लिया। इस सीरीज में 16 विकेट लेकर वह इस मामले में सबसे आगे हैं

स्कोर बोर्ड

भारत पहली पारी: 358/10 (114.1 ओवर), (264/4 से आगे)

	रन	गेंद	4/6
पंत बो. आर्चर	54	75	3/2
जडेजा का. ब्रूक बो आर्चर	20	40	3/0
शार्दुल का. डकेट बो स्टोक्स	41	88	5/0
वाशिंगटन का. वोक्स बो. स्टोक्स	27	90	2/0
अंशुल का. स्मिथ बो. स्टोक्स	0	3	0/0
बुमराह का. स्मिथ बो. आर्चर	4	7	1/0
सिराज अविजित	5	7	1/0

विकेट पतन: 5-266 (जडेजा, 84.5), 6-314 (शार्दुल, 101.4), 7-337 (वाशिंगटन, 109.2), 8-337 (अंशुल, 109.5), 9-349 (पंत, 112.3), 10-358 (बुमराह, 114.1). गेंदबाजी: वोक्स 23-5-66-1, आर्चर 26.1-3-73-3, कार्स 21-1-71-0, स्टोक्स 24-3-72-5, डासन 15-1-45-1, रूट 5-0-19-0

इंग्लैंड पहली पारी : 225/2 (46 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
क्राउले का. राहुल बो. जडेजा	84	113	13/1
डकेट का. सब. बो. अंशुल	94	100	13/0
पोप अविजित	20	42	3/0
रूट अविजित	11	27	2/0

गेंदबाजी: बुमराह 13-4-37-0, अंशुल 10-1-48-1, सिराज 10-0-58-0, शार्दुल 5-0-35-0, जडेजा 8-0-37-1

रिव्यू के निर्णय से खुश नहीं थे बुमराह

मैनचेस्टर: जोफ्रा आर्चर की पहली पारी की आखिरी गेंद लेग साइड की ओर जा रही थी और बुमराह ने उसे खेलने की कोशिश की। आर्चर ने बमुश्किल अपील की। पहली स्लिप में खड़े जो रूट ने कुछ सुन लिया था और उन्होंने स्टोक्स को रिव्यू लेने के लिए मना लिया। रिव्यू में गेंद बुमराह के दस्ताने में लगकर जाते हुए दिखाई दी लेकिन भारतीय गेंदबाज उससे खुश नहीं थे। वह सिर हिला रहे थे कि उनके दस्ताने पर गेंद नहीं लगी। ड्रेसिंग रूम जाते समय उनको रास्ते में जो-जो मिला उससे उन्होंने यही बताया। यही नहीं जब वह गेंदबाजी करने आए तब अंपायर से भी उस बारे में बात करते दिखे।

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी	मैच	पारी	रन	औसत	छक्के
रिषभ पंत	47	82	3427	44.50	90
वीरेंद्र सहवाग	103	178	8503	49.43	90
रोहित शर्मा	66	116	4301	40.57	88
एमएस धौनी	90	144	4876	38.09	78
रवींद्र जडेजा	84	125	3717	36.80	74

4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक के साथ पांच बार पारी में पांच विकेट लिए हैं। गैरी सोबर्स, इयान बाथम और जैक्स कैलिस के बाद ऐसा करने वाले बेन स्टोक्स चौथे आलराउंडर हैं

इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर

रन	खिलाड़ी	देश	बनाम	वर्ष
479	रिषभ पंत	भारत	इंग्लैंड	2025
464	एलेक स्टीवर्ट	इंग्लैंड	द. अफ्रीका	1998
415	जेमी स्मिथ	इंग्लैंड	भारत	2025
387	जानी बेयरस्टो	इंग्लैंड	श्रीलंका	2016

बिखरी नजर आई भारतीय गेंदबाजी

वाशिंगटन को एक भी ओवर नहीं मिला, तेज गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

मैनचेस्टर: जिस ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में दूसरे दिन इंग्लिश गेंदबाजों ने भारत के छह विकेट सिर्फ 94 रन पर झटक लिए, वहां पर भारतीय गेंदबाजों को दो विकेट लेने के लिए 225 रन खर्च करने पड़े। रणजी और दलीप ट्राफी में अच्छा प्रदर्शन करके इस मैच में पदार्पण करने वाले अंशुल कंबोज पूरी तरह दबाव में दिखे। उनके पहले ओवर में ही बेन डकेट ने तीन चौके पड़े। भारत के मुख्य तेज गेंदबाज बुमराह पूरे दिन 140 किमी प्रति घंटे की तेजी से गेंद फेंकने के लिए तरसते रहे। मोहम्मद सिराज को भी विकेट नहीं मिला। आलराउंडर शार्दुल ठाकुर से कोई उम्मीद भी नहीं थी और रवींद्र जडेजा किसी तरह एक विकेट लेने में सफल हुए। भारतीय टीम ने दूसरे दिन 46 ओवर फेंके लेकिन आलराउंडर की तरह खेल रहे वाशिंगटन सुंदर को कप्तान शुभमन गिल ने एक ओवर भी गेंदबाजी नहीं कराई। अगर वाशिंगटन खराब समय में गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं तो उनकी जगह एक मुख्य बल्लेबाज या एक स्पिनर कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। अगर टीम 20 विकेट नहीं लेगी तो इस तरह उसका यहां जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आखिर वाशिंगटन टीम में क्यों हैं?

बुमराह का दम नहीं दिखा: भारतीय टीम को बार्डर-गावस्कर ट्राफी में तहलका मचा देने वाले बुमराह से उम्मीद थी लेकिन वह शुरुआती स्पैल में मुश्किल से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गेंद फेंक पा रहे थे। इंग्लिश ओपनर जैक क्राली ने शुरुआत में उनकी 13 गेंदों पर रन ही नहीं बनाए लेकिन उन्हें कोई विशेष दिक्कत भी नहीं हुई। वह आराम से बुमराह की आफ स्टंप से बाहर की गेंद छोड़ रहे थे और सीधी लाइन पर आ रही गेंदों को नरम हाथों से खेल रहे थे। इंग्लिश ओपनरों क्राउली और डकेट ने नौवें से 12वें ओवर के बीच पांच चौके लगाए। डकेट और क्राउली ने चायकाल से पहले पांच से ज्यादा के रन रेट से 77 रन की साझेदारी की। मददगार परिस्थितियों के बावजूद भारत ने बेहद खराब गेंदबाजी की। भारतीय गेंदबाजों ने डकेट को कई गेंदें पैड पर खिलाईं, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी चौके के लिए भेजा। उनके अर्धशतक तक पहुंचने तक अपने सभी सात चौके लेग साइड पर लगाए। उन्होंने 100 गेंदों पर 94 के स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए। अंशुल कंबोज उन्हें किसी तरह पंत की जगह विकेटकीपिंग कर रहे ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कराने में सफल रहे। डकेट ने 70 प्रतिशत से ज्यादा रन लेग साइड पर बनाए। भारत की गेंदबाजी इतनी खराब थी कि डकेट और क्राउली ने पहले विकेट के लिए 192 गेंदों पर 166 रनों की साझेदारी की। क्राउली भी शानदार 84 रन बनाकर जडेजा का शिकार हुए। बुमराह ने पहले स्पैल में पांच ओवर में 22 रन दिए तो दूसरे स्पैल में इतने ही ओवर में आठ रन दिए। भारतीय टीम ने जहां पहली पारी में 3.13 के रन रेट से रन बनाए थे वहीं इंग्लिश टीम अब तक 4.89 के रन रेट से रन बना चुकी है। वह तो बाद में ओली पोप और जो रूट ने थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की नहीं तो रन रेट पांच से ऊपर का होता। अगर जडेजा की बात करें तो उनके पहले ही ओवर में एक चौका और एक छक्का पड़ा। 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्राउली ने चौका मारा लेकिन अंपायर ने नोबाल दे दी। इसके कारण उन्हें अगली गेंद फेंकनी पड़ी जिसमें गेंद क्राउली के बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में केएल राहुल के पास पहुंची। भारत को तीसरे दिन भी बल्लेबाजी करनी होगी। इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम बहुत लंबा है। 10वें नंबर पर आने वाले ब्रायडन कार्स भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। ऐसे में भारत को अगर इस मैच में बने रहना है तो तीसरे दिन सुबह के सत्र में चार विकेट कम से कम लेने होंगे।

गेंदबाजी के दौरान जसप्रीत बुमराह ● एपी

पांचवें टेस्ट में नहीं खेलेंगे पंत, जगदीशन को बुलाया जा सकता है

मैनचेस्टर: पंत चौथे टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करने जरूर उतरे लेकिन वह ओवल में होने वाले पांचवें टेस्ट में नहीं खेलेंगे। ध्रुव जुरैल को पांचवें टेस्ट में खेलने का मौका मिल सकता है। जुरैल ने तीसरे और चौथे टेस्ट में पंत के चोटिल होने पर विकेटकीपिंग की है। पंत के दाहिने पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। भारतीय चयनकर्ता पंत की जगह बैकअप विकेटकीपर के तौर पर इशान किशन को बुलाना चाहते थे लेकिन वह भी चोटिल बताए जा रहे हैं। स्कूटी चलाते समय उन्हें चोट लगी थी जिस कारण उनके टांके लगे हैं। ऐसे में तमिलनाडु के नारायण जगदीशन को बैकअप के तौर पर बुलाया जा सकता है।

एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले भारतीय विकेटकीपर

कितनी बार	विकेटकीपर	बनाम	वर्ष
5	रिषभ पंत	इंग्लैंड	2025
4	फारुख इंजीनियर	इंग्लैंड	1972-73
4	एमएस धौनी	आस्ट्रेलिया	2008-09
4	एम एस धौनी	इंग्लैंड	2014

खेल डायरी

17 वर्षीय उन्नति ने पीवी सिंधू को चौंकाया

चांगझोउ, प्रेट्र : चाइना ओपन बैडमिंटन में गुरुवार को रोहतक की 17 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने बड़ा उलटफेर करते हुए दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उन्नति ने 73 मिनट में 21-16, 19-21, 21-13 से जीत दर्ज की। यह सात वर्षों में पहली बार था जब सिंधू किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी से हारी हैं। पुरुष डबल्स में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी रोली कार्नांडो और बागस मौलाना को 21-19, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रणय को ताइवान के चोउ तिएन चेन के विरुद्ध 21-18, 15-21, 8-21 से हारकर बाहर हो गए।

उन्नति हुड्डा ● बीडब्ल्यूएफ

दिग्गज पेशेवर पहलवान हल्क होगन का निधन

फ्लोरिडा, एपी : पेशेवर रेसलिंग के दिग्गज अमेरिकी पहलवान और डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिग्गज हल्क होगन का गुरुवार को निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। फ्लोरिडा पुलिस उनके निधन की पुष्टि की है। फ्लोरिडा के क्लियरवाटर शहर में पुलिस को होगन को कार्डियक अरेस्ट (हृदयगति रुकने) की सूचना मिली थी। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हल्क होगन का असली नाम टेरी बोलिया था। वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े चेहरों में से थे। उन्होंने 1985 में पहले रेसलमेनिया में मुख्य भूमिका निभाई थी और कई वर्षों तक कंपनी का प्रमुख चेहरा बने रहे। उन्होंने आंद्रे द जाइंट, रैंडी सैवेज, द राक से लेकर विंस मैकमैहन तक सभी प्रमुख रेसलरों के खिलाफ मुकाबले लड़े। अपने करियर में होगन ने कम से कम छह बार डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीती और 2005 में उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई हाल आफ फेम में शामिल किया गया था।

बोनमती के गोल से स्पेन यूरो कप फाइनल में

ज्यूरिख, एपी: कुछ ही हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती थीं और अब देश को ऐतिहासिक यूरो फाइनल में पहुंचाकर इतिहास रच दिया। स्पेन की स्टार फुटबालर ऐइताना बोनमती ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें दो बार बैलन डिओर पुरस्कार मिल चुका है। महिला यूरो 2025 के सेमीफाइनल में बुधवार को जर्मनी के विरुद्ध खेले गए रोमांचक मुकाबले में बोनमती ने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल कर स्पेन को 1-0 से जीत दिलाई। इसी के साथ स्पेन ने पहली बार महिला यूरो के फाइनल में जगह बनाई है और अब उसका मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। 26 वर्षीय मिडफील्डर बोनमती को यूरो की शुरुआत से एक हफ्ते पहले वायरल मेनिनजाइटिस के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन्होंने कहा, मैं इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती थी, और ये उन सभी लोगों के समर्थन के बिना संभव नहीं था जिन्होंने मुझे इस स्थिति में पहुंचाया।

भारत को कुलदीप यादव के साथ उतरना चाहिए था : पार्थिव पटेल

खेल संवाददाता, नई दिल्ली : भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल का कहना है कि भारत को इस मैच में चार अटैकिंग गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए था न कि अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ। बल्लेबाज आलराउंडर को प्राथमिकता देने के कारण कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव की टीम में जगह नहीं बन पा रही है।

जियो स्टार एक्सपर्ट के रूप में पार्थिव ने वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारतीय टीम को कुलदीप यादव को खिलना चाहिए था। टीम प्रबंधन एक अतिरिक्त बल्लेबाज को प्राथमिकता दे रहा है, इसी वजह से कुलदीप को मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी राय में भारत को चार अटैकिंग गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए। पार्थिव ने लार्ड्स में कप्तान शुभमन गिल के रवैये का बचाव करते हुए कहा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज 90 सेकेंड की देरी से आए। इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया में अक्सर टीमें खेल भावना का इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार करती हैं। इसलिए गिल का रवैया बिल्कुल भी गलत नहीं था। गिल की कप्तानी पर पार्थिव ने कहा कि यह उनके लिए नया है और वह और बेहतर हो रहे हैं। वह अपनी योजनाओं को लेकर बहुत स्पष्ट हैं।

पार्थिव पटेल ● फाइल फोटो

यूएई में एशिया कप की मेजबानी करेगा बीसीसीआइ

क्रिकेट डायरी

नई दिल्ली, जेएनएन: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) आगामी एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट की मेजबानी यूएई में करने के लिए तैयार है और इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। जानकारी के अनुसार एशिया कप आठ से 28 सितंबर के बीच आयोजित किया जा सकता है। ढाका में गुरुवार को एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बैठक के बाद यह निर्णय किया गया, जिसमें बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वर्चुअली रूप से शामिल हुए। एसीसी के सभी 25 सदस्य देशों ने आयोजन स्थल पर चर्चा में हिस्सा लिया।

सूत्रों के अनुसार, टूर्नामेंट आइसीसी टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के तहत टी-20 प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। सभी मैच 28 सितंबर से पहले समाप्त हो जाएंगे। इस बार टूर्नामेंट में पिछले संस्करण की छह टीमों की जगह आठ टीमें खेलेंगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग। सूत्रों के मुताबिक, अगर ड्रा अपेक्षित रूप से होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम दो मुकाबले हो सकते हैं। एक ग्रुप चरण में और एक सुपर फोर में। पीसीबी और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने फिलहाल आधिकारिक पुष्टि से इन्कार किया है लेकिन बातचीत जारी रहने की बात कही है।

अगले साल इंग्लैंड में पांच टी-20 और तीन वनडे खेलेगा भारत

मैनचेस्टर, प्रेट्र : इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत अगले साल सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा जिसमें पांच टी-20 और तीन वनडे मैच शामिल हैं। भारत का दौरा एक जुलाई को डरहम में टी-20 मैच से शुरू होगा और 19 जुलाई को लाइर्स में तीसरे वनडे के साथ समाप्त होगा। भारतीय महिला टीम भी अगले साल फिर से इंग्लैंड का दौरा करेगी। वह इंग्लैंड की महिला टीम के विरुद्ध तीन मैचों की टी20 सीरीज और एक टेस्ट मैच खेलेगी। टी-20 सीरीज 28 मई को चेम्सफोर्ड में शुरू होगी। उसके बाद 30 मई को ब्रिस्टल और दो जून को टान्टन में मैच खेले जाएंगे। एकमात्र टेस्ट मैच 10 जुलाई से लाइर्स में खेला जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार, बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टेस्ट टीम दो टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की मेजबानी भी करेगी।

भारत का इंग्लैंड दौरा (2026)

तिथि	मैच	स्थान
एक जुलाई	पहला टी-20	डरहम
चार जुलाई	दूसरा टी-20	मैनचेस्टर
सात जुलाई	तीसरा टी-20	नाटिंघम
नौ जुलाई	चौथी टी-20	ब्रिस्टल
11 जुलाई	पांचवां टी-20	साउथम्पटन
14 जुलाई	पहला वनडे	बर्मिंघम
16 जुलाई	दूसरा वनडे	कार्डिफ
19 जुलाई	तीसरा वनडे	लाइर्स

दिव्या और हंपी में होगा खिताबी मुकाबला

भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में चीन की तिंगजी लेई को टाइब्रेक में हराया

बाटुमी (जार्जिया), प्रेट्र : भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी ने गुरुवार को चीन की तिंगजी लेई को टाईब्रेक में हराकर फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका सामना अब हमवतन दिव्या देशमुख से होगा। यह पहली बार है, जब टूर्नामेंट का फाइनल दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेला जाएगा। हंपी और दिव्या दोनों ने इस जीत के साथ अगले साल होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हंपी और दिव्या की जीत दिखाती है कि पुरुषों के बाद अब महिला शतरंज में भी भारत का दबदबा दिखाई देने लगा है।

हंपी और लेई के बीच नार्मल टाइम कंट्रोल में दोनों मुकाबले ड्रा रहे, जिसके बाद टाईब्रेक खेला गया। पहले 15 मिनट के दो टाईब्रेक गेम्स भी 1-1 से बराबर रहे। इसके बाद 10-10 मिनट के टाईब्रेक सेट में लेई ने बढ़त बनाई, जब हंपी मध्य खेल में चूक गईं और एक प्यादा गंवा बैठीं। एंडगेम में विरोधी रंग के बिशप्स होने के बावजूद लेई का दबदबा रहा और हंपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद 'विन आन डिमांड' गेम में हंपी ने जबरदस्त वापसी की और क्वींस पान ओपनिंग में शुरुआत से ही दबदबा बनाते हुए बेहतरीन तकनीक से जीत दर्ज की। तीसरे टाईब्रेक सेट में हंपी ने सफेद मोहरों से खेलते हुए लेई को हर क्षेत्र में पछाड़ा। इस जीत के बाद उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए केवल ड्रा की जरूरत थी, लेकिन हंपी ने वापसी गेम में इटालियन ओपनिंग के जरिए एक और शानदार जीत दर्ज की। यह फाइनल हंपी के लिए खास होगा क्योंकि अब तक उनके करियर में विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप का खिताब ही अधूरा रह गया है। बाकी सभी बड़े खिताब वह पहले ही अपने नाम कर चुकी हैं। अब सभी की निगाहें शनिवार को शुरू हो रहे फाइनल पर होंगी, जिसमें अनुभव और युवा जोश की टक्कर देखने को मिलेगी।

चीन की तिंगजी लेई से खेलतीं कोनेरू हंपी ● एक्स

आइओए ने सीईओ की नियुक्ति को दी मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: लंबे विवाद के बाद भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) की कार्यकारी परिषद ने गुरुवार को सीईओ रघुराम अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और डोपिंग से निपटने के लिए पैनल का भी गठन किया है। कार्यकारी समिति की अध्यक्ष पीटी उषा सहित अन्य सदस्यों की संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई।

2036 ओलिंपिक की दावेदारी के लिए राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान आइओसी ने भारत के खराब रिकार्ड पर चिंता जताई थी। इससे पहले कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने जनवरी 2024 में अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। जिसका मुख्य कारण सीईओ का 20 लाख रुपये प्रति माह का वेतन और अन्य भत्ते होना था। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के हस्तक्षेप के बाद इस मामले पर अब मतभेद सुलझ गए हैं। अय्यर ने बताया कि सात सदस्यीय डोपिंग रोधी पैनल का नेतृत्व रोहित राजपाल करेंगे।

27 या 28 अगस्त को हो सकता है बीएफआइ चुनाव : अजय सिंह

लोकेश शर्मा ● जागरण

नई दिल्ली: भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लंबे समय से कानूनी अड़चनों में फंसे बीएफआइ चुनाव अब अगस्त के अंत तक कराए जाने की तैयारी में हैं। बीएफआइ के अध्यक्ष अजय सिंह ने स्पष्ट किया कि बीएफआइ के चुनाव 27 या 28 अगस्त को कराए जा सकते हैं। वर्ल्ड बाक्सिंग ने अंतरिम समिति को 31 अगस्त तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया मार्च में शुरू कर दी गई थी, लेकिन न्यायिक अड़चनों की वजह से इसे रोकना पड़ा। अब स्थिति स्पष्ट है और हम तय समयसीमा के भीतर चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। नई दिल्ली को चुनाव स्थल के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। बीएफआइ ने हाल ही में ब्राजील और कजाखस्तान में आयोजित विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए 17.5 लाख रुपये की इनामी राशि की घोषणा की। पूर्व ओलिंपियन विजेंदर सिंह भी बीएफआइ की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अजय सिंह ने बताया कि हमने विजेंदर से अनुरोध किया है कि वे कुछ ट्रेनिंग कैंप की निगरानी करें।

पदक विजेताओं के साथ अजय सिंह व विजेंद्र सिंह ● आयोजक

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

****

रैपिड फायर

शाह रुख खान पर केस करूंगी

अभिनेत्री वरखा सिंह इन दिनों ओटीटी पर सक्रिय हैं। वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस 4 में युवा वकील शिवानी माथुर की भूमिका में नजर आई वरखा से कुछ फटाफट सवाल-जवाब :

- **किसी कलाकार पर केस करना हो तो किस पर करेंगी?**

मैं शाह रुख खान पर केस करूंगी कि आपको कोई हक नहीं कि आप इतने सारे लोगों के दिल चुराएं।

- **इस केस में जज किसे रखना चाहेंगी?**

(हंसते हुए) इसकी जज उनकी पत्नी गौरी मैम को बनाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि वो मेरे पक्ष में निर्णय देंगी।

- **स्क्रीन पर पसंदीदा वकील कौन हैं?**

क्रिमिनल जस्टिस के माधव मिश्रा (पंकज त्रिपाठी)।

- **पसंदीदा रोमांटिक सीन, जिसे देखकर मन करता हो कि काश मैंने इसमें अभिनय किया होता?**

फिल्म कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी और शाह रुख खान के बीच का वो सीन जिसमें शाह रुख चुटकी बजाते हैं और रानी ओम जय जगदीश हरे आरती गाती हैं।

- **पसंदीदा रोमांटिक डायलाग?**

कुछ कुछ होता है फिल्म का ही डायलाग है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार होता है।

- **प्यार व्यक्त करने का बेस्ट तरीका?**

सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराना। उसके मन की बात समझने की कोशिश करना।

- **प्यार में बढ़ते कदम कब रोक देंगी?**

जब कोई झूठ बोले, किसी का अपमान करता दिखे।

- **सपना जो अधूरा हो?**

मुझे जासूस की भूमिका निभानी है। जिसमें एक्शन और खोजबीन करने को मिले।

- **सबसे अनुशासित कलाकार कौन लगा?**

माधुरी दीक्षित मैम। फिल्म मजा मा की शूटिंग के दौरान वह कभी लेट नहीं हुईं, वह पूरी तैयारी करके आती थीं।

- **किसके साथ काम करने से पहले सबसे ज्यादा नर्वस थीं?**

सुभाष घई निर्देशित फिल्म 36 फार्महाउस में विजय राज सर के साथ काम करने से पहले बहुत नर्वस थी। हालांकि, उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया।

दीपेश पांडेय

क्लासिक फिल्मों के क्लाइमेक्स में एआइ का तड़का

रांझणा फिल्म के अंत को एआइ से बदलने पर बहस छिड़ी है। एआइ के प्रयोग से कल्ट फिल्मों में बदलाव की वजह, भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं **स्मिता श्रीवास्तव**

रांझणा में धनुष व सोनम कपूर

शोले में धर्मेंद्र व हेमा मालिनी

गब्बर बने अमजद खान

चर्चा में

करीब 12 साल पहले आई फिल्म रांझणा वाराणसी में जाकर बस गए तमिल ब्राह्मण परिवार के बेटे कुंदन (धनुष) और जोया (सोनम कपूर) की कहानी थी। कालेज में जसजीत (अभय देओल) की जोया से मुलाकात के बाद दोनों की शादी होने वाली होती है, तभी कुंदन उसका झूठ उजागर कर देता है। उसमें जसजीत की जान चली जाती है। जोया इसके लिए कुंदन को जिम्मेदार समझती है। आखिर में प्रेम के लिए कुंदन बलिदान दे देता है। इस क्लाइमेक्स ने दर्शकों को झकझोर दिया था। अब इस फिल्म के अंत को सुखद बनाया जा रहा है एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से। इस फिल्म के नए डब वर्जन को एक अगस्त को तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाएगा। यह हिंदी फिल्म 2013 में तमिल में अंबिकापथी के नाम से प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के अधिकार इरोस इंटरनेशनल के पास हैं।

फिल्म के निर्देशक आनंद एल राय ने 'रांझणा' के पुनः प्रदर्शित होने वाले संस्करण में एआइ-जनित सुखद अंत का कड़ा विरोध किया है। इस संदर्भ में फिल्म की निर्माता कंपनी इरोस इंटरनेशनल के ग्रुप सीईओ प्रदीप द्विवेदी कहते हैं कि तमिलनाडु में रांझणा का पुनः प्रदर्शन इरोस इंटरनेशनल की क्षेत्रीय बाजार को पुनर्जीवित करने की रणनीति का हिस्सा है। तमिलनाडु का इस फिल्म से खास जुड़ाव है। न सिर्फ अभिनेता धनुष के शानदार अभिनय के कारण, बल्कि नायक के तमिल जुड़ाव के कारण भी। यहां एआइ ने कहानी कहने में सहायक की भूमिका निभाई है। वैकल्पिक अंत एक रचनात्मक रीइंटरप्रिटेशन (पुनर्व्याख्या) है, न कि उसका रीप्लेसमेंट (प्रतिस्थापन)। फिलहाल रांझणा को हिंदी में वैकल्पिक अंत के साथ प्रदर्शित करने की कोई योजना नहीं है। आनंद एल राय ने कहा था कि एआइ भविष्य है, लेकिन इसका इस्तेमाल भविष्य के लिए करें, अतीत को विकृत करने के लिए नहीं। इस बाबत प्रदीप कहते हैं कि हम फिल्म को विकृत नहीं कर रहे हैं। एआइ किस्सागोई को रुचिकर बनाने का तरीका हो सकता है। मूल रांझणा का आकर्षण अछूता है।

बीते दिनों शोले का रीस्टोर वर्जन पेश किया गया था, जिसमें गब्बर मारा जाता है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा कहते हैं कि चाहे शोले हो या रांझणा उसका पांच-सात मिनट का क्लाइमेक्स बदलकर नई फिल्म की तरह नहीं लिया जा सकता है। शोले एक लैंडमार्क फिल्म है, नई फुटेज देखने को मिलेगी तो चर्चा यकीनन होगी, पर ये ट्रेंड बनेगा इसकी संभावना कम ही है।

एआइ से होने वाले बदलाव भविष्य में फिल्म निर्माण के लिए खतरे का संकेत माने जा रहे हैं। इस बाबत फिल्म निर्माता दीपक मुकुट कहते हैं कि एआइ में इमोशन नहीं होते हैं। सनम तेरी कसम फिल्म के पुनः प्रदर्शन के समय हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया था। उसका परिणाम अच्छा ही आया। अगर मैं उसमें बदलाव करूंगा तो वह गलत हो जाएगा। लगेगा कि उस वक्त हमने रचनात्मक तौर पर सही नहीं किया था। अब उसे बदल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जिन फिल्मों को हम बनाकर प्रदर्शित कर चुके हैं उनमें एआइ सरीखी चीजों को लाने करने की जरूरत है। अगर आप कोई नई फिल्म एआइ की मदद से बनाते हैं तो उसे एआइ फिल्म ही कहा जाएगा। मेरा मानना है कि बदलाव के साथ अंत को प्रदर्शित करना महज प्रयोग है। हाउसफुल 5 को भी दो क्लाइमेक्स के साथ प्रदर्शित किया गया था। निर्माता के पास फैसले लेने का हक है। बाकी निर्णय जनता ही करेगी।

वहीं फिल्म एग्जीबिटर अक्षय राठी कहते हैं कि एआइ से बदलाव रोचक प्रयोग हो सकता है, लेकिन आडियंस फिल्म को वापस इसलिए देखने आती है क्योंकि उन्हें पहले भी पसंद आई थी। रांझणा हिट रही थी। यह बता पाना मुश्किल है कि नए क्लाइमेक्स पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन जिस फिल्म की कल्ट वैल्यू हो उसमें संभावनाए इसके विरुद्ध ही दिखती हैं।

एआइ का मनमाना प्रयोग ना हो

एआइ के प्रयोग से कल्ट फिल्मों पर क्या असर पड़ेगा? इस संदर्भ में रांझणा की निर्माता कंपनी इरोस इंटरनेशनल के ग्रुप सीईओ प्रदीप कहते हैं कि किसी भी उपकरण की तरह, एआइ का इस्तेमाल जिम्मेदारी और स्पष्ट रचनात्मक उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए। इरोस सिनेमाई उत्कृष्टता को बदलने के लिए एआइ के मनमाने इस्तेमाल का समर्थन नहीं करता है। रांझणा के मामले में यह एक सोचा-समझा प्रयास था, जिसे एक खास दर्शक वर्ग के लिए हमने तैयार किया है। एआइ रीमेक का व्यापक ट्रेंड हमारा रुख नहीं है। हम नवाचार और कहानी कहने के उद्देश्य में विश्वास करते हैं।

देखने वाली बात

बीते दिनों शोले के रीस्टोर्ड वर्जन को इटली के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में मूल क्लाइमेक्स के साथ प्रदर्शित किया गया था। इसमें गब्बर (अमजद खान) मरता है। हालांकि 50 साल पहले जब फिल्म आई थी तब सेंसर बोर्ड के निर्देश पर क्लाइमेक्स को बदलना पड़ा था और गब्बर की गिरफ्तारी दिखाई गई थी। कल्ट फिल्मों के अंत को बदलाव के साथ पुनः प्रदर्शित करने पर ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा कहते हैं कि यह देखने वाली बात होगी कि दर्शकों को बदला हुआ कांसेप्ट पसंद आएगा या नहीं। बदले हुए क्लाइमेक्स के साथ दर्शक स्वीकार लेते हैं तो माना जाएगा कि तकनीक से बदलाव करके तो बात बन जाती है।

सिनेप्रेमियों पर चढ़ा रंग इश्क का

बाक्स आफिस रिपोर्ट

सैयारा यानी तारों के बीच भटकता एक सितारा, जो अपनी चमक से दूसरों की जिंदगियों को रोशन करता है। नवोदित कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा अभिनीत फिल्म सैयारा ने सौ करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर बड़े फिल्मकारों को चौंका दिया। इसकी सफलता के कारणों की पड़ताल कर रही हैं प्रियंका सिंह

सैयारा में अनीत पड्डा और अहान पांडे

सैयारा प्रदर्शित होने के बाद से ही सिनेमाघरों से ऐसे वीडियो आ रहे हैं, जहां कोई आइवी ड्रिप लगाकर फिल्म देखने पहुंचा तो कोई फूट-फूटकर रोया। फिल्म की लहर का ही प्रभाव है कि अजय देवगन की फिल्म सन आफ सरदार 2 के प्रदर्शन की तारीख एक सप्ताह आगे बढ़ा दी गई। फिल्म को पहले दिन 22 करोड़ की ओपनिंग मिली। वीकेंड के बाद आमतौर पर सोमवार को फिल्म की कमाई में कमी दिखती हैं, वहीं सैयारा ने सोमवार को भी 24.25 करोड़ रुपये कमा लिए। इस फिल्म को राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर राज बसंल कहते हैं कि यशराज फिल्म्स की रणनीति थी कि फिल्म को लेकर उम्मीदें नहीं बढ़ानी हैं। नई स्टारकास्ट है तो धीरे-धीरे व्यापार बढ़ेगा। हमें सिनेमाघर मालिकों से झगड़ना पड़ता है कि ज्यादा शो दो, लेकिन इस बार एडवांस बुकिंग देखते ही, सिनेमाघर वालों ने कहा शो बढ़ाने हैं। इसका कारण था फिल्म का संगीत। दूसरा कारण निर्देशक मोहित सूरी हैं, जो प्रेम कहानी बनाने में एक्सपर्ट हैं।

काम आई रणनीति: प्रदर्शन से पहले फिल्म की टीम प्रमोशन में जुटती है। यहां पारंपरिक प्रमोशन के नाम पर न फिल्म की टीम ने शहरों की धूल छानी, न इंटरव्यू दिए। इंस्टाग्राम स्क्रोल करते वक्त सैयारा के गानों पर कभी रील नजर आ जाती थी तो कभी यह लिखकर आ जाता था कि 18 जुलाई (सैयारा की प्रदर्शन तिथि) को क्या कर रहे हो, सैयारा देखने चलें? फिल्म बिजनेस एनालिस्ट तरण आदर्श कहते हैं कि पिछली सदी के सातवें-आठवें दशक में फिल्मों के पोस्टर लगते थे, रेडियो पर गाने आने लगते थे। फिल्म के प्रदर्शन से पहले अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जैसे सितारे तो इंटरव्यू भी नहीं देते थे। यशराज फिल्म्स उस दौर को जी चुका है। प्रमोशन के लिए केवल मोहित सामने आए और बिना किसी ड्रामेबाजी के फिल्म को लेकर बात की। कास्टिंग में ताजगी थी। पिछले कुछ साल से मसाला, कामेडी, एक्शन फिल्में बन रही हैं। सैयारा इस बीच ताजी हवा के झोंके की तरह आई है, इसलिए दर्शक आकर्षित हो रहे हैं।

सैयारा की तुलना आशिकी 2, राकस्टार जैसी फिल्मों से हो रही है। इसमें भी हीरो संगीत से जुड़ा है, गुस्सैल है, लेकिन सैयारा का अंत सुखद है। फिल्म के अंत में मोहित उम्मीद छोड़ जाते हैं कि प्यार कठिनाइयों को झेलकर भी जीतता है।

कमाई का रिपोर्ट कार्ड

पहला दिन	22 करोड़
शनिवार	26.25 करोड़
रविवार	36.25 करोड़
सोमवार	24.25 करोड़
मंगलवार	25 करोड़
बुधवार	22 करोड़

कोई चुनौती बड़ी नहीं होती

दिल से

कई बार पात्रों की वजह से कलाकारों को कुछ चीजें करीब से जानने-समझने का मौका मिलता है। ऐसा ही कुछ रहा अभिनेता **इश्वाक सिंह** के साथ। वेब सीरीज राकेट ब्वायज में विज्ञानी की भूमिका निभाने के बाद अब उन्होंने अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रदर्शित वेब सीरीज मिट्टी एक नई पहचान में कृषक की भूमिका निभाई है।

गांव से जुड़ाव को लेकर इश्वाक बताते हैं, 'जब मैं थिएटर ग्रुप में था, तो हमें कई बार गांव और छोटे शहरों में जाकर परफार्म करने मौका मिलता था। उसकी कुछ यादें थीं, एक बार परिवार के साथ भी किसी गांव में जाने का मौका मिला था। हालांकि गांव और खेती से कोई सीधा जुड़ाव नहीं रहा। मेरे दादा जी पंजाब के गुरदासपुर से थे, अब वहां पर स्वजन नहीं रहते हैं। मुझे ग्रामीण जीवन का अनुभव चाहिए था, जो इस शो के माध्यम से मुझे मिला। शूटिंग के दौरान जब हम छत पर जाकर गांव की हरियाली, खूबसूरती और शांति देखते थे, वो दृश्य मेरे लिए दिल को छू लेने वाला होता था। मेरा पात्र आधुनिक खेती करके ऋण के पैसे अदा करता है। उन्नत कृषि से सपनों को पूरा कर सकते हैं, यह विचार एक नई उम्मीद उत्पन्न करता है।' इश्वाक बताते हैं, 'मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है। जब मन में कलाकार बनने का खयाल आया तो स्वयं से ही सवाल किया कि ये कितना उचित रहेगा? घर में यह बताना कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूं, ये भी एक बड़ा कदम था, पर मन को मजबूत किया। अपने सपनों के लिए ऐसा करना पहली शर्त है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच हर कदम पर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जब लोग कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, पर आत्मविश्वास हो तो कोई चुनौती बड़ी नहीं होती।'

दीपेश पांडेय

इस पेज के बारे में अपनी राय और सुझाव भेजें- feature@jagran.com

मनोरंजन के हर अपडेट और अधिक खबरों के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।

आज का भविष्यफल-25 जुलाई, 2025 शुक्रवार

पं. के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रहस्थिति : श्रावण मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का राशिफल।
आज का राहुकाल- प्रातः 10:30 से 12 बजे तक।
आज का दिशाशूल- पश्चिम
विशेष- श्रावण मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ

कल 26 जुलाई, 2025 का पंचांग

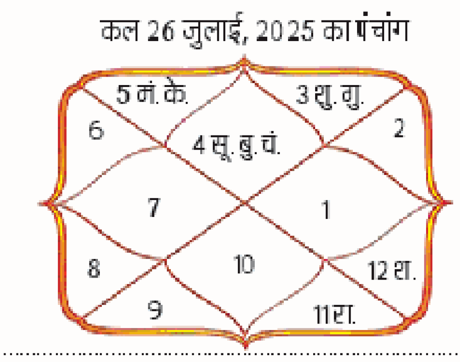

कल का दिशाशूल- पूर्व
कल का पर्व एवं त्योहार- श्रृंगार द्वितीया
विशेष- शुक्र मिथुन राशि में।
विक्रम संवत 2082 शके 1947 दक्षिणायण, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया 22 घंटे 43 मिनट तक, तत्पश्चात तृतीया अश्लेषा नक्षत्र 15 घंटे 52 मिनट तक, व्यतिपात योग कर्क में चंद्रमा 15 घंटे 52 मिनट तक तत्पश्चात सिंह में।

मेष : शुक्र गुरु की युति पुरुषार्थ को प्रभावी करेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रिश्तों में निकटता आएगी।

वृष : शुक्र गुरु की युति से आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। दांपत्य में सुधार होगा। प्रयास फलीभूत होगा।

मिथुन : व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कर्क : जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी लेकिन शुक्र गुरु की युति व्यय अधिक कराएगी। आर्थिक तनाव बढ़ेगा।

सिंह : शनि का लघुकल्याणकारी ढय्या के लिए छाया दान करें। शमी के वृक्ष को लगाएं और जल अर्पित करें।

कन्या : शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा। पिता का प्रोत्साहन रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

तुला : मादक वस्तुओं पर नियंत्रण रखें। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।

वृश्चिक- आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। शुक्र गुरु आपकी राशि से आठवें हैं, कर्मक्षेत्र में बाधाएं आएंगी।

धनु : आपकी राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढय्या चल रहा है। सुख में व्यवधान रहेगा। छाया दान करें।

मकर : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी लेकिन संतान से मतभेद रहेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ : संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। बुद्धि कौशल से कार्य संपन्न होगा। रचनात्मक सफलता मिलेगी।

मीन : भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। शनि की साढ़े-साती चल रही है लेकिन शुक्र गुरु की युति सफलता देगी।

वर्ग पहेली-3054

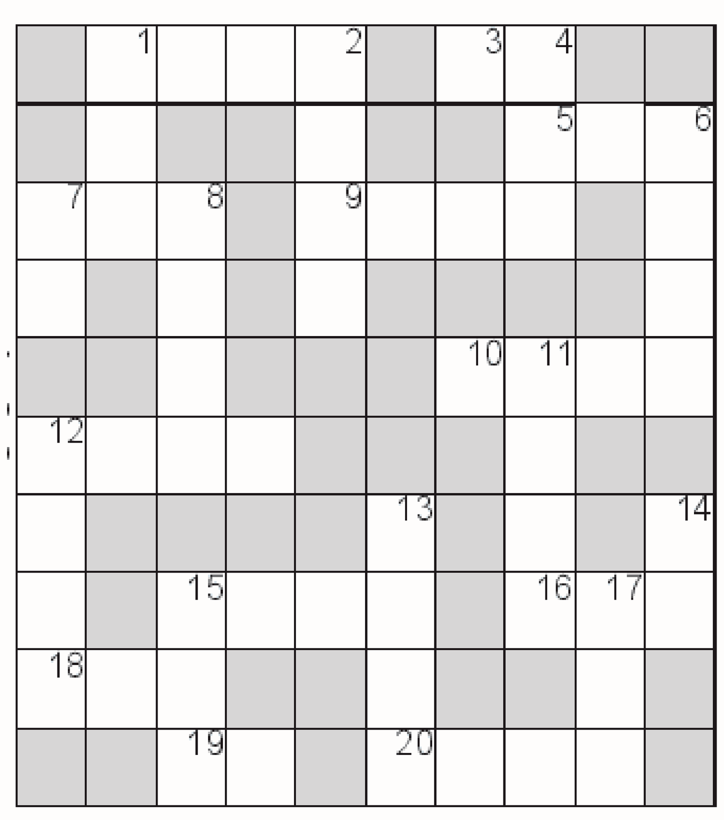

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं :-
1 उत्तराधिकार में प्राप्त धन (4)। 3 निकट, नजदीक (2)। 5 पैर के बिल्कुल नीचे का चिपटा अंश (3)। 7 अचानक, एकाएक (3)। 9 आदि, इत्यादि (4)। 10 परखने का भाव (4)। 12 गणेश, जिसका उदर लंबा हो (4)। 15 ज्ञान प्राप्त करना, अनुमान लगाना (4)। 16 बेवजह, व्यर्थ (3)। 18 बल, शक्ति (3)। 19 गीला, आर्द्र (2)। 20 क्रुद्ध दृष्टि से देखना (4)।

ऊपर से नीचे :-
1 वियोग, अभाव (3)। 2 वह वन जहां बहुत तपस्वी तपस्या करते हैं (4)। 4 वस्तु का ऊपरी भाग या विस्तार, तल (3)। 6 एक प्राचीन जनपद का नाम, झरोखा (4)। 7 एक फिल्म है- सत्ते पर ... (2)। 8 कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत (4)। 11 चकित रह जाना (4)। 12 दुराचारिता (4)। 13 जो अब तक नहीं आया हो, भावी (4)। 14 प्रतिष्ठा (2)। 15 लगातार, निरंतर (3)। 17 दूर करना, हरण करना (3)।

कल का हल

जागरण सुडोकू-3054

7					3		1	
	4			8	6			7
		8	7			6	2	
		4	3			1	6	
	7			4				2
8					5			
5			8		7			3
	2	7		3		8	9	
	8			1			5	

कल का हल

8	6	1	2	5	7	9	3	4
9	5	2	4	3	6	1	8	7
4	7	3	8	9	1	2	5	6
3	1	4	6	7	2	8	9	5
2	9	7	5	8	4	3	6	1
5	8	6	3	1	9	4	7	2
1	3	8	7	2	5	6	4	9
7	4	9	1	6	3	5	2	8
6	2	5	9	4	8	7	1	3

राष्ट्रीय फलक

हरिद्वार मंदिर के लिए रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को सुप्रीम चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : हरिद्वार स्थित मां चंडी देवी मंदिर के सेवायत ने बद्री-केदार मंदिर समिति को मंदिर के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक रिसीवर नियुक्त करने के निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सेवायत का अर्थ उन पुजारियों से है, जो मंदिरों के दैनिक अनुष्ठानों और प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।

महंत भवानी नंदन गिरि ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बिना किसी साक्ष्य और शिकायत के मंदिर का नियंत्रण एक समिति को सौंप दिया, जबकि हाई कोर्ट द्वारा 2012 में ही हरिद्वार के डीएम और एसएसपी की एक समिति गठित की जा चुकी थी। अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक आपराधिक मामले में एक आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।

दक्षिणा के लिए पंडों में चली कैंची, चौकी प्रभारी समेत 24 लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, मीरजापुर

विंध्यधाम में बीते बुधवार दोपहर को दक्षिणा के 750 रुपये के बंटवारे के लिए पंडों में भिड़ंत हो गई। मारपीट के बाद एक पक्ष ने कैंची से हमला कर विपक्षी पंडे को घायल कर दिया। विंध्यधाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिनदहाड़े इस खूनी संघर्ष को एसएसपी सोमने बर्मा ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में विंध्यधाम चौकी प्रभारी राजकुमार पांडेय सहित 24 पुलिसकर्मियों को देर रात लाइन हाजिर कर दिया। वहीं बीट प्रभारी आरक्षी कांताराम को निलंबित कर विभागीय जांच भी बैठा दी है।

बुधवार दोपहर में पंडा निवेदित भट्ट धाम में न्यू वीआइपी गेट संख्या दो पर एक दुकान पर बैठे थे। इसी बीच विपक्षी उत्तम पांडेय भाई और पिता के साथ पहुंचे और पूजापाठ के मिले साढ़े सात सौ रुपये के बंटवारे को लेकर कहासुनी करने लगे। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।

750 रुपये के बंटवारे में विवाद, एसएसपी ने विंध्यधाम में तैनात पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई

इसी बीच उत्तम पांडये पक्ष की ओर से कैंची निकालकर हमला बोल दिया गया। विंध्याचल कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने चिरंजीव पांडेय, उनके पुत्रों उत्तम व उत्कर्ष पर मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लगे सीसीटीवी की जांच की गई तो हमले के दौरान कोई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा नहीं पाया गया। एसएसपी ने मामले की जांच एएसपी सिटी नितेश कुमार सिंह से कराई। जांच में लापरवाही पाए जाने पर धाम चौकी प्रभारी राजकुमार पांडेय समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। राजकुमार पांडेय का विंध्यधाम चौकी से तीन जुलाई 2024 को लालगंज थाना तबादला हुआ था, मगर नहीं गए। दूसरी बार मई 2025 में कटरा कोतवाली के बरौंधा पुलिस चौकी पर तबादला हुआ, वहां भी नहीं गए।

अजमेर दरगाह के नाजिम के नोटिस पर मुस्लिम संगठनों को आपत्ति

जागरण संवाददाता, जयपुर : अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के नाजिम द्वारा जारी नोटिस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम संगठनों ने नोटिस पर कड़ी आपत्ति जताई है। नाजिम मोहम्मद बेलाल खान द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नोटिस में दरगाह में आने वाले लोगों को संभावित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि दरगाह परिसर के भीतर पुरानी संरचनाओं के कारण दुर्घटना की स्थिति में प्रशासन कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।

मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन ने इसे शर्मनाक और जिम्मेदारी का पतन बताया है। फेडरेशन के अध्यक्ष अब्दुल सलाम जौहर ने नाजिम को पत्र लिखकर कहा कि सामूहिक आध्यात्मिक महत्व वाले स्थान पर इस तरह का अस्वीकरण अस्वीकार्य है। प्रशासन को मरम्मत पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान मुस्लिम अलायंस के मोहसिन रशीद ने भी नाजिम के नोटिस को उचित नहीं बताया।

रीलबाजों ने रेल पटरी पर रखे पत्थर, उनकी रील ने ही कराया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बदायूं

रील बनाने की सनक में दो युवकों ने कासगंज-अलीगढ़ पैसेंजर के यात्रियों को खतरे में डाल दिया। दोनों आरोपित ने रेल पटरी पर पत्थर रखकर रील बनाई फिर भाग गए। उसी रील के सहारे आरपीएफ ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को आरोपित मेजुद्दीन मियां और मुजेर मियां को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

11 जुलाई को कासगंज से पैसेंजर ट्रेन बदायूं की ओर जा रही थी। रास्ते में मेजुद्दीन व मुजेर ने पटरी पर कुछ पत्थर रख दिए। फिर मोबाइल फोन से रील बनाने लगे। लोको पायलट ने दूर से देखकर हार्न दिया तो दोनों युवक समय रहते पटरी से हट गए, परंतु पत्थर वहीं रखे रहे। आरपीएफ के अनुसार ट्रेन पत्थर को रौंदते हुए निकल गई, मगर इंजन का यार्ड टेढ़ा हो गया था। लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, मगर आरोपितों की पहचान चुनौती थी। आरपीएफ के पोस्ट कमांडर रामप्रताप ने बताया कि घटनास्थल के आसपास कई लोगों से पूछताछ की। कई ऐसे युवकों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट खंगाले गए, जो रील बनाने का शौक रखते हैं। इसी प्रयास में दोनों आरोपितों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 11 जुलाई की पटरी पर बनाई गई रील मिल गई। आरपीएफ की सक्रियता देखकर आरोपितों ने अकाउंट से रील डिलीट कर दी थी, मगर साक्ष्य पहले ही एकत्र हो चुके थे।

रेलवे पुलिस द्वारा पकड़े गए पत्थर रखने के आरोपित। रेलवे पुलिस

झारखंड में बदला अटल मुहल्ला क्लीनिक का नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को स्वीकृति देते हुए विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के अधिकार सीमित किए हैं। विधेयक के लागू होने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों समेत सभी पदों पर नियुक्ति का पूरा अधिकार अब राज्य सरकार के पास होगा।

झारखंड में अब एक अधिनियम (सिंगल अंब्रेला एक्ट) से राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां होंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने राज्य योजना अन्तर्गत संचालित अटल मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ये क्लीनिक छोटे-छोटे मुहल्लों, झुग्गी-झोपड़ियों तथा बस्तियों में चलाई जाती हैं। जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, ऐसे कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वेतन वृद्धि दी जाएगी।

****

दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जाय ब्राउन का जन्म हुआ

1978 में आज ही के दिन इंग्लैंड में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) के जरिये दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। इस क्रांतिकारी तकनीक की खोज डा. राबर्ट एडवर्ड्स और डा. पैट्रिक स्टेप्टो ने की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनीं स्वेतलाना

1984 में आज ही सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सवित्स्काया अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी थीं। वह सोयूज टी-12 मिशन का हिस्सा थीं, जो सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरा था। अंतरिक्ष में उपकरणों का परीक्षण करते हुए उन्होंने 3.5 घंटे बिताए।

जिम कार्बेट के प्रयास से भारत को मिला पहला नेशनल पार्क

एडवर्ड जेम्स कार्बेट (जिम कार्बेट) का जन्म 1875 में आज ही नैनीताल में हुआ। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन घने जंगलों में बिताया और समय के साथ एक कुशल शिकारी बने। गढ़वाल और कुमायूं में नरभक्षी बाघों का शिकार कर ख्याति प्राप्त की। उनके नाम 19 बाघों और 14 तेंदुओं को मारने का रिकार्ड है। हालांकि, बाघों की घटती संख्या और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव को देखकर उन्होंने शिकारी से संरक्षणवादी का मार्ग अपनाया। कार्बेट ने भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

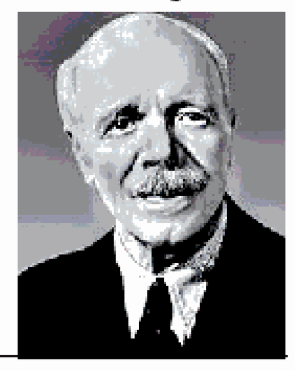

भारत समेत एशिया में कैंसर नियंत्रण की योजनाएं कमजोर

रिपोर्ट ▸ एशियाई देशों में वायु प्रदूषण से बढ़ रहा है कैंसर का खतरा

रिपोर्ट में 21 देशों को किया गया शामिल, एम्स ने किया भारत का प्रतिनिधित्व

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एशियाई देशों में वायु प्रदूषण से कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे रोकने और नियंत्रित करने की योजनाएं अभी भी कमजोर नजर आ रही हैं। यह जानकारी हाल ही में 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल में प्रकाशित एक बड़ी समीक्षा में सामने आई है। इसमें एशिया के 21 देशों को शामिल किया गया।

इस समीक्षा में भारत का प्रतिनिधित्व एम्स दिल्ली के रेडिएशन आन्कोलाजी विभाग के डा. अभिषेक शंकर ने किया। रिपोर्ट के अनुसार, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कैंसर रोकथाम की पांच वर्षीय योजनाओं को अपनाकर मृत्यु दर को कम किया है, जबकि कई अन्य देशों की स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक स्थिति के अलावा भी कई कारक राष्ट्रीय कैंसर योजनाओं को प्रभावित करते हैं। केवल नीति बनाना पर्याप्त नहीं है, उपचार, जांच और जीवन के अंतिम चरण की देखभाल को मजबूत करना जरूरी है। एम्स के डा. अभिषेक शंकर के अनुसार, कैंसर नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने की जरूरत है। वायु प्रदूषण जैसे बड़े कारकों को योजनाओं में शामिल कर ठोस कार्रवाई करनी होगी।

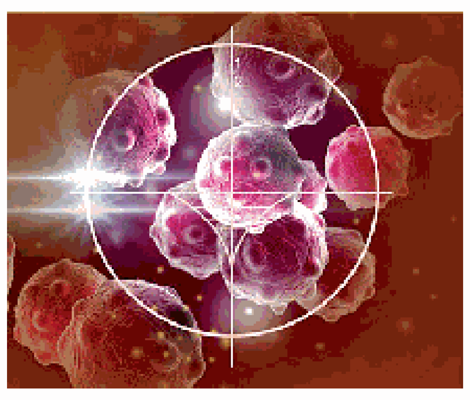

कैंसर के बढ़ते मामले चिंता का विषय। फाइल

वायु प्रदूषण से कैंसर की रोकथाम पर क्या है स्थिति : वायु प्रदूषण से कैंसर के खतरे को 43 प्रतिशत योजनाओं में शामिल किया गया। इनमें ज्यादातर मध्यम आय वर्ग के देश हैं। 91 प्रतिशत योजनाओं में इलाज का प्रोटोकाल शामिल है, पर अंतिम चरण की देखभाल 48 प्रतिशत योजनाओं में दिखाई दी।

कैंसर के मामले और मौत का बोझ : एशिया में विश्व की 59 प्रतिशत आबादी रहती है। 49.2 प्रतिशत नए कैंसर यहीं सामने आते हैं। 56.1 प्रतिशत कैंसर से मौतें भी एशिया में होती हैं। 2050 तक एशिया में कैंसर से मौत के मामले 97.1 प्रतिशत तक बढ़ने की आशंका है।

सिर्फ 28 .5 प्रतिशत कैंसर रोगियों को ही मिल पाती है रेडियोथेरेपी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में केवल 28.5 प्रतिशत कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी मिल पाती है। सामान्य तौर पर 58.4 प्रतिशत कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी की जरूरत होती है, लेकिन मशीनों की कमी से रोगियों को रेडियोथेरेपी नहीं मिल पा रही है। स्तन, सिर व गर्दन, फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से जुड़े 60 प्रतिशत मामलों में रेडियोथेरेपी की जरूरत होती है।

कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। यह ट्यूमर के फैलाव को नियंत्रित करने, सर्जरी से पहले ट्यूमर का आकार कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हालांकि, भारत जैसे देशों में इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार प्रति दस लाख जनसंख्या पर कम से कम एक रेडियोथेरेपी मशीन होनी चाहिए। आदर्श स्थिति में प्रति दस लाख पर चार रेडियोथेरेपी मशीन होनी चाहिए। अध्ययन में कहा गया कि भारत को 1,585 से 2,545 रेडियोथेरेपी मशीनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि निम्न व मध्यम आय वाले देशों में स्तन, सिर और गर्दन तथा फेफड़ों के कैंसर में 70-100 प्रतिशत वृद्धि की आशंका है। कैंसर के वैश्विक मामलों में सात प्रतिशत भारत में मिलते हैं। चीन व अमेरिका के बाद भारत कैंसर से सर्वाधिक प्रभावित देश है। 2025 अंत तक देश में कैंसर के मामले 15.7 लाख तक पहुंचने की आशंका है।

जमीनी ड्रोन

हवाई ड्रोन और पानी पर चलने वाले ड्रोन के बाद अब युद्धक्षेत्र में जमीनी ड्रोन भी काम करने लगे हैं। यह तस्वीर यूक्रेन के कीव प्रांत स्थित जंगल की है, जिसमें एक मानवरहित वाहन दिख रहा है। कैमरा, कम्युनिकेशन व नेविगेशन से लैस यह ड्रोन लड़ाई का नया हथियार है। एएफपी

इधर-उधर की

कीबोर्ड बजाकर मरीजों की एंग्जायटी दूर करता है घोड़ा

वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका में ब्लैक पर्ल नामक एक छोटा घोड़ा सर्जरी के बाद मरीजों की एंग्जायटी को कम करने में अपनी अनोखी भूमिका के लिए चर्चा का विषय बन गया है। कैलिफोर्निया के श्राइनर्स फार चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर में एक बच्ची को बेहोशी से जगाने के लिए ब्लैक पर्ल का कीबोर्ड बजाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में, ब्लैक पर्ल मुंह से कीबोर्ड बजाता नजर आ रहा है, जबकि बच्ची धीरे-धीरे जाग रही है। यह सेवा एनजीओ मिनी थेरेपी हार्सेज ने शुरू की है। यह संस्था अस्पतालों, ट्रामा सेंटरों और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाने के लिए घोड़ों को प्रशिक्षित करती है।

कीबोर्ड बजाता ब्लैक पर्ल नामक घोड़ा। इंटरनेट मीडिया

आकाशीय बिजली से हर साल 32 करोड़ पेड़ों की मौत का अनुमान

▸ यह दुनिया की पौधों की जैव द्रव्यमान हानि का लगभग दो से तीन प्रतिशत

▸ पेड़ों की इस हानि के कारण हर साल 0.77 से 1.09 अरब टन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन होने का अनुमान

आकाशीय बिजली बनती है पेड़ों की मौत का कारण। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : हर साल आकाशीय बिजली से लगभग 32 करोड़ पेड़ मारे जाते हैं, जो दुनिया की पौधों की जैव द्रव्यमान हानि का लगभग दो से तीन प्रतिशत है। एक अध्ययन के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। पेड़ों की इस हानि के कारण हर साल 0.77 से 1.09 अरब टन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन होने का अनुमान है। जर्मनी के तकनीकी विश्वविद्यालय म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने बताया कि यह जंगल की आग में जलने वाले पौधों से हर साल निकलने वाले 1.26 अरब टन कार्बन डाइआक्साइड के बराबर है।

आकाशीय बिजली से मारे गए पेड़ों का अनुमान जर्नल ग्लोबल चेंज बायोलाजी में प्रकाशित हुआ है। टीम ने कहा कि यह उन पेड़ों को शामिल नहीं करता, जो आकाशीय बिजली के कारण होने वाली जंगल की आग में मारे गए हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय म्यूनिख में भूमि सतह-वायुमंडल इंटरैक्शन के शोधकर्ता और मुख्य लेखक एंड्रियास क्राज ने कहा कि जैसे-जैसे ग्रह गर्म होता जा रहा है, आकाशीय बिजली के हमले अधिक सामान्य होने की उम्मीद है, इसलिए यह इस बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई समस्या पर ध्यान देने योग्य है। एंड्रियास क्राज ने कहा कि वर्तमान में आकाशीय बिजली के कारण पेड़ों की मृत्यु दर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक है। हालांकि, यह माडल सुझाव देता है कि आंधी-तूफान की आवृत्ति मुख्य रूप से मध्य और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में बढ़ेगी। इसका अर्थ है कि आकाशीय बिजली से होने वाली पेड़ों की मृत्यु दर समशीतोष्ण और बोरियल जंगलों में भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। लेखकों ने कहा कि ये निष्कर्ष पिछले अध्ययनों के परिणामों का समर्थन करते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आकाशीय बिजली कई जंगलों में पेड़ों की मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण है।

उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली के हमलों के कारण जंगलों को होने वाले नुकसान का पता लगाना कठिन है और इसे दुनिया के कुछ स्थानों में ही व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया है। टीम ने यह भी जोड़ा कि हर साल आकाशीय बिजली से सीधे प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या स्पष्ट नहीं है और उनके शोध ने अनुमान प्रदान करने के लिए पहली विधि विकसित की है। शोधकर्ताओं ने कहा कि आकाशीय बिजली का पारिस्थितिकी पर प्रभाव कम आंका गया है। क्राज ने कहा कि अब हम न केवल यह अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि हर साल कितने पेड़ आकाशीय बिजली से मरते हैं, बल्कि सबसे प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने और वैश्विक कार्बन भंडारण और वन संरचना पर प्रभाव का आकलन करने में भी सक्षम हैं। लेखकों ने पाया कि आकाशीय बिजली हर साल लगभग 32 करोड़ पेड़ों को मारता है, जिससे लगभग 0.25 (गिगाटन कार्बन) मृत जैव द्रव्यमान का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि विभिन्न वन प्रकारों में आकाशीय बिजली के पारिस्थितिकी प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है।

प्रतिदिन सात हजार कदम चलने से कम हो सकता है डिमेंशिया का खतरा

अनुसंधान

द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि प्रतिदिन सात हजार कदम चलने से कुल मिलाकर मृत्यु का जोखिम 47 प्रतिशत, डिमेंशिया का जोखिम 38 प्रतिशत और अवसाद का जोखिम 22 प्रतिशत कम हो सकता है। 2014 से 2025 के बीच प्रकाशित 88 अध्ययनों के डाटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें 1.6 लाख वयस्क शामिल थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह पहला अध्ययन है, जो इस बात का आकलन करता है कि प्रतिदिन चलने वाले कदम कैसे कई स्वास्थ्य स्थितियों को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। पिछले शोध मुख्य रूप से हृदय स्वास्थ्य या समग्र मृत्यु दर पर केंद्रित थे।

इस अध्ययन की टीम में आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन और नार्वे के विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ता शामिल थे। इसमें बताया गया है कि प्रतिदिन 7,000 कदम चलने से कैंसर विकसित होने की संभावना छह प्रतिशत कम हो गई और प्रतिदिन 2,000 कदम चलने की तुलना में हृदय रोग होने की आशंका 25 प्रतिशत, डायबिटीज होने की आशंका 14 प्रतिशत और गिरने की आशंका में 28 प्रतिशत कमी आई। शोधकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रतिदिन 7,000 कदम चलने का लक्ष्य, वर्तमान अनौपचारिक 10,000 कदम प्रतिदिन की तुलना में अधिक यथार्थवादी हो सकता है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि कैंसर व डिमेंशिया जैसी बीमारियों के प्रमाण कम अध्ययनों द्वारा समर्थित हैं, जिसका अर्थ है कि इन परिणामों की निश्चितता का स्तर कम है। टीम ने कहा कि कई अध्ययनों में उम्र व कमजोरी जैसे कारकों को भी ध्यान में नहीं रखा गया। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

फिर एक साथ दिखे तारा सुतारिया व वीर पहाड़िया

चर्चा में तारा व वीर के रिश्ते की खबरें। फाइल

इंटरनेट मीडिया की इस दौर में सितारे भले ही अपने रिलेशनशिप के बारे में स्पष्ट बातें न करें, लेकिन लोग कहीं नहीं से कड़ियां जोड़ ही लेते हैं। इन दिनों ऐसी ही कुछ कड़ियां जुड़ती दिखाई दे रही है फिल्म स्काई फोर्स के अभिनेता वीर पहाड़िया और मरजावां फिल्म की अभिनेत्री तारा सुतारिया के बीच। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच रिलेशनशिप की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी बीच हाल ही में तारा की एक पोस्ट पर सार्वजनिक तौर की हुई इन दोनों की टिप्पणी ने इन खबरों को और हवा दे दी। दरअसल, तारा ने हाल ही में गायक एपी ढिल्लन के साथ अपने आगामी म्यूजिक वीडियो की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की थी। इस पर दिल की इमोजी के साथ टिप्पणी करते हुए वीर ने लिखा, 'मेरी स्टार'। वीर की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए तारा ने भी लिखा कि मेरे और फिर आगे नीली आंख तथा दिल की इमोजी बना दी। मतलब मेरे दिल। फिर लोगों ने इसे तारा और वीर के बीच आ रही रिलेशनशिप की खबरों का पुष्टिकरण भी माना। इसी बीच यह जोड़ी गुरुवार को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ एक ही रंग के कपड़ों में पहुंची। जहां वीर ने आगे बढ़कर तारा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों ने एक साथ पैपराजियों के सामने तस्वीरें और वीडियो भी निकलवाएं। अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है?

स्टेज पर रितेश के रोंगटे खड़े गए थे...

अच्छी फिल्मों के साथ ही अच्छे गाने भी कलाकार के करियर में होना आवश्यक है। अच्छे गानों की पावर क्या होती है, अभिनेता रितेश देशमुख ने जाना था अपने पहले स्टेज शो के दौरान। एक किस्सा साझा करते हुए वह कहते हैं कि मेरी फिल्म मस्ती रिलीज हो चुकी थी। मैं अभिषेक (बच्चन), ऐश्वर्या (राय), प्रिटी जिंटा समेत कई लोगों के साथ अनफार्गेटेबल टूर कर रहा था। तय हुआ था कि सब रोमांटिक गानों पर परफार्म करेंगे। मेरे पास रोमांटिक गाना नहीं था। मैं ज्यादातर कामेडी फिल्में करता था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए दिल दे दिया है... (मस्ती फिल्म का गाना) गाना बजाएंगे। लंदन में मैं स्टेज पर गया और दर्शकों को ओर पीठ करके डांस पोज में खड़ा था। लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दिल दे दिया है... बजा, भीड़ जोर से चिल्लाई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दर्शकों की उस ऊर्जा से मैं उनकी ओर घूमा। नहीं, तो मैंने सोचा था कि जल्दी से डांस करके चला जाऊंगा और अभिषेक-ऐश्वर्या आकर स्टेज संभालेंगे। लेकिन भीड़ ने जो प्रतिक्रिया उस गाने पर दी, मुझे उस गाने की पावर समझ में आई। फिलहाल रितेश इन दिनों अपने निर्देशित फिल्म राजा शिवाजी का काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि मुझ पर जिम्मेदारी है कि सब सही से हो जाए। मराठी और हिंदी में फिल्म बना रहे हैं। फिर इसे दूसरी भाषाओं में भी डब करेंगे।

अभिनय के साथ ही निर्देशन भी करते हैं रितेश। फाइल

... इसलिए रोमियो रखा गया शाहिद कपूर की फिल्म का नाम

इस साल के शुरुआत में जब खबरें आई कि अभिनेता शाहिद कपूर ने फिल्मकार विशाल भारद्वाज के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। तब इस फिल्म के नाम को लेकर काफी कयास लगाए गए, कुछ रिपोर्ट्स में इस फिल्म का नाम अर्जुन उस्तरा भी बताया गया और कुछ कुछ में एविल। अब खबरें हैं कि विशाल और शाहिद ने इस फिल्म के लिए रोमियो शीर्षक तय किया है।

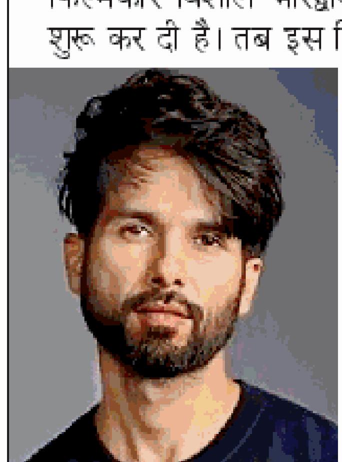

चौथी बार विशाल संग काम कर रहे हैं शाहिद। फाइल

सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में शाहिद गैंगस्टर की भूमिका निभाएंगे, जो पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा निभाई भूमिकाओं से बिल्कुल अलग होगा। फिल्म के शीर्षक को लेकर शाहिद और विशाल ने फिल्म की टीम के साथ मिलकर काफी सोच विचार किया। उसके बाद रोमियो शीर्षक तय किया गया, क्योंकि यह शीर्षक शाहिद के पात्र को रंगीन मिजाज दर्शाता है। फिल्म में अभिनेत्री तृप्ति डिमरी मुख्य नायिका की भूमिका में हैं, जबकि अभिनेत्री दिशा पाटनी पर फिल्माया एक डांस नंबर भी है। फिल्म की शूटिंग लगभग अंतिम चरणों में है। कोरोना काल के बाद से शाहिद की अभी तक एक हिट फिल्म की तलाश जारी है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म से उन्हें यह तलाश पूरी होने की उम्मीदें हैं।

सैयारा की लहर की बीच बोले डब्बू मलिक, मोहित के साथ बनाना चाहूंगा बायोपिक

फिल्मकार मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म सैयारा ने इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रखा है। इस बीच संगीतकार डब्बू मलिक ने उनसे अपनी बायोपिक का निर्देशन करने की भी इच्छा जताई। दरअसल, गुरुवार को डब्बू की बायोग्राफी किताब नेवर टू लेट लांच की गई। इस मौके पर डब्बू के दोनों बेटे संगीतकार अमाल मलिक तथा अरमान मलिक भी पिता के साथ नजर आएं। ऐसे में जब डब्बू से पूछा गया कि अगर इस किताब पर फिल्म या शो बनती है, तो वह अपनी भूमिका में कौन से अभिनेता को देखते हैं? इस पर डब्बू में अपने परिवार में ही पूरी फिल्म की संकल्पना तैयार कर दी।

बेटो अरमान और अमाल के साथ डब्बू मलिक। फाइल

उन्होंने कहा, 'अमाल, डब्बू मलिक की भूमिका निभाएंगे। मैं सरदार मलिक (संगीतकार तथा डब्बू के पिता) की भूमिका निभाऊंगा। अरमान फिल्म में उनकी स्वयं की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का संगीत अमाल तैयार करेंगे और मेरी सिर्फ यही शर्त होगी कि इसका निर्देशन मोहित सूरी से कराया जाए। इसके पीछे कुछ कहानी भी है, कुछ साल पहले मोहित के साथ मेरी इस बारे में चर्चा भी हुई थी। वह हमारे परिवार की कहानी पर कुछ बनाना चाहते थे। इसलिए वह हमारी कहानी के सबसे करीब हैं।' बता दें कि यहां अपने पिता के साथ अमाल और अरमान दोनों का साथ आना चर्चा का विषय रहा। क्योंकि गत मार्च में अमाल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में डिप्रेशन से अपनी लड़ाई और परिवार के साथ तनावपूर्ण संबंधों की बात कही थी। जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया था

सात सवाल

मैं हमेशा से अपने पिता की तरह ही बनना चाहता था

@therealprithvi

इस साल रिलीज फिल्म एल 2: एम्पुरान में अभिनय व निर्देशन करने के बाद पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म सरजमीं में सैन्यकर्मी की भूमिका में नजर आएंगे। पिता-पुत्र के मतभेद पर आधारित फिल्म में उनके साथ अभिनेता इब्राहिम अली खान भी हैं। पृथ्वीराज ने फिल्म, पिता संग जुड़ाव, एक्शन सीन के दौरान सुरक्षा जैसे पहलुओं पर बात की...

● **आपको स्क्रिप्ट में क्या अच्छा लगा था?**

-मुझे इस स्क्रिप्ट में पिता-पुत्र का संबंध ही सबसे पहले पसंद आया था। यह मानवीय कहानी है। हां, इसे कश्मीर की पृष्ठभूमि में सेट किया गया है। इसमें सेना, देशभक्ति, विद्रोह जैसे पहलू हैं, लेकिन यह मूल रूप से मानवीय कहानी है, जो फिल्म के तीन प्रमुख किरदारों के बीच गढ़ी गई है।

● **आपके पिता भी मलयालम फिल्मों के अभिनेता थे। उनका कैसा प्रभाव रहा?**

-जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो पिता को आदर्श मानते हैं। मैं भी पिता को आदर्श मानता था। वह मेरे पहले व सबसे बड़े हीरो थे। फिल्म में काजोल का संवाद है कि मां चाहे कितना भी प्यार करें, लेकिन बेटे को बाप की तरह बनना होता है। मैं पिता की तरह बनना चाहता था।

● **सरजमीं की शूटिंग कश्मीर में हुई थी?**

-इस फिल्म का अधिकतम हिस्सा हमने मनाली में शूट किया है, क्योंकि जिस तरह के सीक्वेंस को हम शूट करना चाहते थे, उसे कश्मीर में शूट कर पाना आसान नहीं था। मेरी फिल्म पिकेट 43 (मलयालम) फिल्म को कश्मीर में शूट किया गया था। हालांकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद मैं कश्मीर नहीं गया हूं, लेकिन मुझे वहां जाना है।

● **फिल्म में काफी एक्शन भी किया है। हाल में तमिलनाडु में निर्देशक पी रंजीत के फिल्म सेट से स्टंटमैन एसएम राजू के निधन की खबर आई...**

-मेरे ख्याल से सबसे कठिन एक्शन वो होगा, जिसमें निर्देशक और एक्शन कोरियोग्राफर को आइडिया नहीं होगा कि वह क्या चाहते हैं। हमारे एक्शन कोरियोग्राफी सुनील राड्रिक्स स्पष्ट थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बाकी राजू ने मेरे साथ कई फिल्मों में काम किया था। यह दुखद घटना थी। मेरे निर्देशन में बनी फिल्म के कई दृश्य राजू के बिना संभव नहीं हो सकते थे। एक्शन शूटिंग के दौरान कभी भी सौ प्रतिशत सुरक्षा नहीं हो सकती। रिस्क बना रहता है। इसमें दो राय नहीं कि सेट पर सुरक्षा के तरीके बेहतर व एडवांस हुए हैं। दो साल पहले जब शूटिंग कर रहे थे, तब मुझे चोट लगी थी और घुटने की सर्जरी करानी पड़ी थी।

● **इब्राहिम अली खान को उनकी फिल्म नदानियां के लिए काफी ट्रोल किया गया था। क्या कलाकारों पर निशाना साधना आसान होता है?**

-आलोचना की बात करें तो सिनेमा बतौर इंडस्ट्री साफ्ट टारगेट है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा आलोचना इसलिए होती है, क्योंकि आपको प्यार भी बहुत सारा मिलता है। हम दर्शकों से मिलने वाली मान्यता पर भरोसा करते हैं। सरजमीं देखने के बाद लोग यही कहेंगे कि इब्राहिम बेहतरीन कलाकार हैं लेकिन यहां से आलोचनाएं खत्म नहीं हो जाएंगी। ममूटी सर और मोहनलाल सर की अभी भी आलोचना होती है। इब्राहिम और मेरी भी आलोचना हो सकती है। अहम यह कि हम प्रक्रिया का आनंद लें। परिणाम की चिंता न करें।

● **इस फिल्म से कुछ सीख भी मिली?**

-पिछले करीब 25 साल से सिनेमा करने के बाद लगता है कि सिनेमा जो सीख देती है वो ऐसे होती है जिसका आपको अहसास नहीं होता। मुझे लगता है जिंदगी सबसे बेहतरीन शिक्षक है। वह जब सबक देती है तो बताती नहीं।

● **एम्पुरान के अगले हिस्से की क्या तैयारी है**

-उसकी तैयारी चल रही है। फिलहाल फिल्म के लेखन पर काम चल रहा है।

(स्मिता श्रीवास्तव)

ड्रीम गर्ल 3 का आफर आएगा तो जरूर करूंगी

ऐसा कई बार होता है कि फ्रेंचाइज फिल्मों में हीरो वही होते हैं, जो मूल फिल्म में होते हैं लेकिन ज्यादातर अभिनेत्रियां बदल दी जाती हैं। अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल 2 में न होने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस फिल्म की फ्रेंचाइज में न होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, 'मुझे मीडिया के जरिये इसके बारे में पता चला था कि मैं उस फिल्म में नहीं हूं। मुझे खुशी है कि दो साल बाद भी इसके बारे में बात हो रही है। लोगों ने उस समय यह नोटिस ही नही किया कि यह गलत हुआ, तो उस पर क्या कहूं। दो साल हो गए हैं। फिल्म आकर चली भी गई। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूं। सोलो लीड फिल्में कर रही हूं। मेरा फोकस उस पर है। तब किसी से सवाल नहीं पूछा, आज भी नहीं पूछना है।' अगर ड्रीम गर्ल 3 का आफर उनके पास आता है, तो वो क्या करेंगी? इस पर उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि जरूर करूंगी।

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

@nushrrattbharuccha

****